आम बजट 2026-27

दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com

भोपाल, सोमवार 02 फरवरी, 2026 ▸ फाल्गुन कृष्ण पक्ष 01, विक्रम संवत 2082 ▸ वर्ष 69 ▸ अंक 125 ▸ पृष्ठ 12 ▸ महानगर ▸ मूल्य 5 रुपए

विकास का रोड मैप

छोटे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे 12.2 लाख करोड़ 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

नई दिल्ली, जेएनएन।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 का आम बजट ऐसे समय में पेश किया है, जब अग्रिम अनुमानों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है जबकि 2024-25 में बढ़त 6.5 फीसदी थी। जीडीपी में इस ऊंची बढ़त के साथ ही मुद्रास्फीति काफी नरम है और राजकोषीय मजबूती भी बनी हुई है। इस मजबूत आर्थिक बुनियाद पर वित्त मंत्री ने विकास का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए छोटे शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जबकि 7 नए रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखते हुए अगले दशके आद्यौगिक विकास की नींव भी रख दी है।

बहरहाल, बाहरी मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई हैं जिसका उल्लेख वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही किया। सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कई अन्य चीजों के अलावा वित्त मंत्री ने एक उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति' के गठन की बात की है जो सेवा क्षेत्र पर जोर देते हुए उपायों के बारे में ऐसी सिफारिशें देगी जिससे साल 2047 तक वैश्विक स्तर पर 10 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करते हुए भारत सेवा क्षेत्र में अग्रणी बन सके।

वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, वित्त मंत्री ने छह मुख्य क्षेत्रों में उपायों की घोषणा की। इनमें सात रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना, विरासत वाले औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना, चैंपियन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम बनाना, अवसंरचना निर्माण को लगातार बढ़ावा देना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं। बजट भाषण में उन 350 से ज्यादा सुधारों को रेखांकित किया गया, जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2025 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी किया गया था। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को मान लिया है कि राज्यों के लिए दी जाने वाली राशि को 41 फीसदी पर बनाए रखा जाए। केंद्र सरकार ने 2026-27 में राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के तौर पर 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राजकोषीय मोर्चे पर, सरकार का अनुमान है कि वह चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4 फीसदी रखने के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।

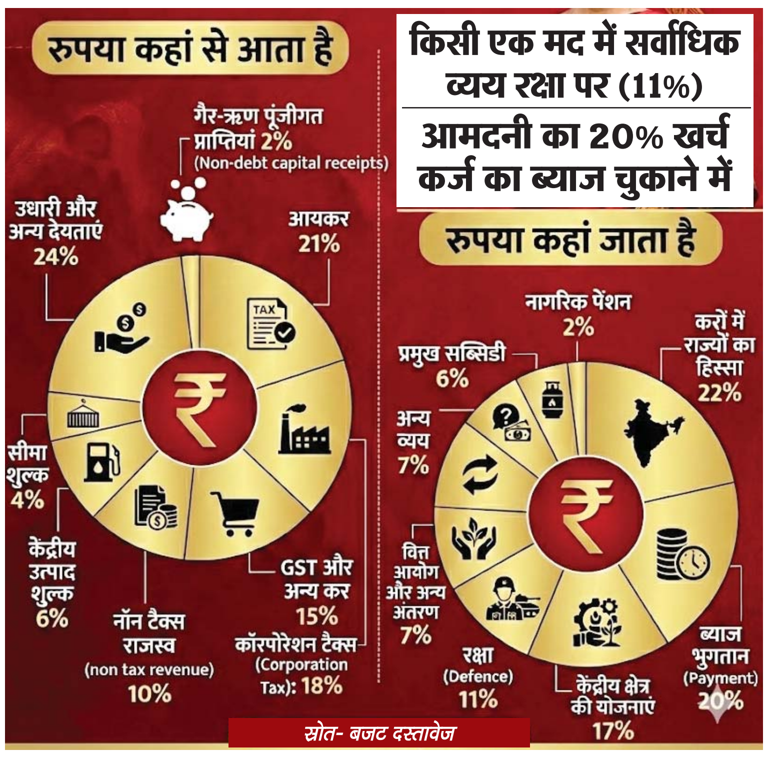

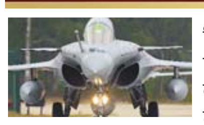

रक्षा पर बड़ा फोकस

वित्त मंत्री ने वैश्विक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करते हुए रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। इसमें से 2.19 लाख करोड़ सेना के आधुनिकीकरण के लिए रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष के 1.80 लाख करोड़ से 15 फीसदी से अधिक है। यह बढ़ोतरी भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत करेगी और घरेलू रक्षा उद्योग को भी गति देगी। 63,733 करोड़ रुपए विमान और एयरो इंजन के लिए आवंटित किये गये हैं। 25023 करोड़ रुपए नौ सेना के बेड़ों को दिये जाने का प्रस्ताव है।

कैंसर की 17 दवाइयां सस्ती, 3 एम्स खुलेंगे

- कैंसर की 17 एडवांस दवाओं पर लगने वाली 5 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री होंगी।
- करदाताओं को राहत की उम्मीद थी, लेकिन टैक्स स्लैब जस का तस रखा गया। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। पहले यह 31 दिसंबर तक थी।
- तीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एम्स मॉडल पर) खोलने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे।
- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ खर्च होंगे। प्रमुख आर्थिक व शहरी केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी होंगे।
- एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर 15 हजार कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। 789 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

53.5 लाख करोड़ का बजट: पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है । 2026 में यह 11.2 लाख करोड़ रुपये था। यानी 9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।

शुद्ध कर प्राप्तियां 28.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।

राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत (जीडीपी का) तक रखने का लक्ष्य।

बिना कर्ज की आमदनी: 36.5 लाख करोड़ रुपये।

शुद्ध टैक्स बचत: 28.7 लाख करोड़ रुपये।

यह बजट भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। यह असीम संभावनाओं का हाईवे है। यह वर्तमान के सपनों को साकार करता है और 2047 तक विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की ठोस नींव रखता है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और विकसित भारत की ओर एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

■ **नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

मोदी सरकार के पास नए आइडिया खत्म हो चुके हैं। बजट में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों का कोई ठोस समाधान नहीं है। किसान अब भी आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षित युवाओं के बीच फैली बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई को काबू करने प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज के दौर से भी आगे निकल गई है। बजट में एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किसी विशेष समर्थन का जिक्र तक नहीं है।

■ **मल्लिकार्जुन खरगे**, अध्यक्ष, कांग्रेस

क्या सस्ता और क्या महंगा?

बजट में कई सामान सस्ता-महंगा होने का ऐलान किया गया है। सोलर से जुड़े सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जूते, मोबाइल बैट्री, ओवन भी सस्ता होगा।

- 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी।
- कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी।
- शुगर की दवाई सस्ती होगीं
- विदेश यात्रा पहले से सस्ती होगीं।
- सीएनजी और बायोगैस भी सस्ती

स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते

सरकार ने बजट में मेक-इन-इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफै. रिंग से जुड़े कई अहम एलान किए हैं। इसके चलते भारत में तैयार होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है।

वहीं भारतीय फैक्ट्रियों में बने स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और घरेलू मैन्युफै. रिंग मजबूत होने से उपभोक्ताओं को ज्यादा किफायती डिवाइस मिल सकेंगे।

शराब, स्क्रैप और खनिज महंगा

शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, विदेशी परफ्यूम, लग्जरी घड़ियां, आयातित कारें सहित अन्य वस्तुएं भी महंगी होंगी।

आयकर स्लैब में बदलाव नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 मार्च तक भरे जा सकेंगे

बजट में इनकम टैक्स को लेकर को कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। वहीं, विदेश रुपए भेजने पर अब 5 फीसदी के बदले 2 फीसदी टैक्स लगेगा।

टैक्स को लेकर 6 बदलाव

1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून: पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने करने की प्रोसेस आसान बनाई जाएगी।

विदेश रुपए भेजने पर कम टैक्स: पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब कम टीसीएस लगेगा। सरकार ने इसे 5 से 2 फीसदी करने का फैसला किया है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5 फीसदी और 20 फीसदी के टीसीएस रेट को घटाकर 2 फीसदी किया गया है।

टीडीएस न कटवाने एप्लिकेशन की जरूरत नहीं: टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) नहीं कटवाने के लिए एप्लिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अब आयकर नहीं बनता है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी फॉर्म 15जी (60 साल से कम)या फॉर्म 15 एच (वरिष्ठ नागरिक) जमा करना होता था।

31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न: आईटीआर में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा: फ्यूचर ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया है। ऑप्शंस पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15 फीसदी किया गया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स: अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। यानी सिर्फ उन्हीं निवेशको टैक्स-फ्री होने का फायदा मिलेगा, जिन्होंने एसजीबी से बॉन्ड खरीदे और उसे पूरी अवधि तक रखा। पहले एसजीबी पर ब्याज के अलावा जो फायदा होता था, वह मैच्योरिटी (8 साल) पर टैक्स-फ्री होता था, चाहे बॉन्ड आरबीआई से खरीदा हो या बाद में सेकेंडरी बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) से लिए हों।

पुरानी रिजीम में छूट 2.5 लाख तक पर

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

बदलाव क्यों नहीं हुआ

टैक्स एक्सपर्ट आनंद जैन के अनुसार सरकार ने पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को 7 लाख बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे में इस साल बदलाव होने की संभावना न के बराबर ही थी।

रील बनाना सिखाएंगे 15 हजार स्कूल

बजट 2026 में युवाओं, महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। आने वाले वर्षों में गेमिंग सेक्टर के जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। युवाओं को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि क्रिएटर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई के सहयोग से देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये लैब्स शुरू होंगी।

बनेंगी पांच नई एजुकेशन टाउनशिप

युवाओं को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखते हुए बजट में पांच नई टाउनशिप विकसित करने की भी घोषणा की गई है, जहां शिक्षा के साथ-साथ कंपनियों में काम का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। इसे 'कॉर्पोरेट मित्र' मॉडल के तौर पर पेश किया गया है।

गेम्स और टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा

गेमिंग, टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया जाएगा, जिससे नए स्टार्टअप्स को लोन मिल सकेगा और बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल्स की भर्ती होगी। उच्च शिक्षा, रिसर्च के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा दांव खेला है।

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी

पर्यटन और सेवा क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी, जो छात्रों को सर्विस इंडस्ट्री के लिए तैयार करेगा। देश के 20 बड़े पर्यटन स्थलों पर 12 हफ्तों के हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स चलाए जाएंगे।

स्टेम को प्रोत्साहित करने विशेष फंड बनाया जाएगा

स्टेम यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी बजट में बुनियादी ढांचे और सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन देने की बात कही गई है। वहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए विशेष आयुर्वेदिक देखभाल केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी इस बजट का हिस्सा है।

बाजार को नहीं भाया बजट | सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद, निफ्टी भी 495 अंक टूटा

शेयर बाजार में हाहाकार, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे

नई दिल्ली, जेएनएन।

बजट के बाद 1 फरवरी (रविवार) को शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1546 अंक यानी करीब 2 फीसदी गिरकर 80,722 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 अंक टूटा, ये 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी किया। ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15 फीसदी किया है। इस वजह से ही बाजार में यह गिरावट आई। बीते सात साल में बजट के दिन की यह सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 2020-21 बजट के दिन सेंसेक्स 987 अंक और निफ्टी 300 अंक गिरकर बंद हुआ था।

लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ घटा

तेज बिकवाली के बीच बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 11 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी रही। बीईएल, एसबीआई और अडाणी पोर्ट्स के शेयर में 6 फीसदी तक की गिरावट रही। सरकारी बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा 6 फीसदी की गिरावट हुई।

ऐसी रही बाजार की चाल

- बजट भाषण के बाद सेंसेक्स 2,370 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर 79,899 पर आ गया। निफ्टी भी 750 अंक गिरकर 24,571 के निचले स्तर पर आ गया था।
- बजट भाषण के दौरान सेंसेक्स 1,600 अंक यानी 2 फीसदी गिरकर 80,600 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी करीब 550 अंक गिरकर 24,800 के स्तर पर आ गया।
- बजट से पहले सुबह 9.15 बजे सेंसेक्स 100 अंक की गिरावट के साथ 82,156 के स्तर पर खुला। निफ्टी 50 अंक गिरकर 25,275 के स्तर पर ओपन हुआ था।

फ्यूचर्स पर एसटीटी बढ़ाया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फ्यूचर्स पर लगने वाले एसटीटी को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया गया है।

एसटीटी क्या है?

एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जो शेयर बाजार में हर खरीद-बिक्री पर लगता है। यह टैक्स तब भी देना पड़ता है, जब घाटा हो रहा हो। यह सीधे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कटता है और स्टॉक एक्सचेंज इसे सरकार के पास जमा कर देता है। टैक्स दरें बढ़ने से अब एक ही ट्रांजैक्शन के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

बजट विशेष

पेज-2

पेज-10

पेज-11

सेमीकंडक्टर से बायोफार्मा तक भारत के मैन्युफैक्चरिंग-इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट

अगले दशक के औद्योगिक विकास की रूपरेखा

नई दिल्ली, जेएनएन। अगर वर्ष 2025 का बजट टैक्स राहत और खपत को सहारा देने की कोशिश था, तो बजट 2026-27 को साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के 'डबल डाउन' के रूप में देखा जा रहा है। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को अगले दशक के लिए तैयार करने की एक औद्योगिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सरकार ने अपने आर्थिक विजन को तीन 'कर्तव्यों' में बांधा है। इनमें पहला उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और लचीलापन बढ़ाकर तेज और टिकाऊ आर्थिक विकास करना कर्तव्य है। यहीं से बजट 2026 का असली फोकस शुरू होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का इंजन माना गया है। बजट साफ करता है कि सरकार अब लो-एंड मैन्युफैक्चरिंग से हटकर, हाई-वैल्यू, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन उत्पादन पर फोकस कर रही है। यह औद्योगिक नीति सिर्फ सब्सिडी नहीं, बल्कि इकोसिस्टम निर्माण की कोशिश है।

रणनीतिक सेक्टरः जहां भारत को वैश्विक लीडर बनाने की तैयारी

बजट 2026 ने साफ किया है कि भारत 'सब कुछ बनाने' की नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षेत्रों में वैश्विक बढ़त हासिल करने की नीति पर चलना चाहता है। इसके लिए सात फ्रंटियर सेक्टर चिन्हित किए गए हैं।

सेमीकंडक्टरः असेंबली से 'मेड-इन-इंडिया चिप' तक

सेमीकंडक्टर अब महज टेक्नोलॉजी नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक संप्रभुता का सवाल हैं। आईएसएम 1.0 जहां चिप असेंबली तक सीमित था, वहीं आईएसएम 2.0 भारत को पूरी वैल्यू चेन में लाने की कोशिश है। यह संकेत है कि भारत अब 'बैक-एंड प्लेयर' नहीं रहना चाहता।

आईएसएम 2.0 के लक्ष्य
- चिप-मेकिंग मशीनरी और मटीरियल का उत्पादन
- फुल-स्टैक इंडियन आईपी का विकास
- सप्लाई-चेन की मजबूती
- इंडस्ट्री-लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्सः सफल स्कीम पर बड़ा दांव

अप्रैल 2025 में शुरू हुई इलेक्ट्रिनिक्स कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम उम्मीद से ज्यादा सफल रही। 22,919 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले दोगुने निवेश प्रस्ताव आए। यह दिखाता है कि सरकार पॉलिसी सक्सेस को स्केल-अप करने के मूड में है।

40,000 करोड़ रुपए आउटले बढ़ाया गया बजट 2026 में

रेयर अर्थ मैग्नेट्सः खनिज से मैन्युफैक्चरिंग तक

ईवी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी के लिए रेयर अर्थ अनिवार्य हैं। बजट ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। इन कॉरिडोर में खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च, फिनिश्ड मैन्युफैक्चरिंग एकीकृत रूप से विकसित की जाएगी।

ग्रीन और सस्टेनेबल फ्रेट मूवमेंट

- डानकुनी-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
- वाराणसी और पटना में शिप-रिपेयर इकोसिस्टम
- कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम
- 2047 तक वाटर/कोस्टल शिपिंग शेयर 6 फीसदी से 12 फीसदी

ऊर्जा सुरक्षाः सीसीयूज पर 20,000 करोड़

बढ़ती मैन्युफै. रिंग के साथ कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। यह बताता है कि विकास की कीमत पर्यावरण से नहीं चुकाई जाएगी।

20,000 करोड़ रुपए का बजट

सीसीयूएस टेक्नोलॉजी

बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर

सी-प्लेन और कनेक्टिविटी

- सी-प्लेन मैन्युफै. रिंग का स्वदेशीकरण
- वीजीएफ स्कीम
- पर्यटन के लिए रिमोट कनेक्टिविटी

रीफॉर्म एक्सप्रेस और फाइनेंशियल सेक्टर

- कॉरपोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा
- क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में तर्कसंगतता
- साथ ही बैंकिंग फॉर विकसित भारत पर हाई-लेवल कमेटी
- 350+ सुधार
- जीएसटी सरलीकरण
- लेबर कोड्स

केमिकल पार्कः आयात निर्भरता घटाने की कोशिश

केमिकल सेक्टर अब भी आयात पर निर्भर है। इसे बदलने के लिए तीन समर्पित केमिकल पार्क, क्लस्टर-आधारित, प्लग-एंड-प्ले मॉडल, प्रतियोगी चयन प्रक्रिया की योजना है। यह मैन्युफैक्चरिंग राज्यों के लिए बड़ा अवसर है।

कैपिटल गुड्सः मशीनें भी अब देश में बनेंगी

मजबूत मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें भी देश में बननी चाहिए। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग मसल मजबूत करने की रणनीति है।

बजट के तीन कदम
- हाई टेक टूल रूम्स (सीपीएसई द्वारा)
- कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम
- 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग मिशन

टेक्सटाइल सेक्टरः रोजगार और आधुनिकता का मिश्रण

टेक्सटाइल भारत का सबसे बड़ा रोजगारदाता सेक्टर है। बजट ने इसके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रखा है। साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क और खादी-ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव है।

- नेशनल फाइबर स्कीम
- टेक्सटाइल एक्सपैंशन और एम्प्लॉयमेंट
- नेशनल हैंडलूम-हस्तशिल्प प्रोग्राम
- टेक्स-इको (सस्टेनेबल टेक्सटाइल)
- समर्थ 2.0 (स्किल डेवलपमेंट)

इंफ्रास्ट्रक्चरः 12.2 लाख करोड़ का निरंतर पुश

यह महज आंकड़ा नहीं, बल्कि दशक-भर की रणनीति का नतीजा है।

02 लाख करोड़ रुपए था 2014-15 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय

12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है 2026-27 के बजट में यह

इसके अलावा नए फाइनेंसिंग टूल्स जैसे इनविट्स, रीइट्स, एनआईआईएफ, नाबफिड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के जरिये प्राइवेट निवेश का जोखिम घटाने की कोशिश की है।

रक्षा पर बड़ा दांवः 7.85 लाख करोड़ का आवंटन

2.19 लाख करोड़ आधुनिकीकरण के लिए

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय बजट में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखते हुए रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह पिछले वित्त वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बजट के इस फैसले को हालिया सुरक्षा हालात और 'ऑपरेशन सिंदूर' की पृष्ठभूमि में सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करने के स्पष्ट संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय का कुल आवंटन 7,84,678 करोड़ रुपये है। इसमें 2,19,306 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जबकि 5,53,668 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए हैं। राजस्व व्यय में 1,71,338 करोड़ रुपये रक्षा पेंशन के लिए शामिल हैं।

63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए

25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़ा पर

पूंजीगत व्यय में बड़ी छलांग

रक्षा बजट का सबसे अहम पहलू पूंजीगत व्यय में तेज बढ़ोतरी है। बीते साल कैपिटल आउटले का बजट अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान में 1.86 लाख करोड़ रुपये किया गया। इसके मुकाबले 2026-27 में इसे बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी करीब 21.84 प्रतिशत की वृद्धि। इस राशि का बड़ा हिस्सा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होगा। इसके अलावा, वायुसेना, थलसेना और नौसेना के लिए हथियार प्रणालियों, आधुनिक संचार उपकरणों, मिसाइल सिस्टम और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।

बड़े रक्षा सौदे और भविष्य की तैयारी

रक्षा मंत्रालय के पास आने वाले सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इनमें राफेल लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त अनुबंध, पनडुब्बियां, और मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ा हुआ पूंजीगत आवंटन इन परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

राजस्व व्यय और पेंशन

3,65,478.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं रक्षा सेवाओं के लिए जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.24 प्रतिशत अधिक हैं।

1,71,338 करोड़ रुपये का प्रावधान है पेंशन मद में

रक्षा एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा

- नागरिक, प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट।
- रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी माफ।

राज्यों को 1.4 लाख करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव

2026-27 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन दिया जाएगा। नेट टैक्स रसीदें 28.7 लाख करोड़ अनुमानित हैं। 2026-27 से आगे की राजकोषीय नीति का लक्ष्य ऐसा घाटा बनाए रखना है, जिससे केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के अनुपात में घटता जाए। 2024 में सामान्य सरकारी कर्ज जीडीपी का करीब 85 फीसदी था, जिसमें केंद्र का हिस्सा 57 फीसदी रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए 3-4 फीसदी का वित्तीय घाटा टिकाऊ माना जाता है।

20,000 करोड़ कार्बन कैप्चर पर

जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देते हुए सरकार ने कार्बन कैप्चर तकनीकों के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है, ताकि परियोजनाओं का स्केल-अप और तकनीकी तैयारियों में तेजी लाई जा सके। बजट में वित्तीय स्थिरता के साथ नवाचार व हरित तकनीक पर केंद्रित विकास रणनीति पेश की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, खनिज और टैक्स में बड़े ऐलान

आयात घटाने के लिए बनेंगे 3 केमिकल पार्क

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। क्लस्टर-आधारित प्लग-एंड-प्ले मॉडल के तहत राज्यों में तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए नई योजना लाई जाएगी, जिससे औद्योगिक सप्लाई चेन मजबूत होगी और बाहरी जोखिम कम होंगे।

प्रमुख घोषणाएं

रेयर अर्थ कॉरिडोरः ओडिशा, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु में खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और निर्माण समर्पित कॉरिडोर विकसित होंगे।

खनन को बढ़ावाः रणनीतिक खनिज क्षेत्रों में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्माण को प्रोत्साहन देने के उपाय।

केमिकल पार्कः चुनौती मार्ग (चैलेंज रूट) के जरिए तीन समर्पित केमिकल पार्क, जिससे आयात निर्भरता घटेगी।

एमएटी टैक्स

बायबैक टैक्सः सभी शेयरधारकों के लिए बायबैक से प्राप्त आय को कैपिटल गेन के रूप में कर योग्य किया जाएगा।

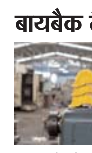

एसटीटी बढ़ोतरीः कमोडिटी फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी।

एमएटी में कटौतीः मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को अंतिम कर माना जाएगा; दर 15 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी।

खेल सामग्री क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपए मिले

खेलो इंडिया को फिर सबसे ज्यादा आवंटन

नई दिल्ली, जेएनएन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई, जिसमें खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि उसको पहली बार 500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.88 करोड़ रुपए है, जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपए से 1133.34 करोड़ रुपए अधिक है। राष्ट्रीय शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के लिए आवंटित राशि को 880 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपए कर दिया गया है। देशभर के स्टेडियमों के रखरखाव और उनके उपयोग की जिम्मेदारी भी साई की होती है। हालांकि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और राष्ट्रीय डोपिंग-विरोधी एजेंसी का बजट क्रमशः 28.55 करोड़ रुपए से घटाकर 23 करोड़ रुपए और 24.30 करोड़ रुपए से घटाकर 20.30 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव

प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने के प्रस्ताव रखा, जिससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। यह मिशन आपस में जुड़े विभिन्न माध्यमों से एकीकृत प्रतिभा विकास कार्यक्रम को सुगम बनाएगा। खेलो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के लिए आवंटित बजट भी 78.64 करोड़ से घटाकर 46.98 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान राशि को तीन करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दिया गया है।

एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा पैकेज

10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय बजट में सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उनके लिए अब तक के सबसे समग्र और बहुस्तरीय समर्थन पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उच्च-क्षमता वाले एमएसएमई को 'भविष्य के इंडस्ट्री चैंपियन' के रूप में विकसित करना है।

सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है, सप्लाई चेन में उतार-चढ़ाव है और घरेलू स्तर पर रोजगार सृजन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एमएसएमई सेक्टर पर ही टिकी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं, जो जीडीपी में लगभग 30 फीसदी योगदान, निर्यात में करीब 45 फीसदी हिस्सेदारी और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।

6.3 करोड़ एमएसएमई हैं देश में

30% योगदान देते हैं एमएसएमई जीडीपी में

45% हिस्सेदारी है निर्यात में

11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है एमएसएमई सेक्टर

'चैंपियन' बनाने की तीन-स्तरीय रणनीति 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड

बजट का सबसे बड़ा ऐलान है 10,000 करोड़ का एमएमई ग्रोथ फंड। यह फंड उन एमएसएमई को इक्विटी सपोर्ट देगा, जिनमें तेजी से विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता है।

- अब तक एमएसएमई को बैंक कर्ज तो मिलता रहा है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग की भारी कमी रही है। इस फंड का उद्देश्य है कि अच्छी कंपनियां महज कर्ज पर निर्भर न रहें, बल्कि पूंजी के जरिए अपने कारोबार को स्केल कर सकें।
- इसके अलावा, 2021 में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए का टॉप-अप किया जाएगा। यह फंड खासकर माइक्रो एंटरप्राइज को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराता है। जिन्हें वेंचर कैपिटल या इक्विटी नहीं मिल पाती।
- यह पहल एमएसएमई को 'छोटा बने रहने' की मजबूरी से बाहर निकालकर मिड-साइज या लार्ज में बदलने में मदद कर सकती है।

लिक्विडिटी संकट पर वारः टीआरईडीएस को मेनस्ट्रीम बनाना

- एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या महज पूंजी की कमी नहीं, बल्कि समय पर भुगतान न मिलना भी है। बड़े कॉरपोरेट और सरकारी संस्थानों से भुगतान में देरी के कारण नकदी फंस जाती है।
- इसी को देखते हुए बजट में ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) को मजबूत करने के लिए चार अहम कदम उठाए गए हैं। अब तक टीआरईडीएस के जरिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एमएसएमई को मिल चुकी है।
- **सीपीएसई के लिए टीआरईडीएस अनिवार्यः** सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदारी के भुगतान टीआरईडीएस के जरिए करने होंगे। इससे निजी कंपनियों पर भी दबाव बनेगा।
- **सीजीटीएमएसई के तहत क्रेडिट गारंटीः** टीआरईडीएस पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए गारंटी व्यवस्था, जिससे बैंकों का जोखिम घटेगा और एमएसएमई को सस्ता फंड मिलेगा।

वर्ष 69 अंक 125 पृष्ठ 12
भोपाल, सोमवार 02 फरवरी, 2026
फाग्गुन कृष्ण पक्ष 01, विक्रम संवत् 2082
महानगर मूल्य 5 रुपए

दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com

सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है..।
-अब्दुल कलाम

ऑफ बीट

विजय की दुल्हन बनेंगी मंदाना

रश्मिका मंदाना व विजय देवरकोंडा बीते कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लव बर्ड्स रश्मिका और विजय इसी महीने सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाएंगे। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों की वेडिंग डेट और वेन्यू को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि रश्मिका और विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। यूजर का ये भी कहना है कि दोनों की शादी उदयपुर के सिटी पैलेस में शाही अंदाज में होगी। वेन्यू पर चल रही सजावट की झलक भी वीडियो में दिखाई गई है। यूजर ने रश्मिका और विजय की शादी को लेकर दावा करते हुए कहा-हम अभी उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं। बहुत तगड़ा डेकोर चल रहा है, हमें पता चला है कि यहां पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो रही है। 2 फरवरी को दोनों शादी कर रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप: पाक ने भारत के साथ खेलने से किया मना

बांग्लादेश के समर्थन में 15 को होने वाले लीग मैच से किया किनारा

इस्लामाबाद, जेएनएन। टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक-दूसरे से भिड़ने वाली थीं। हालांकि, अब तक यह तय नहीं है अगर नॉकआउट में भारत सामने आया तो पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं? आईसीसी ने 24 जनवरी को बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में एंट्री दी थी। आईसीसी के इस फैसले के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है।

पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला आईसीसी के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया। बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

भारत की सुपर-8 की राह होगी आसान

भारत-पाक टीमें वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में है। चारों ग्रुप में 5-5 टीमें हैं,जिनमें से 2-2 टीमें सुपर-8 स्टेज में जाएंगी। पाक के बायकॉट का मतलब यह होगा कि इस मैच के 2 पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे और भारत के सुपर-8 में पहुंचने की राह काफी आसान हो जाएगी। आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक बॉयकॉट से पाक का रन रेट भी खराब होगा। वहीं भारत का रन रेट बेहतर होगा। 16.10.7 क्लॉज में बताया है कि पाक के 20 ओवर में 0 रन होंगे, जबकि भारत का एक भी ओवर काउंट नहीं होगा। इससे पाक का रन रेट निगेटिव में भी जा सकता है। ग्रुप-ए में भारत-पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका की टीमें हैं। पाकिस्तान बाकी मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर इस स्थिति में भी सुपर-8 में पहुंच सकती है।

आईसीसी बोला-पाक फैसले पर विचार करे

टी-20 आईसीसी ने देर रात 11 बजे मीडिया रिलीज में कहा, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी सरकार के फैसलों का समर्थन करता है, लेकिन पाकिस्तान का फैसला दुनियाभर में क्रिकेट के इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाला है। आईसीसी उम्मीद कर रहा है कि पीसीबी फैसले पर फिर से विचार करेगा ताकि दुनियाभर में क्रिकेट का सिस्टम प्रभावित न हो। पाकिस्तान खुद आईसीसी का सदस्य है। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह सभी स्टेकहोल्डर्स को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला ले।

आईसीसी को कुल कमाई का 10% तक नुकसान

वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मैच सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है। कई बार इस मैच की व्युअरशिप फाइनल से भी ज्यादा होती है। यह मैच न होने से सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को होगा। ब्रॉडकास्टर पहले ही मैच के सारे विज्ञापन स्लॉट बेच चुके हैं। आईसीसी को सीधा नुकसान नहीं है, क्योंकि वह पहले ही मीडिया राइट्स बेच चुकी है। हालांकि, यह मैच न होने से ब्रॉडकास्टर आईसीसी से नुकसान की भरपाई की मांग कर सकते हैं। अलग-अलग एनालिसिस के मुताबिक वर्ल्ड कप में एक भारत-पाकिस्तान मैच से होने वाली कमाई पूरे वर्ल्ड कप की कमाई का लगभग 8 से 10 फीसदी तक होती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा: भारत से पहले ही तय हो चुकी डील

अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत : ट्रंप

वॉशिंगटन डीसी, जेएनएन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। यह बयान ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। हालांकि, भारत सरकार से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ट्रंप ने कहा, हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं। उन्होंने यह भी कहा, भारत से इस सौदे का कांसेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक, चीन भी चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। रिलायंस ने पहले भी अमेरिका से लाइसेंस लेकर वेनेजुएला से तेल खरीदा था। कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। गुजरात में स्थित रिफाइनरी की क्षमता 14 लाख बैरल प्रतिदिन है। 2025 के पहले 4 महीनों में वेनेजुएला कंपनी पीडीवीएसए ने रिलायंस को चार जहाजों से तेल भेजा था, जो रोजाना 63,000 बैरल के बराबर था। मार्च-अप्रैल 2025 में अमेरिका ने कई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए।

मोदी ने 2 दिन पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की

पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई थी। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि दोनों देशों ने साझेदारी को और गहरा करने और आने वाले वर्षों में संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साझा विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।

भारत ने 2019 के बाद बंद कर दी थी वेनेजुएला से तेल खरीदी

अमेरिका ने 2019 में वेनेजुएला पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। सेकंडरी सेंक्शंस भी लगा दिए, यानी जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदती है, उसे अमेरिकी बाजार में व्यापार करने या बैंकिंग सुविधाओं से रोक दिया जा सकता था। इससे कई देशों ने वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत भी वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि तब भारत कुल तेल आयात का लगभग 6 फीसदी वेनेजुएला से लेता था। वेनेजुएला पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक) का सदस्य है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है।

2024 में फिर वेनेजुएलाई तेल खरीदना किया शुरू: अमेरिका ने 2023-2024 में वेनेजुएला पर आंशिक सेंक्शंस ढीले किए, जिससे भारत ने फिर से वेनेजुएला से तेल खरीदा। 2025 में वेनेजुएला से भारत का तेल आयात 1.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन मई 2025 में अमेरिका ने फिर से सख्ती बढ़ा दी।

वेनेजुएला से तेल खरीदने की कोशिश में रिलायंस: रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदने अमेरिका से मंजूरी लेने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव बना रहे हैं।

संक्षिप्त खबरें

पाकिस्तान ने 7 भारतीय बंदियों को किया रिहा

अमृतसर। करीब ढाई साल पहले बाढ़ के दौरान पाकिस्तान जा पहुंचे सात भारतीयों को पाकिस्तान ने वापस लौटा दिया है। वापसी की यह कार्यवाही कल अटारी -वाघा सीमा पर हुई। अटारी सीमा पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सात कैदियों की रिहाई का आदेश आज भारत और पाकिस्तान दोनों को मिल गया था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सातों कैदियों को बीएसएफ को सौंप दिया। वहां से उन्हें औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क और आव्रजन कार्यालय लाया गया। इन सात नागरिकों में से चार फिरोजपुर जिले के, एक जालंधर का, एक लुधियाना का और एक उत्तर प्रदेश का है। ये सभी 2023 की बाढ़ के दौरान अपने जानवरों को बचाने की कोशिश में बहकर पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान से रिहा हुए एक भारतीय नागरिक ने कहा कि मेरे गांव में पुल गिरने के बाद तेज पानी के बहाव के कारण मैं पाकिस्तान चला गया।

एयर इंडिया की शंघाई-नई दिल्ली उड़ान शुरू

नई दिल्ली, जेएनएन। छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच हवाई संपर्क की एक अहम कड़ी फिर से जुड़ गई है। एयर इंडिया ने शंघाई-नई दिल्ली के बीच अपनी सीधी उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। इसे दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क, व्यापार, शिक्षा और संस्थागत सहयोग की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। शंघाई स्थित भारत का महावाणिज्य दूतावास, शंघाई ने इस ऐतिहासिक उड़ान का गर्मजोशी से स्वागत किया। दूतावास के नेतृत्व में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने कहा कि यह उड़ान भारत-चीन संबंधों में फिर से गति आने का ठोस संकेत है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पहली शंघाई-नई दिल्ली सीधी उड़ान रविवार को शंघाई पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई, जिसमें 230 से अधिक यात्री सवार थे। यह उड़ान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित की गई।

मैराथन: फिनिश लाइन से 100 मीटर पहले गिरा युवक, मौत

कार्डियक अरेस्ट के बाद सीपीआर देने पर भी नहीं बची जान

जागरण, इंदौर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रविवार सुबह मैराथन के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान आर्यन तोदी के रूप में हुई है, जो मूलरूप से कोलकाता का रहने वाला था। आर्यन ने मैराथन में रजिस्ट्रेशन कराया था और दौड़ में शामिल भी हुआ था। आर्यन मैराथन पूरी करने के बेहद करीब था।

नेहरू स्टेडियम के फिनिश पॉइंट से महज 100 मीटर पहले उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह स्टेडियम के बाहर गिर पड़ा, उस वक्त मैराथन पूरी हो चुकी थी। युवक के पीछे कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. भरत रावत दौड़ रहे थे। उन्होंने आर्यन को संभाला, सीपीआर दिया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आर्यन को बॉम्बे हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन उसे मृत ही बताया गया। शुरुआती तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। हालांकि, पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. भरत रावत ने बताया कि आर्यन 21 किमी की दौड़ में शामिल था। लौटने के दौरान फिनिश लाइन से कुछ पहले वह अचानक गिरा। दूसरे रनर्स उसे उठाने लगे। तब तक डॉ. रावत वहां पहुंचे, तो उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी।

बैतूल के दामजीपुरा में बवाल, दुकानें जलाईं

पशु से दुष्कर्म का वीडियो वायरल आरोपी को हिरासत में लिया

बैतूल जागरण। प्रदेश के बैतूल जिले के दामजीपुरा गांव में पशु से दुष्कर्म के एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद रविवार को हालात बिगड़ गए। आक्रोशित भीड़ ने दो दुकानों में आगजनी कर दी, जिनमें से एक दुकान आरोपी की बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है।

सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे वीडियो सामने आने के बाद बवाल शुरू हुआ। आक्रोशित भीड़ ने पहले आरोपी की दुकान में आग लगाई, फिर पास की एक अन्य दुकान में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई। खबर फैलते ही आसपास के जिलों से भी लोग दामजीपुरा पहुंचने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भैंसदेही, चिचोली और मोहदा

थानों का पुलिस बल भेजा गया। पुलिस लाइन से वज्र वाहन और अतिरिक्त बल सुबह 11.45 बजे रवाना हुआ और दोपहर करीब 1.35 बजे फोर्स गांव पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाकर हालात काबू में करने की कोशिश की। घटना के दौरान कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा। टायर पंक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और टेलरिंग की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। बाजार बंद कराए गए और अलग-अलग मोहल्लों में भीड़ घूमती रही।

भीड़ ने चौकी में घुसकर आरोपी को पीटा

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है। बताया गया कि वीडियो पुराना है। इस दौरान भीड़ द्वारा पुलिस चौकी में घुसकर आरोपी के साथ मारपीट की खबर भी आई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि उपद्रव की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर भेजा गया और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मोहदा थाना प्रभारी वीके मौर्य ने कहा कि आरोपी हिरासत में है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। दामजीपुरा बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 110 किमी दूर स्थित है। गांव की आबादी लगभग 2500 है।

हिंद महासागर में ईरान-चीन-रूस करेंगे अभ्यास

तेहरान, जेएनएन। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी बढ़ा हुआ है। होर्मूज स्ट्रेट में जहां ईरान लाइव फायर ड्रिल कर रहा है तो फरवरी के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, इसी बीच ईरान की तरफ से एक नया और अहम संकेत सामने आया है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक 'संरचित ढांचा' बन रहा है और यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वह दबाव में आकर कोई सौदा नहीं करेगा। यानी एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला है, तो दूसरी तरफ सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। अमेरिका को साफ संदेश देते हुए ईरान ने ऐलान किया है कि फरवरी के मध्य में वह चीन और रूस के साथ मिलकर उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा, इसमें ईरान की नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगी। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स स्ट्रेट ऑफ होर्मूज में लाइव-फायर नेवल एक्सरसाइज करने जा रही है।

ट्रंप के दबाव के बीच बातचीत का इशारा, जंग के लिए भी तैयार

आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम को दी गाली, गिरफ्तार

चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर में की तोड़फोड़, आगजनी

गुंटूर, जेएनएन। आंध्रप्रदेश के गुंटूर में प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अंबाकी रामबाबू ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गाली दी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने शिकायत के बाद रामबाबू को उनके घर से शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।

इस दौरान सत्ताधरी तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) कार्यकर्ताओं ने गुंटूर की सड़कों और रामबाबू के घर पर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबाती के घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ की साथ ही आग भी लगा दी। गुंटूर जिले के एसपी वकुल जिंदल ने बताया कि रामबाबू

को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामबाबू पहले की वाईएसआरसीपी सरकार में सिंचाई मंत्री थे। उन्हें कड़ी सुरक्षा पुलिस अपने साथ ले गई। कार्यकर्ता टीडीपी सुप्रीमो के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए रामबाबू से माफी मांगने की मांग कर रहे थे।

चीनी जेट बेचकर कर्जा चुका रहा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, जेएनएन। पाकिस्तान अपना कर्जा चुकाने के लिए चीन के फाइटर जेट्स की अन्य देशों के साथ डीलिंग कर रहा है। उसने नाइजीरिया, अजरबैजान, लीबिया, सऊदी अरब, मोरक्को, इंडोनेशिया, इथियोपिया और सूडान जैसे देशों को ये जेट्स बेचे हैं। जिन देशों को जेट्स दिए गए हैं उनमें से 8 मुस्लिम देश हैं।

इस्लामाबाद के कामरा में चीन सरकार का चेंडु एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (सीएसी) और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्पलेक्स (पीएसी) जॉइंट वेंचर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरह से चीन ही ऑपरेट कर रहा है। चीन के लगभग 500 एयरोनॉटिकल इंजीनियर यहां पर नियुक्त हैं।

कामरा यूनिट से हर साल लगभग 50 जे सीरीज फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चीन के जेट बेच कर 18 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी चुका दिया। इससे बार्टर डील कहा जा रहा है। पाक पर सऊदी का लगभग 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। चीन के फाइटर जेट बेचने को ऑलवेज ब्रदर डील का नाम दिया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए के एक जे सीरीज के फाइटर जेट को बेचने का लगभग 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा चीन के हिस्से में जाता है।

जेएफ 17 जेट्स की सउदी अरब लीबिया जैसे देशों से डीलिंग

एपस्टीन फाइल

माइक्रोसाफ्ट के को-फाउंडर अरबपति ने यौन बीमारी के दावे को गलत बताया

रूसी लड़कियों से संबंध नहीं बनाए: बिल गेट्स

वॉशिंगटन डीसी, जेएनएन। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध बनाने और यौन बीमारी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में दावा किया गया है कि बिल गेट्स के रूसी लड़कियों से यौन संबंध थे और इसके बाद उन्हें यौन रोग (एसटीडी) हुआ। गेट्स के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ये दावे गेट्स को फंसाने और बदनाम करने की कोशिश हैं।

प्रवक्ता के मुताबिक, इन दस्तावेजों से सिर्फ इतना पता चलता है कि जेफ्री एपस्टीन इस बात से नाराज था कि बिल गेट्स ने उससे दूरी बना ली थी। इसी वजह से वह गेट्स की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 जनवरी को जेफ्री एपस्टीन जांच से जुड़े

करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज, 2,000 वीडियो और 1.8 लाख तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। शुक्रवार को रिलीज हुई फाइल्स में एपस्टीन ने एक मेल में दावा किया कि यौन रोग होने के बाद बिल गेट्स ने उससे एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थी, ताकि वह ये दवाएं चुपचाप अपनी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे सकें। रिपोर्ट के मुताबिक, एपस्टीन ने एक ईमेल में गेट्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी छवि बचाने के लिए छह साल पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया।

मैंने पूरी फाइलें नहीं देखीं : ट्रंप

फरवरी 2026 में न्याय विभाग द्वारा 30 लाख से अधिक नए दस्तावेजों के जारी होने के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ये फाइलें उन्हें किसी भी गलत काम से पूरी तरह बरी करती हैं। ट्रंप ने कहा कि हालांकि उन्होंने खुद पूरी फाइलें नहीं देखी हैं, लेकिन उन्हें बताया गया है कि ये दस्तावेज उन पर लगे आरोपों के विपरीत परिणाम दिखाते हैं और कट्टरपंथी वामपंथियों की उम्मीदों के उलट हैं। उन्होंने लेखक माइकल वोल्फ पर मुकदमा करने की योजना बनाई है। ट्रंप का आरोप है कि वोल्फ ने उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए एपस्टीन के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुराने संबंधों पर स्पष्टीकरण- ट्रंप ने बार-बार जोर दिया है कि उन्होंने 15 साल पहले ही एपस्टीन से अपनी दोस्ती खत्म कर दी थी।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बुश पर रेप का आरोप

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से 30 जनवरी को जारी एपस्टीन फाइल्स में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर एक पुरुष के साथ रेप का आरोप लगा है। जॉर्ज बुश का नाम एपस्टीन की निजी डायरी या रिकॉर्ड में नहीं है। बल्कि उनका जिक्र न्यूयॉर्क पुलिस की चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन यूनिट को दी गई एक शिकायत में है। यह शिकायत उस शख्स ने दी थी, जो खुद को एपस्टीन का पीड़ित बताता है। दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल में पीड़ति के बयान का जिक्र है। इसमें लिखा है कि बुश-1 ने भी उसके साथ बलात्कार किया। ये कहीं नहीं बताया गया है कि जॉर्ज बुश 1 कौन हैं। अमेरिका में जॉर्ज बुश नाम के 2 राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1998 में जॉर्ज बुश सीनियर राष्ट्रपति बने थे, वहीं उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2000 में राष्ट्रपति बने। वहीं, नई रिलीज फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 100 से ज्यादा बार जिक्र है। हालांकि, ट्रंप का ज्यादातर जिक्र एफबीआई की लिस्ट में है। एफबीआई ने इसे पिछले साल तैयार किया था। इसमें वे बातें दर्ज हैं, जो कुछ लोगों ने एफबीआई को फोन करके ट्रंप के खिलाफ कही थीं। ये आरोप ज्यादातर बिना किसी ठोस सबूत के हैं और सिर्फ फोन पर मिली जानकारियों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

फिल्म निर्देशक शेट्टी के घर पर 4 राउंड फायरिंग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेवारी

मुंबई, जेएनएन। महाराष्ट्र के मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीमें उनके घर पहुंचीं। रोहित शेट्टी मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं। उनके घर के पास बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज के घर हैं। डायरेक्टर के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मुंबई पुलिस ने बताया कि ये घटना शनिवार रात करीब 3 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की। इसके बाद जुहू में रोहित शेट्टी के घर के आसपास सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। हमले के पीछे

का मकसद अभी पता नहीं चला है। मामले में अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने रविवार दोपहर बताया कि इस मामले में पुणे के कारवेनगर और धायरी इलाकों से चार लोगों को हिरासत में लिया है। जांच जारी है। घटना के बाद, सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान और बैलिस्टिक्स विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंची।

राजधानी का तापमान/मौसम

अधिकतम 26.6°c | न्यूनतम 12.0°c

राजधानी में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, आज भी तापमान गिर सकता है

•11• राज्य •31• संस्करण मध्य प्रदेश • उत्तर प्रदेश • दिल्ली • हरियाणा • उत्तराखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • बिहार • झारखंड • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित www.dainikjagranmpcg.com

नगर में आज

सांस्कृतिक आयोजन

- **स्थान:** स्टूडियो एक्सो, एमपी नगर
- **समय:** रात 8 बजे से

जश्ने उर्दू

- **स्थान:** गोलघर, शाहजहांनाबाद
- **समय:** शाम 4:30 बजे से

राजधानी को मिलेगा नया कमर्शियल हब, तीन साल में होगा पूरा

पांच नंबर मार्केट की जगह बन रही 20 मंजिला इमारत, 7 जनवरी को जारी हुए टेंडर, मार्च में शुरू होगा 650 करोड़ का प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, भोपाल। राजधानी भोपाल में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए न्यू मार्केट और एमपी नगर के बाद एक और नया कमर्शियल हब विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है, जल्दी ही 5 नंबर स्थित रविशंकर शुक्ल मार्केट की जगह 20 मंजिला ऊंची इमारत बनाई जाएगी। इस हाईराइज इमारत के लिए 7 जनवरी को टेंडर जारी कर दिए गए हैं। मार्च से इसका निर्माण शुरू होने की तैयारी है, जिसके बाद 42 महीने (3.5 साल) के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि इस इमारत के बन जाने के बाद शहर में भी अन्य मेट्रो सिटी की तरह कमर्शियल उपयोग के लिए हाईराइज इमारत तैयार होगी। इस इमारत में नीचे दुकानें और

रेसिडेंशियल उपयोग के लिए वन बीएचके से 4 बीएचके वाले लग्जरी फ्लैट भी तैयार किए जाएंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण मध्य प्रदेश री डेवलपमेंट पॉलिसी 2023 के तहत किया जा रहा है, जिसमें विकास कार्य के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड निर्माणाधीन एजेंसी के रूप में निवेश कर रहा है। बता दें कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा से अनुमति लेने का काम किया जा रहा है। बिल्डिंग परमिशन में देरी से प्रोजेक्ट के लेट होने की बात भी सामने आ रही है।

शिफ्ट हो रहीं दुकानें : टेंडर के साथ ही 5 नंबर स्थित 50 साल पुराने रविशंकर शुक्ल मार्केट की पुरानी दुकानों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 5 दशक में यह मार्केट जर्जर हो गया है। अब इस मार्केट परिसर को तोड़कर आधुनिक मिक्स्ड-यूज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वर्तमान में मार्केट में मौजूद 65 पुरानी दुकानों को खाली कराया जा रहा है। दुकानदारों के लिए मार्केट के सामने ही अस्थायी शेड तैयार कर दुकानों की शिफ्टिंग कराई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार नए प्रोजेक्ट के तहत यहां पर 125 नई दुकानें बनाने की तैयारी है।

प्रोजेक्ट में किए गए बदलाव

इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत पहले यहां पर 5-बीएचके फ्लैट बनाए जाने की तैयारी थी, जिसकी जगह पर अब वन बीएचके से लेकर 4 बीएचके फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जिनकी कीमत भी अलग अलग होगी। यह सभी फ्लैट्स का निर्माणा 2800 से 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल में किया जाएगा। बता दें कि अभी यहां के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 165 फ्लैट हैं। इनकी संख्या बढ़कर आने वाले समय में 380 हो जाएगी, जिसमें से 165 फ्लैट पुराने रहवासियों को दिए जाएंगे। जबकि 215 फ्लैट्स नए खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इन सभी फ्लैट्स में 4 बालकनी सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

प्रोजेक्ट की विशेषताएं

- नए प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र में 20 मंजिल ऊंचे आठ ३टावर बनाए जाएंगे।
- हर टावर में लगभग 48 फ्लैट बनाए जाएंगे।
- रहवासियों के लिए स्वीमिंग पूल, योगा मेडिटेशन सेंटर
- बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया जाएगा।
- रहवासियों और ग्राहकों के लिए अलग-अलग पार्किंग एरिया रहेगा।
- भूकंप रोधी आरसीसी स्ट्रक्चर से निर्माण किया जाएगा।
- शहर के बीच में होने के कारण प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी होगी।

संक्षिप्त खबरें

पुलिस देर रात सड़कों पर उतरी, 163 वारंटी गिरफ्तार

क्राइम रिपोर्टर, भोपाल। पुलिस कमिश्नरेट के जोन-4 में शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात कॉम्बिंग गश्त की गई। पुलिस के सड़कों पर उतरने से बदमाशों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने सात घंटे के अंदर कुल 163 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। सबसे ज्यादा निशातपुरा पुलिस ने 36 वारंट तामील किए हैं। डीसीपी जोन-4 मयूर खंडेलवाल ने बताया स्थायी, गिरफ्तारी वारंटों की तामीली, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, निगरानी/गुंडा फाइलों की समीक्षा के चलते शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात जोन-फोर में कॉम्बिंग गश्त की गई। विशेष अभियान में एडिशनल डीसीपी मलकीत सिंह, एसीपी निशातपुरा अक्षय चौधरी, एसीपी चुनाभट्टी आलोक श्रीवास्तव सहित जोन-फोर के समस्त थाना प्रभारी व पुलिस बल शामिल हुआ। कॉम्बिंग गश्त के दौरान थाना चूनाभट्टी ने 13, थाना कोलार ने 32, थाना गांधीनगर ने 14, थाना छोला मंदिर ने 13, थाना बैरागढ़ ने 30, थाना खजूरी सड़क ने 15 और थाना निशातपुरा ने 36 स्थायी व गिरफ्तारी वारंट तामील किए। अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

15 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत

जागरण, भोपाल। कोलार थाना क्षेत्र में करंट लगने से 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना वक्त वह अपने घर में बिजली सुधार रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 15 वर्षीय आयुष खंडेल पिता राकेश थुआखेड़ा में रहता था। वह 9वीं क्लास का छात्र था। उसके पिता मजदूरी करते हैं। आयुष दो भाईयों में बड़ा था। रविवार दोपहर एक बजे वह अपने घर पर इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। करंट का तेज झटका लगने से वह बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। घटना के बाद परिजन तुरंत उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला बैंक अधिकारी की थार से स्टेपनी चोरी

जागरण, भोपाल। मन्नीपुरम कॉलोनी में महिला बैंक अधिकारी की थार से चोर ने स्टेपनी उड़ा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 36 वर्षीय अम्रत कौर चार इमली स्थित मन्नीपुरम कॉलोनी में रहती है। वह टीटीनगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क का काम करती हैं। 27 जनवरी को रात 11.30 बजे उन्होंने घर के बाहर साइड में अपनी महेन्द्र थार खड़ी कर सोने चली गई थी। अगले दिन जब उन्होंने शाम करीब साढ़े सात बजे गाड़ी को देखा तो पीछे लगी थार के पीछे लगी स्टेपनी गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक आरोपी नजर आया। जिसके बाद उन्होंने हबीबगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

ऑनलाइन बेटिंग की लत ने फोरेन रिटर्न इंजीनियर को बनाया चोर, एसी कोच में देर रात करता था चोरी

200 सीसीटीवी फुटेज खंगाल गुलमोहर स्थित घर तक पहुंची जीआरपी

क्राइम रिपोर्टर, भोपाल। आनलाइन बेटिंग की लत ने फोरेन रिटर्न एक इंजीनियर को चोर बना दिया। ऑनलाइन बेटिंग में वह जमा पूंजी 10 लाख रुपए हार गया था। हरकतों की वजह से नौकरी चली गई। इधर, पत्नी ने तलाक के लिए केस लगा दिया। डेढ़ महीने पहले वह भोपाल पहुंचा। गुलमोहर कालोनी स्थित एक कमरे में किराए से रहने लगा। रेलवे स्टेशन भोपाल में एक पर्स चोरी किया। बचकर निकला तो यह आदत बन गया। डेढ़ माह में उसने 15 चोरी की। इसमें चार चोरी बड़ी थी, जिसमें सात लाख का माल उड़ाया। वह रात एक बजे से तीन के बीच ट्रेन के एसी कोच में चढ़कर चोरी करता था। खासकर सोती हुई महिलाओं के पर्स चोरी कर निकल जाता था। जीआरपी ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उसके घर तक पहुंची और उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार चोरी के केस दर्ज कर सात लाख रुपए कीमती जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पत्नी ने तलाक का केस लगा दिया

इधर, शादी होने के बाद पत्नी ने भी तलाक का केस लगा दिया। मां अकेले लखनऊ में रहती है। डेढ़ माह पहले वह भोपाल आया था। जॉब तलाश की, लेकिन नहीं मिली। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इस बीच वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। जहां एक पर्स चोर कर लिया। इसमें नकदी मिली और वह आसानी से बाहर निकल आया। तब उसे लगा कि यह काम आसान है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। इसके बाद ट्रेनों के एसी कोच में चोरी करने लगा। रिमांड खत्म होने के बाद जीआरपी ने उसे जेल भेज दिया है।

दो दिन रिमांड पर लेकर की पूछताछ

भोपाल रेलवे स्टेशन जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि बीते दिनों अचानक रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात में इजाफा हुआ। इस बीच 20 जनवरी को अफशा बेगम (52) निवासी वजीरपुर आगरा राजधानी एक्सप्रेस से एसी कोच में सवार होकर आगरा से मुंबई जा रही थीं। स्टेशन भोपाल पर उनके सिराहने रखा लेडीस पर्स चोरी हो गया। पर्स ने नकदी 35 हजार रुपए समेत जेवरात रखे थे। जिसकी कुल कीमत 3.40 लाख रुपए थी। मुंबई पहुंचकर उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें एक संदेही युवक दिखा, जोकि पिट्ठू बैग लिए था और हाथ में महिला का पर्स था। पुलिस ने रोड मैप तैयार किया। करीब 200 कैमरों के खंगालने के बाद संदेही प्रांजल दीक्षित (36) पिता प्रभात दीक्षित के गुलमोहर कालोनी स्थित किराए के घर तक पुलिस पहुंची। प्रांजल मूलतः बी/28 देव स्थान लखनऊ, यूपी का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने उसे दो दिन की रिमांड पर लिया।

10 लाख रुपए हार गया: आरोपी प्रांजल ने बताया कि उसने पूना एक कालेज से बीटेक किया। इंजीनियर बनने के बाद एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम किया। उसे दो बार फोरेन भेजा गया। कुछ समय बाद उसकी जॉब छूट गई। इस बीच उसे आनलाइन बेटिंग की लत लग गई। इसमें वह 10 लाख रुपए हार गया।

डॉक्टर के सूने मकान में चोरी

भोपाल। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में चोरों ने डॉक्टर के सूने मकान को निशाना बनाया। दो संदिग्ध आरोपियों घर में घुसते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए है। जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश की कर रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 46 वर्षीय अनंत भान पिता योगीलाल हैवेल्स लाइफ कॉलोनी में रहते है। वह पेशे एक डॉक्टर है। वह पिछले कुछ सालों से परिवार के साथ अपोलो अस्पताल के पास नए मकान में रहते थे। जिससे उनका मकान खाली पड़ा था। 22 नवंबर 2025 को अज्ञात चोर द्वारा ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हाल ही जब वह किसी काम से मकान में पहुंचे। तो घर का ताला टूटा मिला।

प्री-बोर्ड परीक्षा के फिसड्डी विद्यार्थियों की विशेष तैयारी

सीबीएसई की 15 तक चलेंगी प्रायोगिकी परीक्षाएं

एजुकेशन रिपोर्टर, भोपाल। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। सोमवार से 15 फरवरी तक विषयवार प्रायोगिक परीक्षाएं चलेंगी। 17 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। पिछले सप्ताह ही राजधनी सहित प्रदेशभर के सीबीएसई स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। विद्यार्थियों की तैयारी देखने परीक्षा कराई गई थीं। परीक्षा में फिसड्डी विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है। अब उक्त विद्यार्थियों की विशेष कक्षाएं शुरु कर दी गई हैं। उक्त कक्षाओं में उन्हें मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। प्राचार्यों का कहना है कि दोनों ही कक्षाओं में 15 से लेकर 20 फिसड्डी विद्यार्थी निकलकर सामने आये हैं। उन्हें अपेक्षा अनुसार तैयारियां नहीं कर पाये हैं। ज्यादातर विद्यार्थी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय में कमजोर निकले हैं। उक्त विद्यार्थियों के अभिभावकों से संवाद किया जा रहा है। इसमें पालकों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर घरों पर ध्यान दें। इससे उनके बच्चे उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण हो सकेंगे। सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों की तैयारियों के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ हो रही हैं। फिजिक्स, कैमिस्ट्री एवं बायोलॉजी विषयों के की प्रायोगिक परीक्षाएं 15 फरवरी तक चलेंगी। इसके बाद 17 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरु हो जाएंगी। वर्तमान में विद्यार्थियों की स्कूल स्तर पर कांउसलिंग की जा रही है।

बोर्ड परीक्षा से पहले फर्जी पेपर गैंग सक्रिय,एडवाइजरी जारी

जागरण, भोपाल। फरवरी और मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से पहले फर्जी पेपर गैंग सक्रिय हो गया है। इसको लेकर साइबर क्राइम ने छात्रों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोर्ड परीक्षा के लीक पेपर और सॉल्यूशन के नाम पर फर्जी प्रश्नपत्र वायरल किए जा रहे हैं। इससे छात्रों में भ्रम फैलाने के साथ पैसे की ठगी भी हो रही है। पुलिस ने कहना है कि किसी भी अनजान लिंक,ग्रुप या व्यक्ति से मिले प्रश्नपत्र को असली नहीं होते है। बोर्ड परीक्षा का प्रश्नपत्र केवल परीक्षा केंद्र पर ही मिलता है। छात्रों से अपील की गई है कि किसी भी फर्जी प्रश्नपत्र से जुड़ा मैसेज मिलने पर तुरंत निजी थाने और साइबर क्राइम भोपाल की हेल्पलाइन 9479990636, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें।

कार की टक्कर से 6 साल की बच्ची की मौत, सड़क पार करते समय हुआ हादसा

माता-पिता के साथ थी बच्ची, कार चालक के खिलाफ केस दर्ज

क्राइम रिपोर्टर, भोपाल। ईंटखेड़ी इलाके में कार की टक्कर से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के वक्त वह सड़क पार कर रही थी। उसके साथ माता-पिता थे। घटना के बाद चालक, घायल बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार की पहचान कर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईंटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि आसिया अली (6) पिता इकबाल अली परेवाखेड़ा पतलोन की रहने वाली थी। आसिया को तीन दिन से वायरल फीवर आ रहा था। शनिवार रात उसके पिता व मां उसे लेकर गांव के पास हाइवे पर स्थित एक क्लीनिक में दिखने पहुंचे थे। डाक्टर को दिखाने के बाद परिवार वहां से लौट रहा था। परेवाखेड़ा के पास मुख्य मार्ग पर बच्ची ने पिता का हाथ छुड़ाया और सड़क पार करने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। कार चालक स्वयं बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया। मर्ग कायम करने के बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

50 फीट रेलिंग तोड़कर बाणगंगा के नाले में गिरी कार

जागरण, भोपाल। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए बाणगंगा के नाले में गिर गई। हादसे के समय कार में चार युवक सवार थे। घटना शनिवार देर रात गर्वनर हाउस से पॉलीटेक्निक की तरफ जाने वाली सड़क पर रवींद्र भवन के पास हुआ है। पुलिस के अनुसार कार में सवार युवकों को गंभीर चोट नहीं आई। हादसा देर रात हुआ था। क्रेन से कार को उठाने का कोशिश की गई लेकिन च्यादा गहराई में होने से कार को बाहर नहीं निकाला जा सका। घटना से सड़क किनारे लगी करीब 50 फीट रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। मामूली एक्सीडेंट होने से किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

बंटी-बबली ने कंपनी में निवेश व डायरेक्टर बनाने के नाम पर निवेशक से 40 लाख ऐंठे

15 फीसदी प्रतिवर्ष रिटर्न का किया वादा, साइनिंग व बैंक अथॉरिटी रखी अपने पास

क्राइम रिपोर्टर, भोपाल। बंटी-बबली ने कंपनी में निवेश और डायरेक्टर बनाने के नाम पर एक निवेशक से 40 लाख रुपए ऐंठ लिए और नौ-दो-ग्यारह हो गए। जालसाज दंपति और साले ने 15 फीसदी प्रतिवर्ष रिटर्न देने का झांसा दिया लेकिन साइनिंग और बैंक अथॉरिटी अपने पास रखी। करीब डेढ़ साल बाद निवेशक को कंपनी से भगा दिया। उसके पैसे भी नहीं लौटाए। पीड़ित ने मिसरोद थाने में इसकी शिकायत की। डेढ़ साल चली लंबी जांच के बाद पुलिस ने शनिवार को आरोपी पति-पत्नी और साले के खिलाफ अमानत में खयानत समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इस बीच आरोपी कंपनी किसी दूसरे के बेचकर फरार हो गए। घटना सी-21 मॉल की है। मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि 45 वर्षीय हितेश कुमार सिंह एक टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते थे। कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई। उनके पास कुल जमा पूंजी 44 लाख रुपए थी। इस बीच उनकी मुलाकात अमितेश सिन्हा, उनकी पत्नी प्रिया व साले सन्नी से हुई। तीनों मिलकर सी-21 मॉल में उपलब्ध निधि, उपलब्ध फिनसर्स, अमिपिया समेत अन्य कंपनी चलाते थे। उन्होंने हितेश को बोला कि आप हमारी कंपनी उपलब्ध निधि में 40 लाख रुपए निवेश करो। इस पर वह प्रतिवर्ष 15 फीसदी रिटर्न देंगे। साथ ही कंपनी में डायरेक्टर बनाएंगे। हितेश को उनकी डील पसंद आ गई। झांसे में आने के बाद हितेश ने 40 लाख रुपए का निवेश उनकी कंपनी में किया। लेकिन साइनिंग और बैंक अथॉरिटी अपने पास रखी।

डेढ़ साल बाद कंपनी से भगा दिया

करीब डेढ़ साल तक हितेश इस कंपनी में डायरेक्टर रहे। बाद में उन्हें पता लगा कि उनकी पैसा उपलब्ध निधि में न लगाकर उपलब्ध फिनसर्स में लगाया गया है। तीनों ने न तो हितेश को रिटर्न दिया और न ही उनके पैसे लौटाए। इसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया। ठगी का अहसास होने पर जुलाई 2024 में हितेश ने इस संबंध में मिसरोद थाने में शिकायत की। शिकायती आवेदन की लंबी जांच के बाद शनिवार को आरोपी अमितेश सिन्हा, प्रिया और सन्नी के खिलाफ केस दर्ज किया।

कंपनी बेचकर भी लगाया चूना

इसके पूर्व आरोपी उक्त कंपनी किसी दूसरे को बेचकर भाग निकले। बताया गया है कि आरोपियों ने उन्हें भी चूना लगा दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी शातिर हैं। अमितेश मूलतः बिहार का रहने वाला है। पुलिस उनका आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है।

पक्षी गणना भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट 2025-26 में पक्षी को खोजा गया, खंडवा और बुरहानपुर में भी हो चुका ट्रैक

लुप्त मान लिया गया नौ इंच का चित्तीदार उल्लू भोपाल में दिखा

जागरण संवाददाता, भोपाल। लगभग दो दशक पहले तक पूरी दुनिया में लुप्त मान लिए गए फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट (चित्तीदार उल्लू) की जनसंख्या मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में भी बढ़ रही है। हाल ही में इस पक्षी को भोपाल जिले में भी चिन्हित किया गया है, जो कि भोपाल के वन्य क्षेत्र की जैव विविधता के लिए अच्छे संकेत हैं। रविवार को मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, भोपाल सामान्य वनमंडल, भोपाल बर्ड्स संस्था और वीएनएस नेचर सेवियर्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट 2025-26 में इस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई है। भोपाल के बिशनखेड़ी और बीलखेड़ा के आसपास इस पक्षी को खोजा गया है। इन सभी संस्थाओं की ओर से आयोजित पक्षी गणना के अंतर्गत 110 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। जिसमें बिशनखेड़ी में 64, बम्होरी में 55, बीलखेड़ा में 45 पक्षियों को चिन्हित किया गया। बता दें कि फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट के लुप्त होने क बाद भी इनकी खोज शोधार्थियों द्वारा लगातार जारी रही। अब महाराष्ट्र के बाद इस पक्षी की संख्या मप्र में भी बढ़ रही है। खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल के बाद भोपाल व आसपास के वन क्षेत्रों में इस पक्षी की उपस्थिति दर्ज की गई है। जिसके बाद इनके संरक्षण के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं।

आठ से नौ इंच होती है लंबाई

भारत में चित्तीदार उल्लू के नाम से प्रसिद्ध इस जीव की लंबाई मात्र आठ से नौ इंच होती है, इसलिए इसे छोटा उल्लू भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पेड़ों की कोटरों में रहना पसंद करते हैं। जीव विज्ञानी बताते हैं कि पुराने पेड़ों में ही कोटरों का विकास होता है, लेकिन लगातार जंगलों के कम होने से इस तरह के पेड़ों की संख्या कम हो गई। प्राकृतिक आवास कम होने से इनकी संख्या तेजी से घटने लगी।

इन क्षेत्रों में सीमित है फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट

फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट की बड़ी संख्या गुजरात और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा में लगभग 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैले जंगलों तक ही सीमित मानी जाती रही, लेकिन इसे अब भोपाल में भी देखा गया है। 150 साल पहले तक यह पक्षी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी बहुतायत से पाया जाता था। इस पक्षी की खोज में जीव विज्ञानी महाराष्ट्र की सीमा से लगे बैतूल के जंगलों में खोज करते रहे हैं। पर अब यह फिर से दिखने लगा है।

113 सालों तक माना गया विलुप्त

फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट की खोज 1872 में ब्रिटिश पक्षी शास्त्री एलन आक्टेवियन ह्यूम ने की थी। उसके बाद लगभग 113 सालों तक इसे नहीं देखा गया और उसे लुप्त मान लिया गया। बाद में वर्ष 1997 में वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सोसायटी की डॉ. प्राची मेहता ने खंडवा में इन्हें एक सागौन के पेड़ पर खोजा था। इसके बाद संरक्षण को लेकर प्रयास तेज हुए। लेकिन उसके बाद भी इन्हें कभी कभार ही देखा जाता था।

1.50 लाख क्लब की सदस्यता पार नहीं कर सका राजाभोज एयरपोर्ट

इंडिगो में क्रू समस्या व कोहरे से रद्द रहीं फ्लाइटें

हिरदाराम नगर प्रतिनिधि। दिसम्बर में इंडिगो के क्रू की समस्या ने जहां यात्रियों की संख्या को ब्रेक लगा दिया। सप्ताहभर 40 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं, वहीं जनवरी माह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा होने से कई बार एयर इंडिया व इंडिगो की उड़ानें भोपाल नहीं आ सकीं। इससे यात्रियों की बढ़ती संख्या पर ब्रेक लगा गया। इस कारण जनवरी में भी राजा भोज एयरपोर्ट 1.50 लाख यात्री क्लब की सदस्यता पार नहीं कर सका। संतोष की बात यह रही कि इस क्लब से अब वह केवल 27 यात्री ही दूर है और फरवरी माह में उसे पूरा करने की उम्मीद है। जनवरी में जहां 73564 यात्री भोपाल आए, वहीं भोपाल से 26209 यात्रियों का आगमन हुआ जबकि दिसंबर 2025 में 73285 का आगमन एवं 73391 प्रस्थान इस तरह कुल 148676 यात्रियों का आवागमन हुआ। उसकी तुलना में जनवरी 2025 में संख्या में कुछ

बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर माह में इंडिगो के क्रू समस्या के कारण लगभग एक सप्ताह तक पूरे भारत सहित भोपाल आने व जाने वाली उड़ानें भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहीं। अगर वह स्थिति न आती तो शायद राजा भोज एयरपोर्ट 1.50 लाख यात्री क्लब की सदस्यता में शामिल हो जाता। वैसे एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने उम्मीद जताई है कि फरवरी माह 28 दिन का होने के बावजूद मौसम साफ होते ही यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और यह आंकड़ा 1.50 लाख से पार हो जाएगा।

केंद्रीय बजट में हुआ ऐलान

भोपाल के जेपी सहित 27 जिला अस्पतालों में इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर बनेंगे, गोल्डन ऑवर में मिलेगा इलाज

पहले चरण में प्रदेश के दूरस्थ जिलों में होगा काम

नगर संवाददाता, भोपाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली, विशेषकर आपातकालीन चिकित्सा में एक नए युग की शुरुआत की है। बजट में देश के 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर विकसित करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है, जहां सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन मामलों में समय पर इलाज न मिलना एक बड़ी चुनौती रही है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 55 जिले। केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत की नीति के अनुसार, मध्य प्रदेश के लगभग 27 जिला अस्पतालों को पहले चरण में इमरजेंसी एंड ट्रामा सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इन अस्पतालों का चयन उनकी भौगोलिक स्थिति, नेशनल हाईवे से निकटता और वर्तमान में वहां के मरीजों के दबाव के आधार पर किया जाएगा।

ट्रामा सेंटर में क्या-क्या होंगी सुविधाएं

अत्याधुनिक आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर: दुर्घटना के तुरंत बाद सर्जरी के लिए समर्पित 24×7 ओटी और वेंटिलेटर सुविधा।
एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स: सेंटर के भीतर ही सीटी स्कैन, एमआरआई और डिजिटल एक्स-रे की सुविधा होगी ताकि मरीज को बाहर न जाना पड़े।
विशेषज्ञ टीम: एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और ट्रामा सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की तैनाती होगी।
ब्लड स्टोरेज और लैब: इमरजेंसी के लिए पृथक ब्लड बैंक लिंकेज औरक्ष इंटीग्रेटेड लैब, जहां जांच रिपोर्ट मिनटों में उपलब्ध होगी।
टेली-मेडिसिन: ये सेंटर एम्स जैसे बड़े संस्थानों से सीधे जुड़े होंगे, ताकि जटिल मामलों में बड़े डॉक्टरों की सलाह ली जा सके।

बजट और खर्च का गणित

स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आवंटित 1,06,530 करोड़ के बजट में से एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत खर्च किया जाएगा। प्रत्येक सेंटर के अपग्रेडेशन पर करोड़ों रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो केंद्र और राज्य सरकार के 60:40 के अनुपात में हो सकता है। बजट में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का भी लक्ष्य है, जो इन ट्रामा सेंटर्स में रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे। बजट 2026 का यह फैसला मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा के रेफरल कल्चर को खत्म करेगा। जब जिला स्तर पर ही वेंटिलेटर और सर्जन उपलब्ध होंगे, तो हजारों कीमती जानें बचाई जा सकेंगी।

किन मरीजों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

सड़क दुर्घटना के शिकार: गोल्डन ऑवर (हादसे के बाद का पहला घंटा) में इलाज मिलने से मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक की कमी आएगी।
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मरीज: समय पर थ्रॉम्बोलेसिस (थक्का घोलने का इंजेक्शन) मिलने से पैरालिसिस और मौत का खतरा कम होगा।
गरीब और मध्यम वर्ग: प्राइवेट अस्पतालों के भारी-भरकम इमरजेंसी खर्च से मुक्ति मिलेगी।
ग्रामीण आबादी: ब्लॉक स्तर के मरीजों को अब बड़े शहरों (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर) तक भागने की जरूरत नहीं होगी।

सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप बजट: सीएम

विसं, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बजट विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है। डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा।

मध्यप्रदेश को मिलेगा विशेष लाभ: उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आम बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बड़ा कदम है। इसका लाभ मप्र को भी मिलेगा। प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगा। वित्त विभाग संभाल रहे देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेज गति से जीडीपी में बढ़ोतरी कर रहा है। पूंजीगत व्यय में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 2 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

संक्षिप्त खबरें

नकल रोकने अब साफ्टवेयर से छांटे जाएंगे परीक्षा केंद्राध्यक्ष

एजुकेशन रिपोर्टर, भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं-बारहवीं परीक्षा में केंद्राध्यक्षों की तैनाती में अब मनमानी नहीं चलेगी। परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष का फैसला अधिकारी नहीं, बल्कि साफ्टवेयर के माध्यम से लिया जाएगा। दसवीं-बारहवीं बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में नकल पर रोक और प्रश्न पत्र को लीक होने बचाने नियमों को सख्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति विकासखंड स्तर पर नहीं होगी। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष बनने योग्य व्यक्तियों की जिला स्तरीय सूची तैयार होगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति अनुमोदित सूची जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेजेंगे। यहां मौजूद केंद्रों की सूची से उक्त सूची को भी विशेष सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। वह सॉफ्टवेयर रैंडम पद्धति से किसी शिक्षक का नाम जिले के किसी केंद्र के साथ केंद्राध्यक्ष या सहायक केंद्राध्यक्ष के तौर पर जोड़ देगा। गत वर्ष की परीक्षा में कई परीक्षा केंद्रों पर सामूहिक नकल कराई गई है, उक्त केंद्रों नियुक्त केंद्राध्यक्षों को वर्तमान वर्ष की परीक्षा में केंद्राध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। गोपनीयता भंग करने या परीक्षा कार्य में घोर लापरवाही बरतने वाले केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं लगाने का निर्देश हुआ है। मंडल ने परीक्षा कार्य से डीबार हुए शिक्षक और प्राचार्यों को अपात्र कर दिया है।

गोपनीयता भंग करने या काम में लापरवाही करने वाले बाहर

टीआईटी में रैगिंग, जूनियर के साथ सीनियर ने की मारपीट

एजुकेशन रिपोर्टर, भोपाल। टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (टीआईटी) में रैगिंग की घटना सामने आई है। यहां प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ सीनियर ने मारपीट की। दूसरी तरफ मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) में एक बार फिर रैगिंग की घटना सामने आई है। दोनों घटनाओं की शिकायत यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में गई है। दोनों संस्थानों को कार्रवाई कर सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है। टीआईटी में एक जूनियर विद्यार्थी के साथ सीनियर ने मारपीट कर रैगिंग ली है। जूनियर को लात घूसों से पीटा गया है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। जूनियर ने सीनियर विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर दी है। हेल्पाहइन ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कालेज प्रबंधन और आरजीपीवी को ई-मेल भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। इसके चलते आरजीपीवी ने टीआईटी प्रबंधन को कार्रवाई पूर्ण कर तीन दिन में पत्र भेजकर सूचित करने के लिए कहा है। दूसरी ओर मैनिट में लगातार तीसरी रैगिंग की घटना एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में दर्ज की गई है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को करीब आधा दर्जन विद्यार्थियों ने पीटा है। जूनियर ने सीनियर विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। हेल्पलाइन ने मैनिट प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई कर सूचित करने को कहा है। वहीं हेल्पलाइन पर प्रकरण को गंभीर प्रकरण की श्रेणी में डाल दिया गया है। मैनिट प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा अधिकारी और एंटी रैगिंग कमेटी के अध्यक्ष ने करीब दो दर्जन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी हैं।

मैनिट में दर्ज हुई रेगिंग की तीसरी शिकायत

शाहजहांनाबाद के स्मारकों पर पुरातत्व इंडिया की हैरीटेज वॉक

जागरण, भोपाल। धरोहरों के माध्यम से शहर के इतिहास और संस्कृति से भोपालवासियों को जोड़ने के उद्देश्य से रविवार को पुरातत्व इंडिया कम्युनिटी ने हैरीटेज वॉक का आयोजन किया। यह वॉक मुख्य रूप से भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में मौजूद स्मारकों पर केंद्रित रही जिसमे साहित्य, कला, शिक्षा और शासकीय सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए 20 प्रतिभागियों सम्मिलित हुए। इस हैरीटेज वॉक को पुरातत्वविद शिवाजी राय ने लीड किया। पुरातत्व प्रेमियों ने बड़ा बाग के शाही मकबरों और बावड़ी के स्थापत्य को करीब से जाना।

नो मैपिंग वाले 73 हजार 254 वोटर्स की सुनवाई पूरी

जागरण संवाददाता, भोपाल। जिला निर्वाचन कार्यालय को नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के रविवार शाम तक 81 हजार 614 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। इन सभी आवेदनों की जांच के बाद इन्हें नई मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अलावा नाम, पते व अन्य संशोधन के लिए 48 हजार 324 और नाम कटवाने के लिए 10 हजार 439 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नो मैपिंग वाले 1 लाख 16 हजार 925 मतदाताओं में से 73 हजार 254 की सुनवाई पूरी हो गई है। अब 13 दिनों तक 43 हजार 671 मतदाताओं की सुनवाई और दस्तावेजों की जांच की जाना है। सुनवाई का काम तेज गति से हो सके। इसके लिए एईआरओ की संख्या भी 90 से बढ़ाकर 181 कर दी गई है। बता दें कि सुनवाई का काम सबसे धीमे हुजूर और नरेला विधानसभा में चल रहा है। वहां एईआरओ की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

नाम जुड़वाने 81 हजार लोगों ने किया आवेदन

मप्र से होकर गुजरेगा दनकुनी-सूरत रेलवे फ्रेट कॉरीडोर

रेल बजट में भोपाल मंडल के कई स्टेशनों को फंड, इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन के काम को मिलेगी तेजी

नगर संवाददाता, भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में रेल मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्रालय को मिले इस बजट में मप्र के लिए कई योजनाओं का उल्लेख है। मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों और रेल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे अहम इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन और भोपाल-रामगंजमंडी रेल परियोजना शामिल है। इसके अलावा जो सात नए हाई स्पीड रेल कॉरीडोर हैं, उनमें से एक कॉरीडोर मप्र के कुछ जिलों से होकर गुजरेगा। जो पश्चिम बंगाल के दनकुनी से गुजरात के सूरत तक के लिए बनाया जा रहा है। इसका कुछ हिस्सा दक्षिण-पूर्वी मप्र से होकर गुजरेगा।

मप्र के व्यापार को लगेंगे पंख: रेल बजट में पश्चिम बंगाल के दनकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए पूर्व-पश्चिम समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर की घोषणा की है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वी और पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे जोड़ेगा। यह कॉरिडोर औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इसकी शुरुआत दनकुनी से होगी। इसके बाद यह झारखंड और बिहार के खनिज-समृद्ध क्षेत्रों, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अंत में गुजरात तक जा सकता है। इस नए कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए गुजरात के सूरत तक जाने की योजना है, जिससे इसके मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी या पूर्वी हिस्सों से होकर गुजरने की प्रबल संभावना है। इस कॉरीडोर के मप्र से गुजरने पर मप्र के औद्योगिक क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसमें मंडीदीप और पीथमपुर सबसे ज्यादा लाभांवित हो सकते हैं।

नई ट्रेनें और कनेक्टिविटी

- **नागपुर-शहडोल डेली ट्रेन:** विंध्य और महाकौशल क्षेत्र को महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए एक नई दैनिक ट्रेन की घोषणा की गई है।
- **वंदे भारत स्लीपर:** मध्य प्रदेश के रूटों (जैसे भोपाल-दिल्ली और इंदौर-मुंबई) पर मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों को वंदे भारत स्लीपर संस्करणों में अपग्रेड करने का प्रावधान है।
- **हाई-स्पीड कॉरिडोर:** दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड कॉरिडोर की घोषणा का लाभ भी ग्वालियर और चंबल संभाग को बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगा।

परियोजनाओं को फंड

- **इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन:** इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण में तेजी लाने के लिए बजट आवंटित किया गया है।
- **रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन:** इस रूट को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **छोटा उदयपुर-धार लाइन:** आदिवासी अंचल को जोड़ने वाली इस लाइन के लिए भी बजट दिया गया है।

अमृत स्टेशन योजना से जुड़ेंगे 53 रेलवे स्टेशन

मध्य प्रदेश के 53 छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों के लिए 214 करोड़ के विशेष फंड का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, सूखी सेवनिया, सलामतपुर जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर आधुनिक कवर्ड शेड्स बनाए जाएंगे ताकि यात्रियों को धूप और बारिश से राहत मिले, साथ ही प्लेटफॉर्म्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं

- माल की तेज आवाजाही, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, और पूर्व से पश्चिम के बीच औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
- यह खनिज-समृद्ध पूर्वी भारत को गुजरात के हीरा, कपड़ा और बंदरगाह-आधारित उद्योगों से जोड़ेगा।

आधुनिक तकनीकों को अपनाना समय की जरूरत

सूक्ष्म सिंचाई के साथ सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली पर कार्यशाला

एजुकेशन रिपोर्टर, भोपाल। प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और किसानों का सशक्तिकरण राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता और बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यकता बन गई है। उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भोपाल स्थित प्रमुख उद्यान (गुलाब गार्डन) में राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री कुशवाह ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के साथ जल और उर्वरक के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है यह समय की मांग है। किसान इसको अपनाकर उच्च गुणवत्ता की खेती कर सकते है। उद्यानिकी सचिव जॉन किंग्सली ने बताया कि प्रणाली के माध्यम से पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संतुलित मात्रा में पानी और उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे न केवल जल और उर्वरकों की बचत होती है, बल्कि श्रम लागत में कमी, खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार भी संभव होता है। परिणामस्वरूप फसल की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि प्रदेश में योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत प्रति हितग्राही एक यूनिट का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक के पास न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर रकबा उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत होना अनिवार्य है। परियोजना के तहत भारत सरकार की एमआईडीएच योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हितग्राही निर्धारित इकाई लागत 4 लाख रुपये है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान हितग्राही कृषक को देय होगा। यह सहायता सीधे किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रदेश में 715 कृषकों के खेतों में स्थापित करने का लक्ष्य

उद्यानिकी आयुक्त अरविंद दुबे ने बताया कि सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को प्रदेश में 715 कृषकों के खेतों में स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 597 कृषकों के विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शेष पात्र कृषकों को भी योजना से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि योजना के सफल क्रियान्वयन में निचले स्तर पर कार्यरत अमला महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वही सीधे किसानों से संपर्क करता है। योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारियों, निर्माता कंपनियों और कृषकों के बीच समन्वय आवश्यक है। जिला अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में परियोजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा इच्छुक और पात्र कृषकों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएं। साथ ही किसानों के आवेदन विभागीय पोर्टल पर समय पर दर्ज कराए जाएं।

सरकारी अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष: मुख्यमंत्री

गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन कार्यक्रम

विशेष संवाददाता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में बन रहे सभी शासकीय चिकित्सालयों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होंने कहा कि सनातन व्यवस्था के संस्कार जीवन को संतुलित, स्वस्थ और मूल्यवान बनाने की वैज्ञानिक पद्धति है। सीएम रविवार को इंदौर के कॉलेज में गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में परंपरा और विज्ञान कभी अलग-अलग नहीं रहे। सनातन व्यवस्था के संस्कार केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और मूल्यवान बनाने की वैज्ञानिक पद्धति है। गर्भ में पल रहे शिशु को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संस्कारित करना ही गर्भ संस्कार है। सरकार द्वारा जल्द ही विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृत्व केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, गर्भ शरीर निर्माण के साथ संस्कार की पहली पाठशाला भी है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि 5-6 महीने से ही बच्चे पर मां की भावनाओं और बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। महाभारत में अभिमन्यु तथा अन्य पौराणिक संदर्भ देखते हुए सीएम ने कहा कि हमारे पूर्वज मानसिक और भावनात्मक विकास की गहरी समझ रखते थे। आयुर्वेद की सामर्थ्य सर्वविदित है। कोविड काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोविड से बचाव के लिए सभी चिकित्सा पद्धतियों ने आयुर्वेद की प्रक्रियाओं अपनाया। आयुर्वेद में गर्भ संस्कार के महत्व को स्वीकारा गया है। इस मौके पर अखिल भारतीय कार्यकारणी सदस्य भय्याजी जोशी ने कहा कि भारत का चिंतन विश्व को संचालित करने का नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने का है।

बजट — सत्ता पक्ष ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया तो विपक्ष ने नकारा

सत्ता की नजर में बजट विकासोन्मुखी, विपक्ष ने कहा- देश निराश

विसं, भोपाल। बजट पर मंत्रियों से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की नजर रही। सत्ता पक्ष के नेताओं ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया, तो विरोधी दलों के नेताओं ने कहा कि बजट ने देश को निराश किया है।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत -2047 के दृष्टिकोण को नई गति देगा। बजट में समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण और पंच प्राण के सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया है। शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। इससे बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत बायोलॉजिक व बायोसिमिलर दवाओं में आत्मनिर्भर बनेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बजट में बेटियों से लेकर शहरों तक विकास की सौगात दी गई है। बजट महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देना सरकार की संवेदनशील एवं दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आम बजट को जनता को समर्पित, विकासोन्मुख और समावेशी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यप्रदेश को मिली सौगातें राज्य के शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। राजपूत ने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास हेतु किए गए बड़े आवंटन से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर जैसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं, रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग, सभी को राहत देने वाला है। बजट में मध्यप्रदेश को मिली सौगातें रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को मजबूती देने वाला, परिपूर्ण और नए आयाम स्थापित करने वाला है। यह बजट आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के संकल्प के साथ देश के हर वर्ग के कल्याण, संरक्षण और सर्वांगीण विकास की स्पष्ट दिशा देता है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि यह बजट विकास और जनकल्याण को समर्पित है। बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को लाभ पहुँचाने का स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिससे मध्यप्रदेश को व्यापक लाभ मिलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केन्द्रीय बजट आने वाले 10 वर्षो में भारत के विकास की दिशा तय करेगा। भारत को दुनिया के नक्शे पर अग्रणी देश बनना है,तो हमें उन सभी क्षेत्रों में ध्यान देना होगा,जहां आज अमेरिका और चीन आगे है। बजट में रेयर अर्थ सहित उन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है.जिनसे भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके।

मंदी और छलावे का बजट : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आम बजट को मंदी और छलावे का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तविक आर्थिक स्थिति से आंख मूंदने वाला और केवल आंकड़ो की बाजीगरी पर आधारित है। वित्त मंत्री ने गिरते रुपए,विदेश निवेश के लगातार बाहर जाने,निजी निवेश की कमी और आर्थिक मंदी जैसे गंभीर विषयों पर एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा। उन्होंने कहा बजट कटौती के सहारे गढ़ा गया है।

बजट खोखले वादे का दस्तावेज: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बजट किसानों, युवाओं, मजदूरों और मध्यम वर्ग की उम्मीदों को पूरी तरह से नजरांदाज करता है। बजट सिर्फ भाषणों और खोखले वादों का दस्तावेज बनकर रह गया। प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है।

जुमलों का पुलिंदा है: पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि केन्द्र का बजट पूरी तरह से जुमलों और घोषणाओं का पुलिंदा साबित हुआ है। किसान,महिलाएं,युवा इस बजट से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है। न तो एमएसपी की कानूनी गारंटी है और न ही बढ़ती लागत व प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों के लिए कोई ठोस राहत ही इस बजट में दी गई है। रोजगार सृजन के लिए बड़ी-बड़ी बाते कही जाती है,लेकिन जमीनी स्तर पर नौकरियां कहां से आएंगी,इसका कोई जवाब नहीं है।

अमीरों के लिए है बजट: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मध्यप्रदेश राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि यह बजट अमीरों और कारपोरेट के लिए है। मेहनतकश वर्गो,मजदूरों और किसानों के हितों को दरकिनार किया गया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर किसानों को फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम देने और खरीदी निर्धारित एमएसपी पर सुनिश्चित करने की बात को भूलकर सरकार ने कृषि और मंडी व्यवस्था को ही कारपोरेट कंपनियों को सौंपने के इरादे जाहिर कर दिए है।

विकासशील रोडमैप है: सीआईआई मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष और आईसेक्ट समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी का कहना है कि केन्द्रीय बजट विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरुप एक दूरदर्शी और विकासोन्मुख रोडमैप प्रस्तुत करता है। एमएसएमई, रोजगार सृजन, कौशल विकास और बेहतर ऋण उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर,लॉजिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजबूत आधार मौजूद है।

संस्थापक : गुरुदेव गुप्त

संपादकीय

आर्थिक नींव मजबूत करने पर केंद्रित बजट

यह बजट भविष्य का है। हर क्षेत्र में की गई घोषणाओं का असर आने वाले एक से डेढ़ दशक में दिखाई देगा। सरकार ने बुनियादी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक ठोस बजट देने की कोशिश की है।

सरकार के अनुसार विकसित भारत 2047 की आर्थिक नींव मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें तत्काल नकद राहत की बजाय औद्योगिक क्षमता, अवसंरचना, रोजगार-योग्यता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक पूंजी व्यय, निर्यात-उन्मुख उद्योगों, सेवा क्षेत्र और कर प्रशासन सुधारों को एक साथ आगे बढ़ाया गया है। यह बजट आपूर्ति-पक्ष सुधारों पर आधारित है, जिससे मध्यम अवधि में स्थिर विकास का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी टैरिफ, सख्त नियम और वैश्विक संरक्षणवाद के चलते भारत के वस्त्र निर्यात, खासकर रेडीमेड गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स, पर दबाव बढ़ा था। बजट में आधुनिक-पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टरों का विस्तार, चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के जरिए इस दबाव से निपटने की रणनीति सामने आई है। बजट का फोकस टैरिफ के असर को सीधे सब्सिडी से नहीं, बल्कि लागत घटाने, गुणवत्ता सुधारने और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के जरिए संतुलित करने पर है। बजट 2026 में चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर निर्यात के लिए कर-मुक्त इनपुट का दायरा बढ़ाया गया है, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियमों को सरल बनाया गया है। ये कदम निर्यात लागत घटाकर भारतीय उद्योगों को वैश्विक सप्लाई चेन में दोबारा प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश हैं।

एमएसएमई को चैंपियन के रूप में विकसित करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड और 2 हजार करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत फंड को जारी रखा गया है। यह बदलाव एमएसएमई को केवल छोटे उद्यम की श्रेणी में सीमित रखने के बजाय उन्हें स्केल-अप और निर्यात-योग्य इकाइयों में बदलने की दिशा में है।

बजट 2026 में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को एक साथ साधने की कोशिश की गई है। यह भारत को व्यावहारिक ग्रीन ट्रांजिशन की ओर ले जाने वाला बजट है, जिसमें बेस-लोड पावर को नजरअंदाज नहीं किया गया है। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति, विश्वविद्यालय टाउनशिप, एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब पर फोकस युवाओं को कौशल-आधारित कार्यबल के रूप में तैयार करने की नीति दिखाते हैं। प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर रोजगार-योग्यता बढ़ाने की दिशा में है। इससे डिग्री और नौकरी के बीच की संरचनात्मक खाई कुछ हद तक कम हो सकती है।

बजट में किसानों की आय बढ़ाने का फोकस उच्च मूल्य कृषि और बाजार से सीधे जुड़ाव पर रखा गया है। इस बजट का उद्देश्य किसानों की आय प्रति इकाई मूल्य बढ़ाकर बढ़ाना है। इससे मध्यम अवधि में किसानों की नकद आय में स्थिर और टिकाऊ वृद्धि दिखाई दे सकती है।

रक्षा क्षेत्र के लिए सीधा संदेश यह है कि भारत अब आयात-निर्भर सुरक्षा ढांचे से बाहर निकलकर घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना चाहता है। विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट तथा आवश्यक कच्चे माल के आयात पर शुल्क राहत इसी रणनीति का हिस्सा है। यह बजट खपत-आधारित राहत की बजाय आय-सृजन आधारित विकास पर भरोसा करता है, जिसका लाभ मध्यम और निम्न आय वर्ग को समय के साथ मिलेगा।

एक दिशा-निर्देशक और संरचनात्मक बजट है। यह वैश्विक टैरिफ दबाव, घरेलू रोजगार की जरूरत और 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को एक साथ साधने की कोशिश करता है। यह बजट तात्कालिक राहत से अधिक भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने पर केंद्रित है।

बजट 2026

कम राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार को बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा

देश को कर्ज से बाहर निकालने की पहल

विनोद पाठक

वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर लाकर एक कड़ा संदेश दिया कि वह देश को कर्ज के जाल से बाहर निकालना चाहती हैं। कम घाटे का अर्थ है कि सरकार को बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब अपना 9वां बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि क्या सरकार आगामी विधानसभा चुनावों या वैश्विक मंदी की आहट के बीच कोई बड़ा धमाका करेगी, लेकिन डेढ़ घंटे के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वित्तमंत्री ने लोकलुभावन के बजाय बचत का रास्ता चुना। राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर सीमित रखना बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन शेयर बाजार की मायूसी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या देश की वित्तीय सेहत सुधारने की कवायद में हम विकास की रफ्तार को नजरअंदाज कर रहे हैं?

वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर लाकर एक कड़ा संदेश दिया कि वह देश को कर्ज के जाल से बाहर निकालना चाहती हैं। कम घाटे का अर्थ है कि सरकार को बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा। इससे निजी क्षेत्र के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ेगी और ब्याज दरों में गिरावट की संभावना बनेगी। यह वैश्विक रेटिंग एजेंसियों, जैसे मूडीज और फिच को सकारात्मक संकेत देता है, जिससे विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि, इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि घाटे को कम करने के लिए सरकार को अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी है। यही वह बिंदु है, जहां बाजार और सरकार के हित आपस में टकरा रहे हैं।

वित्तमंत्री से शेयर बाजार को उम्मीद थी कि वो अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाएंगी, लेकिन बजट ने इसके उल्ट काम किया। बाजार की निराशा के तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखने को मिली थी। इस बार इसे केवल 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। निवेशकों को डर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश कम होने से सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक कंपनियों की ग्रोथ सुस्त पड़ जाएगी। दूसरा, मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी के लिए किसी बड़ी टैक्स कटौती या नकद हस्तांतरण की अनुपस्थिति ने बाजार को चौंका दिया। बाजार का मानना है कि जब तक आम आदमी की जेब में अतिरिक्त पैसा नहीं आएगा, तब तक ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में मांग नहीं बढ़ेगी। तीसरा, बाजार किसी बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की उम्मीद कर रहा था, जैसे कि विनिवेश का नया लक्ष्य या बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण की स्पष्ट समय सीमा। इन पर चुप्पी ने निवेशकों को मुनाफावसूली के लिए उकसाया।

वित्तमंत्री ने नए इनकम टैक्स कानून के जरिए जटिलताओं को कम करने का प्रयास तो किया है, लेकिन करदाताओं के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मामूली बढ़ोतरी और स्लैब में छोटे बदलावों को बाजार ने अपर्याप्त माना।

बजट 2026 में टैक्स स्लैब का निर्धारण इस तरह किया गया है कि मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ मिले। पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि रु9 लाख से रु15 लाख के बीच की आय वाले लोग सबसे अधिक कर के बोझ तले दबे महसूस करते थे।

नए प्रावधानों के तहत दरों को इस तरह पुनर्गठित किया गया है कि इस आय वर्ग के लोगों के टैक्स लायबिलिटी में 10 से 15 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है। तथ्यात्मक रूप से देखें तो, स्लैब की चौड़ाई बढ़ाने से रु10 लाख की आय वाले व्यक्ति को अब पुरानी दरों के मुकाबले प्रभावी रूप से लगभग रु15,000 से रु20,000 तक की वार्षिक बचत हो सकती है। यह राशि सीधे तौर पर मध्यम वर्ग की परचेजिंग पावर को बढ़ाती है। सरकार का यह कदम आर्थिक सुस्ती के समय में डिमांड-साइड इकोनॉमिक्स को मजबूती देता है, क्योंकि हाथ में अतिरिक्त पैसा होने पर मध्यम वर्ग ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेज और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश करता है।

निवेशकों को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कुछ राहत मिल सकती है, जो नहीं मिली। हालांकि, वित्त मंत्री का बचाव यह हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों के बीच बड़ी घोषणाएं करना जोखिम भरा हो सकता था। सरकार ने भविष्य के लिए बफर (सुरक्षित कोष) रखने की नीति अपनाई है। 4.4 प्रतिशत का घाटा घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।

नीति आयोग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट युवाओं को पारंपरिक सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरियों से आगे बढ़ाकर हेल्थ-केयर, क्रिएटिव इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर में अवसर देने की तैयारी है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास विश्वविद्यालय टाउनशिप, प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर छात्रों की रोजगार-योग्यता बढ़ाने की दिशा में है। शिक्षा नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे डिग्री और नौकरी के बीच की संरचनात्मक खाई कुछ हद तक कम हो सकती है।

बजट में कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। जैसे, क्या 10 प्रतिशत की कैपेक्स वृद्धि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है? क्या राजकोषीय अनुशासन के नाम पर ग्रामीण भारत की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है?

कुल मिलाकर, बजट एक यथास्थिति वाला बजट है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है, जो वित्तीय स्थिरता और कम मुद्रास्फीति चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए निराशाजनक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में रॉकेट जैसी रफ्तार देखना चाहते थे। बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया भले नकारात्मक है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से 4.4 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था की साख को वैश्विक पटल पर मजबूत करेगा। अब गेंद निजी क्षेत्र के पाले में है, क्या वे सरकार द्वारा छोड़े गए क्रेडिट स्पेस का लाभ उठाकर निवेश बढ़ाएंगे?

अब समय आ गया है कि बजट घोषणाओं की सूची से आगे बढ़कर परिणामों की जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि आखिरकार, बजट कोई लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश के नागरिकों से किया गया सबसे बड़ा सामाजिक अनुबंध होता है।

खुला मंच

रात ट्रंप मेरे सपने में आए....

गुरमीत बेदी

सपने देखना मेरी पुरानी आदत है। मैं रात को तो सपने देखता ही हूं, दिन में भी उठते बैठते सपनों की दुनिया में खो जाता हूं। पत्नी भी सपने को रिकॉर्ड करने की ताकत नहीं रखती। इस बार सपने में ट्रंप से मुलाकात हो गई। मैंने सपने में ट्रंप से हाथ भी मिलाया और उनसे कई गिले शिकवे भी किए। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनता देखने के लिए हमारे इंडिया में कई जगह हवन और अनुष्ठान भी किए गए थे। इसलिए किए गए थे कि आप इंडिया वालों को बहुत बड़ी राहत देंगे। जमकर तोहफे देंगे। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। हमारी गरीबी दूर कर देंगे। हमारे लिए अमेरिका में नौकरियों के दरवाजे खोल देंगे। हम दौड़े चले आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा जीतने के बाद आपने हमें आंखें दिखाना शुरू कर दी। ट्रंप मेरी बात सुनकर वैसे ही मुस्कुराए जैसे नेता चुनाव के बाद जनता को देखकर मुस्कुराते हैं- मतलब मुस्कान में दांत ज्यादा, सच्चाई कम। बोले, 'गुरमीत, पॉलिटिक्स में वादे सच करने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए होते हैं।' मैंने कहा, 'तो फिर हमारे यहां जो पंडितों ने आपके लिए हवन किए थे, उनका क्या? घी, लकड़ी, नारियल सब फूंका गया।

कम से कम उसका जीएसटी ही लौटा देते!' वो बोले, 'हमारे यहां भी बहुत कुछ फूंका जाता है, फर्क बस इतना है कि हम उसे 'पॉलिसी' कह देते हैं।' मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, 'आपने वीजा सख्त कर दिए, नौकरियां बंद कर दीं, ऊपर से टैरिफ लगा दिए। हमारे कई हिंदुस्तानी वहां से डिपोर्ट कर दिए। हथकडियां पहनाकर उन्हें वापस इंडिया भेज दिया। हम पाकिस्तान की खटिया खड़ी करने लगे थे और तुमने अपनी टांग बीच में फंसा दी। क्या यह दोस्ती है?' ट्रंप ने कोट की जेब से कैलकुलेटर निकाला, कुछ बटन दबाए और बोले, 'दोस्ती दिल से होती है, व्यापार दिमाग से। हम दिल की सुनें तो अमेरिका दिवालिया हो जाए।'

इतने में मैंने देखा कि पीछे लंबी लाइन लगी थी, चीन रूस, यूरोप सब अपने-अपने शिकवे लेकर खड़े थे। मुझे लगा ये तो इंटरनेशनल शिकायत केंद्र है। मैंने आखिरी वार किया, 'कम से कम हमें इतना बता देते कि 'अच्छे दिन' का वीजा किस काउंटर से मिलता है?' ट्रंप ने कंधे उचकाए, 'अच्छे दिन हर देश खुद बनाता है, ।' इतना सुनते ही सपना हिलने लगा। पत्नी ने आवाज लगाई, 'उठिए जी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है।' मैं हड़बड़ाकर उठा। ट्रंप गायब, व्हाइट हाउस गायब, बस अपना रसोईघर मौजूद। तभी समझ आया- सपनों में राष्ट्रपति मिल जाते हैं, हकीकत में सिलेंडर ही सबसे बड़ा सुपर पावर होता है। अब सोच रहा हूं, अगली बार अगर सपना आया, तो ट्रंप से नहीं, सीधे भगवान से मिलूंगा। कम से कम वहां टैरिफ नहीं लगते।

प्रसंगवश

दवा कारोबार में बाधक नियमों को हटाने का प्रयास

सरकार ने अनुसंधान के लिए छोटी मात्रा में दवाएं बनाने के लिए जरूरी पारंपरिक, अनिवार्य परीक्षण लाइसेंसों को खत्म कर दिया है। यह कदम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कई बार लाचार बना देने वाली नियामक बाधाओं को हटाने की एक कोशिश है। यह फैसला कारोबार करना आसान बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है। औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियमावली, 2019 में इन संशोधनों का केंद्रीय तत्व यह है कि दवाओं के गैर-वाणिज्यिक निर्माण के लिए आवश्यक अनिवार्य लाइसेंस की जगह एक नयी प्रणाली ले रही है जिसमें बस पूर्व-सूचना देनी होगी। विकासकर्ता अब केंद्रीय औषधि मानक संगठन को ऑनलाइन, उसके 'सुगम पोर्टल' के जरिए सूचित करने के बाद अनुसंधान, परीक्षण, और विश्लेषण के लिए छोटी मात्रा में दवाएं निर्मित कर सकते हैं। एक बार 'इरादे की सूचना' ऑनलाइन स्वीकृत हो जाए तो कंपनी, सिर्फ अनुसंधान कार्य के लिए, दवा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। कोविड के बाद की दुनिया में, जहां अंतिम उपयोग के लिए दवा मुहैया कराने की गति अहम हो गयी है, सरकार का अनुमान है कि यह लाइसेंसिंग फैक्टर हटाने से दवा के विकास में लगने वाले समय में कम-से-कम तीन महीने की कटौती होगी। पोर्टल पर ऑनलाइन सूचित करने के बाद विनिर्दिष्ट कम-जोखिम वाले जैव-उपलब्धता और जैव-समतुल्यता अध्ययन भी किये जा सकते हैं। इसके अलावा, जिन श्रेणियों में अब भी लाइसेंस जरूरी है, जैसे कि उच्च-जोखिम वाली साइकोट्रोपिक या नार्कोटिक दवाएं, वैधानिक प्रसंस्करण समय घटाकर 90 से 45 दिन किया जायेगा। सभी निर्माताओं को नियमों के मुताबिक प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करने और दाखिल करने की जरूरत होगी।

'लाइसेंस राज' को हटाना हमेशा अच्छी खबर है। फार्मा अनुसंधान और विकास में बाधाओं को दूर करना उस देश के लिए शुभ संकेत है जो खुद को दुनिया की फार्मेसी के रूप में देखना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि कागजरहित, पूर्व सूचना देने की प्रणाली से, लाइसेंस की भौतिक प्रति का इंतजार करते हुए, बैठे-ठाले उंगलियां चटकाने में खर्च होने वाला समय घट जायेगा। स्वाभाविक रूप से, समय बचने का अर्थ है धन और जिंदगियां बचना। प्रयोगशाला से निकल कर मरीज तक दवा पहुंचने में लगने वाला समय घटाकर बेशुमार जिंदगियां बचायी जा सकती हैं और बहुत से लोगों की तकलीफ घटायी जा सकती है। हालांकि, सरकार गुणवत्ता नियंत्रण में गिरावट आने का खतरा टालने के लिए काम करे तो अच्छा रहेगा। उसे एक प्रणाली शुरू करनी चाहिए जिससे, सूचना मिलने के बाद, यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अच्छी निर्माण प्रथाओं (मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) का सख्ती से पालन हो। कोई दवा चाहे जितनी तेजी से उत्पादित हो, अगर उसमें गुणवत्ता की चूक है तो उसकी कीमत उस ब्लिस्टर के बराबर भी नहीं है जिसमें उसे पैक किया जाता है। दवाओं की खराब निगरानी, जैसा कि हालिया कफ सिरप संबंधी मौतों ने दिखाया, जानलेवा हो सकती है। अब ज्यादातर दवाओं के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सूचना देना काफी होगा. वहीं, हाई-रिस्क कैटेगरी की दवाओं पर ही लाइसेंस जरूरी रहेगा। यह प्रस्ताव कई मायने में अहम माना जा रहा है. इससे लाइसेंस की फाइलें लगभग 50 फीसद तक कम होंगी। नई दवाओं पर रिसर्च और ट्रायल जल्दी शुरू होंगे. साथ ही दवा मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से भारत दुनिया में दवाओं और क्लिनिकल रिसर्च का बड़ा केंद्र बनेगा और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।

स्टार्टअप नवाचार

अब केवल 'आइडिया' नहीं, बल्कि रेवेन्यू, कैश फ्लो और स्पष्ट बिज़नेस मॉडल मायने रखते हैं

परिपक्वता की ओर बढ़ रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम

डॉ शशांक द्विवेदी

साल 2025 स्टार्टअप की दुनिया में उत्साह से अधिक विवेक का वर्ष रहा। यह स्पष्ट हुआ कि स्टार्टअप्स का भविष्य केवल बड़ी वैल्यूएशन में नहीं, बल्कि टिकाऊ बिज़नेस और सामाजिक प्रभाव में है। वहीं भारत ने साबित किया कि उसका स्टार्टअप इकोसिस्टम अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है।

साल 2025 स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ, जहां केवल तेज़ ग्रोथ के बजाय टिकाऊ बिज़नेस मॉडल, मुनाफ़े और सामाजिक प्रभाव पर भी जोर दिया जाने लगा। अब स्टार्टअप्स को सफलता के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और सामाजिक योगदान की कसौटी पर भी परखा जाने लगा है। पिछले एक दशक की तुलना में 2025 को 'संयम और परिपक्वता' का वर्ष कहा जा सकता है- जहां दुनिया भर में स्टार्टअप्स की संख्या भले ही तेज़ी से न बढ़ी हो, लेकिन जो स्टार्टअप टिके, वे अधिक मज़बूत और व्यावहारिक साबित हुए।

वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप गतिविधियां अधिक यथार्थवादी रहीं। दुनियाभर में हजारों नए स्टार्टअप सामने आए, लेकिन निवेशकों और बाज़ार का रुख साफ़ था- अब केवल 'आइडिया' नहीं, बल्कि रेवेन्यू, कैश फ्लो और स्पष्ट बिज़नेस मॉडल मायने रखते हैं। कोरोना काल के बाद स्टार्टअप्स में निवेश एक तरह की दौड़ बन गया था, वहीं 2025 में फंडिंग अपेक्षाकृत चयनात्मक रही। अमेरिका, यूरोप और एशिया में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स ने खुद को पुनर्गठित किया, कई का विलय हुआ और कुछ बाज़ार से बाहर भी हो गए। वैश्विक स्तर पर अनुमान लगाया जाता है कि 2025 में लाखों नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए, लेकिन उनमें से एक सीमित प्रतिशत ही वास्तव में 'सफल' कहलाने योग्य रहे-यानी जिन्होंने स्थिर राजस्व, विस्तार या लाभप्रदता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए। वर्ष 2025 में सफलता की परिभाषा बदल गई। पहले जहां यूनिकॉर्न बनना ही सफलता का प्रतीक माना जाता था, वहीं अब सस्टेनेबल ग्रोथ, मुनाफ़ा और दीर्घकालिक टिकाव को अधिक महत्व दिया जाने लगा। टेक्नोलॉजी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, हेल्थटेक, क्लाइमेट टेक, फिनटेक और डीप-टेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, केवल उपभोक्ता छूट और तेज़ विस्तार पर आधारित कई मॉडल कसौटी पर खरे नहीं उतरे।

भारत 2025 में भी दुनिया के सबसे सक्रिय स्टार्टअप देशों में शामिल रहा। देश में लगभग 22,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए- जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है और उद्यमशीलता की गति स्पष्ट करता है। हालांकि, बीता वर्ष भारत के लिए भी 'छंटाई' का वर्ष रहा- स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, लेकिन गुणवत्ता व फोकस में सुधार दिखा। कई स्टार्टअप्स ने आक्रामक विस्तार के बजाय लागत नियंत्रण, स्थानीय बाज़ार और मुनाफ़े पर ध्यान दिया। साल 2025 में भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में एक सीमित हिस्सा ही बड़े पैमाने पर सफल हुआ। कुछ स्टार्टअप्स ने मुनाफ़े की दिशा में कदम बढ़ाए, कई का विलय या अधिग्रहण हुआ और कुछ बाज़ार की वास्तविकताओं के सामने टिक नहीं पाए। यह स्थिति नकारात्मक नहीं, बल्कि स्वस्थ इकोसिस्टम का संकेत है, जहां अव्यावहारिक मॉडल खुद ही बाहर हो जाते हैं।

2025 में वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में भारत की स्थिति तीसरे या चौथे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में बनी रही। अमेरिका और चीन के बाद भारत को अक्सर यूरोप के साथ तुलना में रखा जाने लगा। भारत ने लगभग 125 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाए (स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू .1 बिलियन से अधिक है)। इनमें से कई ने इस वर्ष यह मुकाम हासिल किया और ग्रोथ जारी रखी।

भारत की खासियत रही कि वह केवल उपभोक्ता बाज़ार नहीं, बल्कि नवाचार और स्केल- दोनों का केंद्र बन रहा है। भारतीय स्टार्टअप्स अब केवल घरेलू नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भी लक्ष्य बना रहे हैं। हालांकि, पूंजी की उपलब्धता, गहन तकनीकी अनुसंधान और वैश्विक ब्रांड निर्माण के मामले में भारत अभी विकसित देशों से पीछे है। 2025 में स्टार्टअप निवेशकों का व्यवहार बदला हुआ दिखा। 'ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट' की जगह 'सस्टेनेबल रिटर्न' निवेश का मंत्र बना। भारत में शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को अपेक्षाकृत समर्थन मिला, लेकिन बड़े फंडिंग राउंड्स की संख्या सीमित रही। इससे स्टार्टअप्स को अपने खर्च और रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। भारत में तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग माहौल चुनौतीपूर्ण रहा। कुल इक्विटी फंडिंग पिछले साल के मुकाबले लगभग .10.5 बिलियन तक गिर गई। यह संकेत है कि निवेशक अब और अधिक सावधानी से धन लगा रहे हैं और केवल 'स्पष्ट प्रगति वाला मॉडल' ही पूंजी आकर्षित कर पा रहा है।

2025 ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सामने कई संरचनात्मक चुनौतियां हैं। वैश्विक अनिश्चितता का सीधा असर भारतीय स्टार्टअप फंडिंग पर पड़ता है। मसलन भारत में अब भी उपभोक्ता-आधारित स्टार्टअप्स की संख्या अधिक है, जबकि गहरे तकनीकी नवाचार की कमी महसूस की जाती है। टैक्स, अनुपालन और राज्यों के बीच अलग-अलग नियम कई स्टार्टअप्स के लिए बाधा बनते हैं। उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रबंधन प्रतिभा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता सीमित है।

साल 2025 स्टार्टअप की दुनिया में उत्साह से अधिक विवेक का वर्ष रहा। स्पष्ट हुआ कि स्टार्टअप्स का भविष्य केवल बड़ी वैल्यूएशन में नहीं, बल्कि समस्या समाधान, टिकाऊ बिज़नेस और सामाजिक प्रभाव में निहित है।

भारत ने 2025 में साबित किया कि उसका स्टार्टअप इकोसिस्टम अब किशोरावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट है। यदि भारत पूंजी, नीति और कौशल के मोर्चे पर संतुलन बना पाया, तो कुछेक वर्षों में वह वैश्विक स्टार्टअप दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बनने के साथ ही दिशा देने वाला देश भी बन सकता है।

जीवन दर्शन

जिम्मेदारी दिखाकर रिश्तों में किया जा सकता है सुधार

व्यक्ति नार्सिसिस्ट, यानी आत्ममुग्ध है या नहीं, इसके लिए आप उससे शांत माहौल में इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यह शेर के पिंजरे में जाने जैसा भी हो सकता है। दशकों पहले, नार्सिसिज्म या आत्ममुग्ध शब्द का इस्तेमाल नैदानिक परिवेश व शोध अध्ययन के कमरे के बाहर शायद ही कभी किया जाता था। लेकिन आज, यह पसंद न आने वाले या परेशान करने वाले कई तरह के व्यवहारों के लिए एक सामान्य संकेत बन गया है। मिशिगन में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर वर्जिल जिग्लर-हिल कहती हैं कि नार्सिसिस्ट वह व्यक्ति होता है, जिसे खुद को विशेष और अलग महसूस करने की तीव्र इच्छा होती है। इसमें कुछ लोग अहंकारी, आत्मकेंद्रित और प्रशंसा की तलाश में रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उनमें नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (एनपीडी) है। एनपीडी एक गंभीर स्थिति है, जिसके लिए विशेष चिकित्सकीय मापदंड होते हैं, जैसे लगातार आत्म-महत्व की भावना व दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी और लगातार प्रशंसा की आवश्यकता। विशेषज्ञ बताते हैं कि नार्सिसिज्म केवल एक मानसिक विकार नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तित्व की विशेषता है, जो अलग-अलग लोगों में भिन्न-भिन्न स्तर पर हो सकती है। नार्सिसिज्म को लेकर कई मिथक मौजूद हैं। पहला, जिनमें एनपीडी होता है, वे बेहद हानिकारक होते हैं। दूसरा, सभी नार्सिसिस्ट समान होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एजेंटिक नार्सिसिस्ट आत्मविश्वासी व महत्वाकांक्षी होते हैं। न्यूरोटिक नार्सिसिस्ट लगातार मान्यता की तलाश में रहते हैं और आलोचना से असुरक्षित महसूस करते हैं। एंटागोनिस्टिक नार्सिसिस्ट प्रतिस्पर्धी व कभी-कभी दूसरों को नीचा दिखाने वाले होते हैं। बर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उलरिच ऑर्थ कहती हैं कि नार्सिसिस्ट कोई स्थिर गुण नहीं है। यह वयस्क होने के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है, क्योंकि जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, सहानुभूति बढ़ती जाती है। डॉ. जिग्लर-हिल कहती हैं कि एजेंटिक या विरोधी नार्सिसिस्टिक आदतों वाले लोग अक्सर मदद लेने से कतराते हैं, क्योंकि वे इसकी जरूरत महसूस नहीं करते, या इलाज को कमजोरी का संकेत मान लेते हैं। वह कहती हैं कि माता-पिता जब अपने किसी एक बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो दूसरे बच्चे में नार्सिसिस्ट लक्षणों के विकास की संभावना बढ़ जाती है।

व्यक्ति नार्सिसिस्ट है या नहीं, यह जानने के लिए आप शांत माहौल में उससे उसकी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉ. दुर्वासुला इसे 'शेर के पिंजरे में जाना' कहती हैं। वह कहती हैं कि जब नार्सिसिस्ट जिम्मेदारी दिखाते हैं, तब रिश्तों में सुधार और व्यक्तिगत विकास संभव है।

क्रिस्टीना कैरन

॥ गीता ज्ञान ॥

श्लोक

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात॥

भावार्थ

इस योगमार्ग में किया गया थोड़ा भी प्रयास नष्ट नहीं होता और न ही इसमें कोई पाप का दोष है। यह थोड़ा-सा भी धर्म, महान भय (जन्म-मरण) से रक्षा करता है।

संक्षिप्त खबरें

एनएसएस शिविर में जल संरक्षण व डिजिटल जागरूकता पर गतिविधियां

एजुकेशन रिपोर्टर, भोपाल। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा विशेष शिविर के पंचम दिवस जनजागरूकता एवं बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रातःकालीन व्यायाम के बाद प्राचार्य डॉ. शालिनी सक्सेना के मार्गदर्शन में अनमोल एकेडमी में बच्चों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। बौद्धिक सत्र में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के डॉ. आशीष कुमार चांचौदिया ने डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सुरक्षा एवं तकनीक के सकारात्मक उपयोग पर मार्गदर्शन दिया। वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के सत्र में डॉ. वीपीएस गौर ने महात्मा गांधी के सेवा एवं नैतिक मूल्यों पर विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डॉ. राजेश श्रीवास्तव, सुषमा जैन एवं अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार डहारे ने आभार व्यक्त किया।

धर्म संस्कृति समिति का त्रैवार्षिक चुनाव निर्विरोध हुआ संपन्न

जागरण, भोपाल। धर्म संस्कृति समिति भोपाल के त्रैवार्षिक चुनाव विधायक विश्राम गृह मार्ग पर स्थित शुभ रेस्टोरेंट में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश शर्मा, चंद्रहास शुक्ल,दिनेश शर्मा पर्यवेक्षक ने प्राप्त चार पैनल पत्रक की मिलान कर एक पत्रक पैनल में अधिक समर्थक प्रस्तावक होने पर पदाधिकारियों की घोषणा की गई जिसमें अध्यक्ष भगवानदास सबनानी विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल ,कार्यकारी अध्यक्ष वैद्य डॉ.गोपाल दास मेहता,वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह चौहान, उपाध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला, महामंत्री अंकित शर्मा, संयुक्त महामंत्री योगेंद्र सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष नरेंद्र भानु खंडेलवाल, सह कोषाध्यक्ष निहाल साहू, संगठन सचिव डॉ मयंक चतुर्वेदी,कार्यालय सचिव गोलू सिंह जादौन, सचिव प्रचार दिनेश शर्मा, सचिव कार्यक्रम डॉ सूर्यभान गुर्जर, सहसचिव दिलीप चौरसिया, सहसचिव कु. हिमानी लोखंडे, कार्यकारिणी में पांच सदस्य बनाए गए। डॉ .दीपक रघुवंशी डॉ. शिवांशु गहरवार, डॉ दिव्या मंडलोई , डॉ दीपक मेहता,शुभम ठाकुर, राजेंद्र सोनी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए।

सिंधिया ने की हितानंद शर्मा से मुलाकात

भोपाल। केंद्रीय मंत्री च्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भोपाल प्रवास के दौरान आरएसएस मध्य क्षेत्र के सह-बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हितानन्द शर्मा से भेंट कर उनकी अस्वस्थ पूच्य माताजी के कुशल-क्षेम की आत्मीय जानकारी ली एवं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा उत्तम आरोग्य की कामना की।

दान के नाम पर सायबर फ्रॉड, ट्रस्ट अध्यक्ष और सहायक को भोपाल बुलाया, होटल में बंधक बनाकर की मारपीट

अंतरराज्यीय गिरोह के पांच आरोपी गिरफ्तार, मारपीट, अड़ीबाजी, बंधक समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज, बैंक अकाउंट की ले रहे थे जानकारी

क्राइम रिपोर्टर, भोपाल। दान के नाम पर सायबर फ्रॉड की घटना सामने आई है। अंतरराज्जीय गिरोह के पांच सदस्यों ने ट्रस्ट अध्यक्ष और उसके सहयोगी को बहाने से भोपाल बुलाया। इसके बाद एक होटल में बंधक बना लिया। आरोपी उनके बैंक अकाउंट की जानकारी ले रहे थे। इससे पहले वह ठगी कर पाते, ईंटखेड़ी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मारपीट, अड़ीबाजी, बंधक समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जीएट कंपनी का मैनेजर बनकर किया कॉल: ईंटखेड़ी पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर शनिवार रात मारूति पैलेस होटल में छापामार कार्रवाई की थी। जहां 62 वर्षीय ओमप्रकाश वर्मा निवासी ग्राम परसन का पुरा, थाना इब्राहिमपुर, जिला अम्बेडकर नगर यूपी मिले। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह राष्ट्र रक्षा मंच (ट्रस्ट) के अध्यक्ष हैं। 16 जनवरी को उनके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति द्वारा ने कॉल किया। कॉलर ने खुद को जीएट कंपनी का मैनेजर बताया। कॉलर ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से आपके ट्रस्ट की जानकारी मिली है। वह ट्रस्ट में दान देना चाहता था। इसके लिए उसने भोपाल बुलाया। 26 जनवरी को ओमप्रकाश अपने सहयोगी सुखदेव वर्मा के साथ भोपाल पहुंचे। स्टेशन के पास बजरिया इलाके में स्थित एक लॉज में ठहरे।

मारपीट कर ली बैंक खातों की जानकारी

आरोपियों ने दानकर्ता से मिलवाने के बहाने 27 जनवरी से 30 जनवरी तक ओमप्रकाश को आरकुस होटल कोलार में रुकवाया गया। 30 जनवरी को होटल से मनीष पटेल, सनित पटेल, जितेन्द्र पटेल एवं रविंद्र नामक व्यक्ति अपने साथ मारूति पैलेस होटल ईंटखेड़ी में ले आए और दो रूम में ठहरा दिया। वह स्वयं भी यहीं रुके। बताया कि दानकर्ता सुबह आएगा। सुबह दानकर्ता के नहीं आने पर जब ओमप्रकाश ने होटल छोड़ने की बात कही, तो आरोपियों द्वारा गाली-गलौच की गई। स्वयं को सायबर फ्रॉड करने वाला बताते हुए 10 हजार रुपए एवं ट्रस्ट के नाम से यूनियन बैंक खाते की जानकारी जबरन मांगने लगे। जानकारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने ओमप्रकाश को होटल के कमरे में बंद कर मनीष पटेल ने मारपीट की। इसके बाद उनके अन्य साथी सत्यम, तनिष्क एवं चरनप्रीत सरदार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने खाते बेचने एवं संचालित करने की बात कहते हुए ओमप्रकाश के बैंक खाते की जानकारी हासिल करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अन्य राज्यों में 31 सायबर फ्रॉड की शिकायत

पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मनीष पटेल के पैन कार्ड आधार पर दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कुल 31 सायबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज होना बताया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। जहां उनसे सायबर फ्रॉड नेटवर्क और पूर्व आपराधिक रिकार्ड की जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस ने इन्हें किया गिरफ्तार

- मनीष पटेल (37) पिता टीकाराम निवासी दृष्टि सिटी, कोलार।
- जितेन्द्र पटेल (27) पिता शिवप्रसाद निवासी ग्राम मनगवा, महराजपुर, जिला छतरपुर।
- सत्यम उर्फ शरद बरगले (19) पिता बसंत निवासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, तीन मंदिर, इटारसी।
- तनिष्क अवस्थी (18) पिता सुशील कुमार निवासी निवासी सूरजगंज मोहल्ला, इटारसी।
- चरनप्रीत सिंह (26) पिता मुरप्रीत निवासी 220 रुचि लाइफ, जाटखेड़ी, मिसरोद।

हिस्ट्रीशीटर को हथौड़े से मारने वाले दो आरोपी हुए गिरफ्तार

जेल से छूटने के बाद अवैध माइनिंग को लेकर कोलार में हुई थी मारपीट

क्राइम रिपोर्टर, भोपाल। कोलार रोड इलाके में हिस्ट्रीशीटर को हथौड़े और सब्बल से मारकर अधमरा करने वाले दो आरोपियों को कोलार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीवा के चौरहटा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में मारपीट का काउंटर केस दर्ज है। जेल से छूटने के बाद हिस्ट्रीशीटर ने मारपीट की थी। बदला लेने के लिए अवैध माइनिंग खनन करने वाले सचिन कुशवाहा और उसके साथियों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से स्कॉर्पियो जब्त की है। शेष आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों की पहचान होने के बाद कोलार पुलिस की एक टीम रीवा में डेरा डाले थी। जैसे ही आरोपी अपने बिलों से निकले पुलिस की टीम ने उन्हें दबोच लिया। देर रात पुलिस दोनों को लेकर भोपाल पहुंची। कोलार पुलिस के मुताबिक, 25 जनवरी 2025 की सुबह लगभग दस बजे नेताजी चौराहे पर रीवा के चौरहटा निवासी कुलदीप पटेल उर्फ कुलदीप सिंह (40) पर आधा दर्जन बदमाशों ने हथौड़े और सब्बल से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में आरोपियों ने कुलदीप के हाथ-पैर व कमर की हड्डियां तोड़ दी थीं। वे दो बिना नंबर की स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ी से आए थे। बयान में कुलदीप ने सचिन कुशवाहा, अतुल तिवारी और कपि ध्वज के साथ रंजिश की बात कहते हुए संदेह जताया था। संदेहियों की भूमिका की जांच के लिए कोलार पुलिस की एक टीम संदेहियों की तलाश में रीवा रवाना हुई थी। टीम पांच दिन से रीवा में डेरा डाले हुए थी। रविवार शाम को टीम को सफलता मिली और दो आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

ये है पूरा मामला

अशुमित प्रताप सिंह (27) पिता ज्ञानेंद्र सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि वह सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और खेती किसानी करता है। हमले में घायल कुलदीप का रिश्तेदार हैं। वह और कुलदीप दोनों स्कॉर्पियो एमपी17 जेडएल 7711 से घटना के वक्त अकबरपुर स्थित कुलदीप की मंगेतर के क्लीनिक में जा रहे थे। तभी नेताजी कालोनी के चौराहे पर उनकी गाड़ी को बिना नंबर की स्कॉर्पियो और बोलेरो से आए बदमाशों ने घेर लिया था। इसके बाद जानलेवा हमला कर दिया। कुलदीप रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम धौचट में रहता है। कुलदीप दो महीना पूर्व ही भोपाल आया है। उसे हत्या के मामले में सजा हुई है। जिसमें उसे 10 सितंबर, 2025 को जमानत मिल गई थी।

मत पेटियों में कैद हुआ भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष का नाम, नतीजा आज

मतगणना के बाद घोषित होगा अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी के सदस्यों का नाम

जागरण संवाददाता, भोपाल। भोपाल में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हुई। बता दें कि इस दौरान संस्था के करीब 1917 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भावी अध्यक्ष व नई कार्यकारिणी के लिए वोट डाले। इसके साथ ही साथ ही 39 टेंडर वोट और 50 पोस्टल वोट भी डाले गए। पहली बार टेंडर वोटिंग के साथ मत पत्र में प्रत्याशियों के चित्र भी थे। चुनाव में उन्नति पैनल की ओर से व्यवसायी गोविंद गोयल अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर प्रगतिशील पैनल की ओर से तेजकुल पाल सिंह पाली अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। उन्नति पैनल में गोयल के अलावा, उपाध्यक्ष पद पर तीन, महामंत्री पद पर 1, मंत्री पद पर तीन, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद पर एक-एक पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी 17 सदस्य मैदान में हैं। वहीं प्रगतिशील पैनल में उपाध्यक्ष पद पर तीन, महामंत्री पद पर 1, मंत्री पद पर दो, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और अतिरिक्त कोषाध्यक्ष पद पर एक-एक पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के 21 सदस्य मैदान में हैं। बता दें कि भोपाल में चेंबर ऑफ कॉमर्स के 6 हजार से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन इनमें से 2200 सदस्य गतिविधि शुल्क जमा न होने के कारण मताधिकार से वंचित हैं। पूर्व अध्यक्ष पाली ने वादा किया है कि गतिविधि शुल्क को कम करना उनकी पहली प्राथमिकता है।

पीसी कोठारी के साथ मैदान में डटी रही 170 लोगों की टीम

शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मुख्य चुनाव पदाधिकारी अधिवक्ता पीसी कोठारी के साथ 170 लोगों की टीम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ मैदान में जुटी रही। इस दौरान सदस्यों की सुविधा के लिए पूरे शहर में 20 मतदान केंद्र बनाए गए थे। ताकि सदस्य समय पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस दौरान सभी सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी तरह के वाद विवाद की खबर सामने नहीं आई। शहर में भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के करीब 2236 सदस्य हैं, करीब 1917 सदस्यों ने ही मताधिकार का प्रयोग किया।

दोनों अध्यक्षों ने जीत के बाद काम कराने के किए दावे

रविवार का दिन होने के बाद भी चुनाव में भाग लेने के लिए दोपहर 2 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगना शुरू हो गई थी। इस दौरान उन्नति पैनल और प्रगतिशील पैनल के पक्ष में मताधिकारियों ने नारे भी लगाए। इस दौरान उन्नति पैनल के गोविंद गोयल ने बताया कि उनका पहला काम भोपाल के व्यापारियों के काम में आने वाली रुकावटों को दूर करना है। इसके अलावा भोपाल को राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। तेजकुल पाल सिंह पाली ने कहा कि लंबित कामों को पूरा करना और व्यापारियों से किए गए वादों को निभाना उनकी प्राथमिकता है।

छात्राओं पर कटर से हमला करने वाले सिरफिरे का 90 घंटे बाद भी सुराग नहीं

अयोध्या नगर और पिपलानी इलाके में हुई थी वारदात, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

जागरण,भोपाल। पिपलानी और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात 10.30 से 11 बजे के बीच एक सिरफिरे बाइक सवार युवक ने तीन छात्राओं पर कटर से जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। हमला करने वाला आरोपी अब भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच केवल सीसीटीवी फुटेज पर अटकी हुई है। पहली घटना गुरुवार रात करीब 10.30 बजे की है। जहां पिपलानी क्षेत्र स्थित सोनागिरी ए सेक्टर में 21 वर्षीय घर के पास खड़ी थी। इस दौरान बाइक सवार युवक ने कटरनुमा धारदार हथियार से युवती के पैर पर हमला कर फरार हो गया। जबकी दूसरी घटना बी सेक्टर में करीब 11 बजे की है। जहां 22 वर्षीय छात्रा का आरोपी ने बीच सड़क पर रास्ता रोककर उस पर हमला कर दिया। युवती ने जिस पहनी हुई जिसके चलते उसे पैर में केवल खरोचे आई है। ये दोनों लड़कियां आरोपी को नहीं पहचानती है। घटना को अंजाम देते समय आरोपी नशे की हालत में था। तीसरी घटना गुरुवार रात करीब 11.30 बजे वह नरेला जोड़ के पास हुई। जहां 21 वर्षीय युवती अपने घर जा रही थी। तभी बाइक सवार युवक ने उसके सामने बाइक रोककर कटर से हमला कर दिया। बचाव के दौरान युवती झुक गई, जिससे उसकी नाक पर चोट आई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इलाके में लगे सीसीटीवी फूटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

जनजातीय संग्रहालय में संभावना का आयोजन

जागरण, भोपाल। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित सांस्कृतिक श्रृंखला संभावना के अंतर्गत रविवार को लोक कलाओं का अनूठा समागम देखने को मिला। आयोजन में बुंदेलखंड के शौर्य और बघेलखंड के माधुर्य ने दर्शकों को अपनी लोक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया। सागर से आए अजय कुमार बेड़िया और उनके दल ने बुंदेली राई नृत्य की प्रस्तुति से सभागार में उर्जा भर दी। राई केवल एक मंचीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि ग्रामीण जनजीवन की प्रतिष्ठा का पर्याय है। श्रृंगार और लास्य के इस संगम में कलाकारों ने राई के दानों सी त्वरित गति और अंग-संचालन (फुटवर्क) से सबको चकित कर दिया। विवाह और जन्मोत्सव पर मनौती के रूप में किया जाने वाला यह नृत्य बुंदेली अस्मिता का प्रतीक बनकर उभरा।

50 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर से बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली सप्लाई

जागरण संवाददाता, भोपाल। भोपाल के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में 50 एमवीए क्षमता का एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने बगरोदा स्थित 132 केवी के सबस्टेशन में यह पावर ट्रांसफार्मर लगाया है, ताकि शटडाउन की स्थिति में पावर सप्लाई बंद होने की समस्या से निजात मिल सके। अब बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दो ट्रांसफार्मर होने से मेनटेनेन्स के लिए शटडाउन लेने की समस्या से भी निजाद मिली है। एमपी ट्रांसको भोपाल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रदीप राघव के अनुसार बगरोदा में दूसरे पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना से औद्योगिक केंद्र विकास निगम रामाखेड़ी, उमरावगंज, सोलर एनर्जी, दुर्गास्टील 33 केवी फीडरो से जुड़े उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। अब उन्हें बेहतर गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उचित वोल्टेज पर मिलेगी। इस क्षमता वृद्धि से बगरोदा सबस्टेशन की क्षमता बढ़कर 90 एमवीए की हो गई है। भोपाल जिले में एमपी ट्रांसको अपने कुल 18 एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशनों के माध्यम से विद्युत सप्लाई करती है, इसमें 400 केवी का एक, 220 केवी के 4, 132 केवी के 13 सबस्टेशन शामिल हैं।

निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन

जागरण, भोपाल। राजधानी के बरखेड़ा स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ में रविदास जयंती के अवसर पर 37वां निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस सामाजिक आयोजन में नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचार आज भी समाज को समानता, सामाजिक समरसता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने गुरु रविदास के आदर्शों को अपनाकर समाज में भाईचारे, सद्भाव और आपसी सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया।

बीएसएस कॉलेज ग्राउंड में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम

भोपाल। दुर्गा नगर स्थित बीएस कॉलेज ग्राउंड में चल रही देवी भागवत कथा में श्रद्धा और उल्लास के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जैसे ही कथा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का प्रसंग आया, पूरा पंडाल भक्ति और आनंद से गूंज उठा। कथा व्यास शशांक शेखर महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण के अवतरण की दिव्य कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। कथा के दौरान राधा रानी के पावन चरित्र और उनके निर्मल प्रेम का भी सुंदर वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। श्रीकृष्ण जन्म के समय पंडाल में जयकारों की गूंज सुनाई दी। भक्तों ने फूलों की वर्षा की, भजन-कीर्तन किए और एक-दूसरे को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, आष्टा, जिला-सीहोर, म.प्र.

कमांक / 2337 /राजस्व शा./न.पा./2026 आष्टा दिनांक 29.01.2026

—:: ई–निविदा फूड जोन एवं छत ऑफर सूचना (तृतीय) ::—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सपंत्ति का अंतरण) नियम 2016 एवं संशोधन के अंतर्गत वार्ड क. 16 में काला तालाब की पाल पर स्थित रिक्त भूमि में प्रस्तावित रेस्टोरेंट/फूड जोन हॉल निर्मित फूड जोन ऑफर एवं वार्ड क.18 कार्यालय नगर पालिका परिषद के सामने पुराना इंदौर भोपाल रोड़ भूतल पर स्थित दुकान की छत (क्षेत्रफल लगभग 73.00 वर्ग मी.) को 30 वर्ष की समयावधि हेतु लीज पर उच्चतम दर के आधार पर अपने ऑफर प्रस्तुत कर सकते है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

फूड जोन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऑनलाईन टेण्डर कमांक	फूड जोन का वर्ग	फूड जोन का साईज	अमानत राशि	ऑफसेट प्राईज (लाख में)	वार्षिक न्युनतम किराया	निविदा प्रपत्र की कीमत (प्रति दुकान)
1	2026_UAD_475823_1	अनारक्षित	77.80 वर्ग मीटर	182500/–	7300000/–	146000/–	10000रू. + जीएसटी

वार्ड क. 18 की दुकानों की छत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ऑनलाईन टेण्डर कमांक	आर.सी.सी.छत का क्षेत्रफल वर्ग मी.	अमानत राशि	ऑफसेट प्राईज (लाख में)	छत का वार्षिक किराया	निविदा प्रपत्र की कीमत (प्रति दुकान)
1	2026_UAD_475824_1	73.00 वर्ग मी.	36000/–	14,18,000/–	रू–29000/–	2000/–

शर्तेः–

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जायेगा।
2. इक्छुक कयकर्ता दिनांक 16.02.2026 को सायं 17.30 बजे तक अपनी अपनी निर्धारित अमानत राशि ऑनलाईन जमा कर निविदा में भाग ले सकते है।
3. फूड जोन की विस्तृत शर्ते/नियम कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर राजस्व शाखा में भी देखी जा सकती है।
4. निविदा प्रारूप राशि निर्धारित निविदा शुल्क जमा कर क्रय किये जा सकते है।
5. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा दर पर नियमानुसार जी.एस.टी. (वर्तमान में 18 प्रतिशत) पृथक से देय होगा।

विनोद कुमार प्रजापति, मुख्य न.पा. अधिकारी, न.पा.प. आष्टा
श्रीमती तारा कटारिया, सभापति, राजस्व शाखा, न.पा.आष्टा
सिद्धीका बी भूरू भाई, उपाध्यक्ष, न.पा.प. आष्टा
हेमकुंवर रायसिंह मेवाडा, अध्यक्ष, न.पा.प. आष्टा

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन
छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन
(Online) निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र./ शि.वि./2026/149 उज्जैन दिनांक :- 30-1-26

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र अ (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म. प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गर्वमेंट व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल के एस.ओ.आर. 02.08.2021 अनुसार सिरियल क्र. 1 का टेण्डर फार्म मूल्य 1000/- सिरियल क्र. 2 से 9 तक का टेण्डर फार्म मूल्य 2,000/- रहेगा।

सिरियल क्र. 1 से 9 तक का ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 16.02.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 10.02.2026 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 1 से 9 तक का की ऑनलाईन निविदा दिनांक 18.02.2026 समय 11:00 बजे खोली जायेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टम नी रू.	समयावधि
1	3	4	5	6	7
1	2025_UAD_454556_3	वार्ड क्र. 50 ऋषि नगर में क्रॉसड्रेन निर्माण।	102591/–	2060/–	30 दिन
2	2025_UAD_470222_2	वार्ड क्र. 46 अंतर्गत विभिन्न स्थानो पर पेवर ब्लॉक लगाने बाबत।	254000/–	2540/–	30 दिन
3	2024_UAD_333741_12	वार्ड क्र. 50 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण तथा मरम्मत कार्य।	677433/–	13550/–	30 दिन
4	2025_UAD_443670_4	ग्रैण्ड होटल परिसर के पीछे से मुख्यमार्ग तक नाली निर्माण कार्य।	1693783/–	5720/–	60 दिन
5	2025_UAD_466759_3	वार्ड क्र. 52 स्थित जिला पंचायत उज्जैन परिसर में टेकरेश्वर मंदिर के पास सभा मण्डप निर्माण।	847445/–	55650/–	90 दिन
6	2025_UAD_468799_2	वार्ड क्र. 44 स्थित अम्बेडकर मांगलिक भवन में आवश्यक संधारण कार्य।	1694657/–	12710/–	90 दिन
7	2026_UAD_478957_1	वार्ड क्र. 45 अंतर्गत शिवाजी पार्क, संत नगर, विद्या नगर में पेवर ब्लॉक निर्माण।	847532/–	8500/–	60 दिन
8	2026_UAD_478969_1	वार्ड क्र. 52 गांधीनगर सामुदायिक भवन में शेष विकास कार्य	701818/–	7020/–	60 दिन
9	2026_UAD_479094_1	वार्ड क्र. 42 अंतर्गत आनंद मंगल परिसर के कोने से अर्जुन नगर के नाले तक क्रॉसड्रेन निर्माण।	593280/–	5950/–	30 दिन

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन

करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने अल्काराज, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहली बार हारे जोकोविच

अल्काराज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जोकोविच के 25वें ग्रैंड स्लैम का सपना फिर टूटा

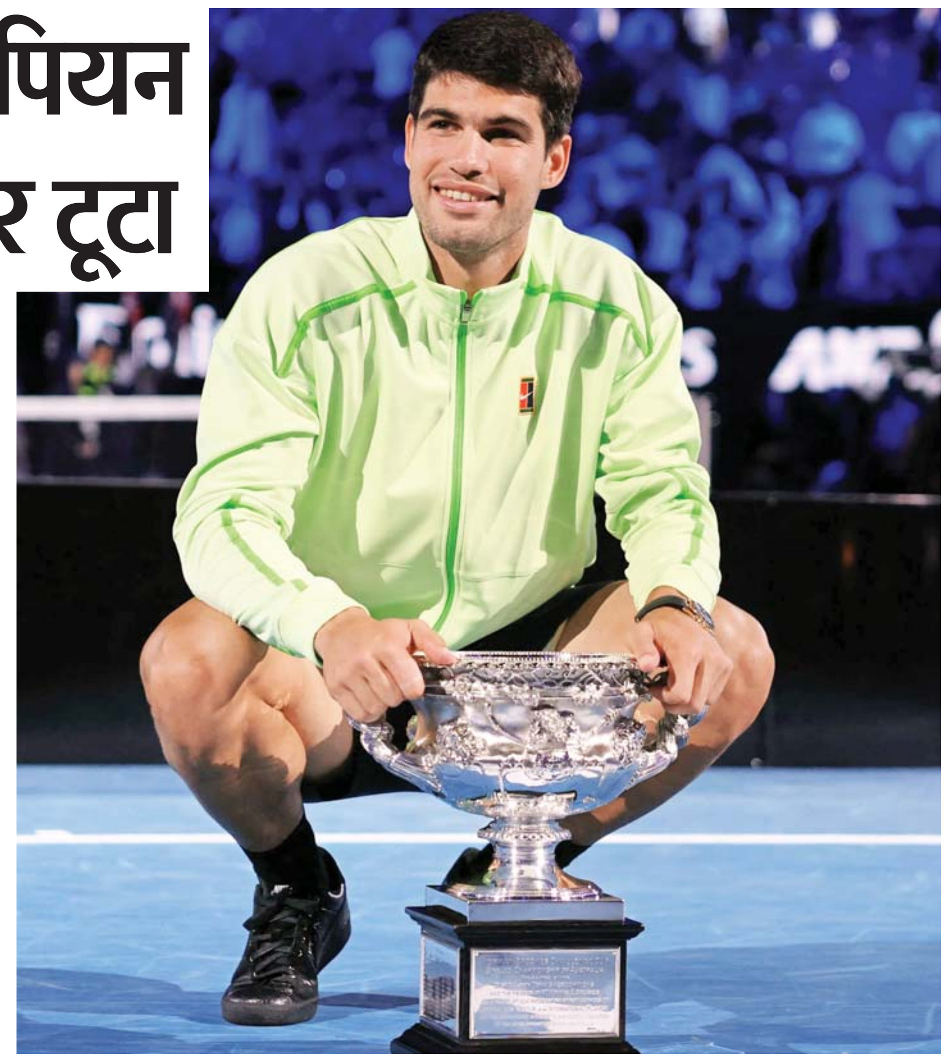

जेएनएन, मेलबर्न

कार्लोस अल्काराज रविवार को फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है, तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं। रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्काराज ने रविवार को पहला सेट गंवाया, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। 22 साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा।दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया।

कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया, जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा।

- जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्काराज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे, लेकिन अल्काराज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
- स्पेन के अल्काराज ने अब तक सात ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा दो-दो विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन शामिल हैं।
- ओपन एरा में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले अल्काराज पांचवें पुरुष खिलाड़ी बने। अल्काराज अब रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और आंद्रे अगासी जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं।

खेल एक नजर

गुकेश ने नीमैन को बराबरी पर रोका अब्दुसत्तोरोव ने खिताब की ओर

विज्क आन जी (नीदरलैंड), जेएनएन। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें चरण में रविवार को हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने मैथियास ब्लूबाउम पर दमदार जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रज्ञानानंदा के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया, जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। वह अपने हमवतन अब्दुसत्तोरोव से आधा अंक पीछे हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक दौर का खेल बचा है और उज्बेकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष दो स्थान के साथ साल के पहले सुपर-टूर्नामेंट में अपने देश का दबदबा कायम किया। नीमन, नीदरलैंड के जॉर्डन वान फोरेस्ट और जर्मनी के विंसेंट कीमर सात-सात अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

थाईलैंड मास्टर्स: देविका ने जीता अपना पहला सुपर 300 खिताब

बैंकॉक, जेएनएन। भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की 20 साल की देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में कोच उमेंद्र राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा की देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ अपने खेल को निखार रही हैं।

वेस्टइंडीज ने जीता तीसरा टी-20, दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की

जोहानिसबर्ग, जेएनएन। वेस्टइंडीज ने बारिश से प्रभावित तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर छह रन से हराकर विश्व कप से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। पहले दोनों मैच जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह से तीन मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। बारिश के कारण मैच लगभग दो घंटे देर से शुरू हुआ और इसे दोनों टीमों के लिए 16-16 ओवरों का कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जब छह ओवर में एक विकेट पर 66 रन बनाए थे, तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और बाद में इसे दोनों टीमों के लिए 10-10 ओवरों का कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने तीन विकेट पर 114 रन बनाए। उसकी तरफ से कप्तान शाई होप ने 25 गेंदों में 48 रन और शिमरोन हेटमायर ने 22 गेंदों में नाबाद 48 रन का योगदान दिया। इन दोनों ने मिलकर 10 छक्के जड़े। दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस पद्धति से 125 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन उसकी टीम छह विकेट पर 118 रन ही बना पाई। क्विंटन डीकॉक ने 14 गेंद पर 28 और जैसन स्मिथ ने 10 गेंद पर 26 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से गुडाकेश मोती ने 17 रन देकर तीन विकेट लिए।

अनाहत पहली बार पीएसए कांस्य स्तर की प्रतियोगिता के फाइनल में

नई दिल्ली, जेएनएन। भारत की अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में चल रहे स्क्वाश ऑन फायर ओपन में अमेरिका की सबरीना सोभी को 3-1 से हराकर पहली बार किसी पीएसए कांस्य स्तर की प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। विश्व

रैंकिंग में 31वें स्थान पर काबिज और इस टूर्नामेंट में सातवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अनाहत ने सेमीफाइनल में विश्व रैंकिंग में 23वें स्थान पर काबिज अमेरिकी खिलाड़ी सबरीना को 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 से हराया। फाइनल में अनाहत का सामना इंग्लैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज जॉर्जीना कैनेडी से होगा। अनाहत ने क्वार्टरफाइनल में मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त सना इब्राहिम को हराया था।

पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज कर भारत अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में

58 रन से जीती टीम इंडिया, अंतिम चार में सामना अफगानिस्तान से चार को

जेएनएन, बुलावायो

भारत ने अंडर-19 विश्व कप के सुपर सिक्स मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत के सामने चार फरवरी को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती होगी। दूसरे सेमीफाइनल में तीन फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने होंगे। प्लेयर ऑफ द मैच कनिष्क चौहान ने बल्ले से 29 गेंद में 35 रन की पारी खेलने के अलावा आठवें विकेट लिए खिलान पटेल (15 गेंद में 21 रन) के साथ 50 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की, जिससे टीम ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाए। पाकिस्तान को भारत से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 33.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था, लेकिन टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान ने 33.3 ओवर में चार विकेट पर 167 रन बनाए थे और फिर पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन पर आउट हो गई।

प्लेयर ऑफ द मैच : कनिष्क चौहान, 35 रन व 1 विकेट

कनिष्क ने 40 डॉट गेंद डाली

गेंदबाजी विभाग में कनिष्क ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर एक विकेट चटकाते हुए पाकिस्तान टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने इस दौरान 40 डॉट गेंदें डाली। पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के बीच बाएं हाथ के स्पिनर खिलान (9.2 ओवर में 35 रन देकर तीन विकेट) और कप्तान आयुष म्हात्रे (8 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट) ने भी बीच ओवरों में रन गति को पूरी तरह बांधे रखा। एशिया कप के नायक रहे पाकिस्तान के समीर मिन्हास को हेनिल पटेल ने शुरुआती ओवरों में ही अपनी ऑफ-कटर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद टीम के बल्लेबाजों ने बेहद रक्षात्मक रवैया अपना लिया।

वेदांत का अर्धशतक

एक समय पाकिस्तान ने भारत को 47 रन पर 3 और 200 रन पर 7 कर दिया था, लेकिन उन्हें वह छोटे स्कोर पर नहीं रोक पाए। वेदांत त्रिवेदी ने 98 गेंदों में 68 रन बनाकर भारत को संभाला और फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों कनिष्क चौहान (35 रन), आरएस अमब्रिश (29 रन) और खिलन पटेल (15 गेंदों में 21 रन) ने भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। कनिष्क और खिलान ने महज 5.1 ओवर में 50 रन जोड़े और पारी के अंत में तेजी से रन जुटाए। पाकिस्तान के लिए अब्दुल सुभान ने तीन, जबकि मोहम्मद सय्याम ने दो विकेट लिए।

रणजी ट्रॉफी: 42 बार की चैंपियन मुंबई, कर्नाटक व मप्र नॉकआउट में

कर्नाटक ने पंजाब को और मप्र ने महाराष्ट्र को हराया

मोहाली, जेएनएन। 42 बार की चैंपियन मुंबई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड और आंध्र ने रविवार को अपने-अपने मुकाबले जीतकर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान देवदत्त पडिक्कल (नाबाद 120 रन) की शतकीय पारी से कर्नाटक ने ग्रुप-बी के अपने आखिरी मैच में पंजाब को पांच विकेट से हराया। ग्रुप-बी से कर्नाटक (27 अंक) और मध्य प्रदेश (28 अंक) ने नॉकआउट में जगह बनाई। मध्य प्रदेश ने शनिवार को महाराष्ट्र को 133 रन से शिकस्त दी। मप्र का सामना क्वार्टर फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम से होगा। सौराष्ट्र (26 अंक) ने चंडीगढ़ के खिलाफ अपना मैच जीता, लेकिन कर्नाटक से एक अंक पीछे रह गया। मैच के आखिरी दिन कर्नाटक ने तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और श्रेयस गोपाल के तीन-तीन विकेट की बदौलत पंजाब को दूसरी पारी में 256 रन पर आउट कर दिया। कर्नाटक को अधिकतम 40 ओवर में 250 रन बनाने थे, लेकिन पडिक्कल के आठवें प्रथम श्रेणी शतक की बदौलत कर्नाटक ने 27.5 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में पडिक्कल ने नाबाद 120 रन की पारी खेली। जबकि अनुभवी मयंक अग्रवाल ने भी 36 गेंद में 53 रन बनाए। दोनों ने सिर्फ 12.3 ओवर में 117 रन जोड़े।

आयुष के शतक से दिल्ली ने मुकाबला ड्रॉ कराया

मुंबई, जेएनएन। दिल्ली ने एलीट ग्रुप-डी में तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ करा लिया। दिल्ली के कप्तान आयुष दोसेजा ने नाबाद 159 रन बनाए और मुंबई को जीत से दूर रखा। दोनों टीमों ने चाय के विश्राम से करीब आधा घंटा पहले मुकाबला बराबरी पर समाप्त करने पर सहमति जता दी। दिल्ली ने दूसरी पारी छह विकेट पर 407 रन बनाकर घोषित की। उस समय उसकी कुल बढ़त 311 रन की थी। दिल्ली ने पहली पारी में 96 रन से पिछड़ने के बाद पिछले दो दिनों में मुंबई को कड़ी चुनौती दी। दिल्ली आठ टीमों की ग्रुप तालिका में सातवें स्थान पर रही। जम्मू-कश्मीर ने हिमाचल के खिलाफ पहली पारी में 603 रन की बड़ी बढ़त से इस मैच में तीन अंक हासिल किए। जम्मू कश्मीर के 771 रन के जवाब में पहली पारी में 168 रन बनाने वाली हिमाचल की टीम ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 26 रन बना लिए थे, लेकिन बीती रात हुई बारिश के कारण चौथे दिन का खेल संभव नहीं हुआ। सोविमा में अपने अंतिम मैच में नगालैंड के खिलाफ ड्रॉ खेल आंध्र की टीम शीर्ष पर रही। नगालैंड ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 85 रन से आगे खेलते हुए 342 रन बनाए। आंध्र को 173 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम 8.3 ओवर में चार विकेट पर 64 रन बनाने के बाद मैच ड्रॉ कराने को राजी हो गई।

थाईलैंड को हराकर आयरलैंड ने किया 2026 महिला टी-20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई

काठमांडु, जेएनएन। आयरलैंड ने थाईलैंड को हराकर 2026 महिला टी-20 विश्व कप में जगह बना ली है। नेपाल में आयोजित क्वालिफायर के जरिए वह ऐसा करने वाली तीसरी टीम बनी है। वे जून-जुलाई में इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ शामिल हो चुकी हैं। थाईलैंड के खिलाफ आयरलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 121 रन बनाए। टीम को एमी हंटर (24), लुईस (25), और ओर्ला प्रींडरगास्ट (24) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। थाईलैंड की लेग स्पिनर सुलीपॉर्न लाओमी ने 24 रन देकर चार विकेट चटकाए। यह कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन थाईलैंड इस टूर्नामेंट में इससे पहले सिर्फ दो बार ही

इस आंकड़े को पार कर पाया था। बल्लेबाजी के लिहाज से थाईलैंड का यह टूर्नामेंट में सबसे खराब दिन रहा। पूरी टीम 16.1 ओवर में महज 59 रन पर ढेर हो गई और आयरलैंड को 62 रनों से जीत मिल गई।

दिल्ली एलिमिनेटर में, चारों सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली इकलौती टीम

वडोदरा, जेएनएन। दिल्ली कैपिटल्स ने डब्ल्यूपीएल में रविवार को यूपी वारियर्स को पांच विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह बनाई। दिल्ली की टीम अब एलिमिनेटर में मंगलवार को गुजरात जाएंट्स से भिड़ेगी। दिल्ली चारों सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली इकलौती टीम बन गई है। इसके साथ ही पिछली बार की चैंपियन मुंबई टूर्नामेंट से बाहर हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (12) और गुजरात जाएंट्स (10) शुरुआती दो स्थान पर रहे। वारियर्स के 123 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने दो जीवनदान का फायदा उठाने वाली लॉरा वोल्वार्ट की 47 रन की पारी और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (29 रन) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 73 रन की साझेदारी से 18.4 ओवर में पांच विकेट पर 126 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 18 गेंद में नाबाद 34 रन की पारी खेलकर दिल्ली की जीत

सुनिश्चित की। मारिजेन कैप (30 रन पर तीन विकेट), श्री चरणी (22 रन पर दो विकेट) और चिनेल हेनरी (25 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी वारियर्स की टीम आठ विकेट पर 122 रन ही बना सकी। वारियर्स की ओर से सलामी बल्लेबाज दीप्ति शर्मा (24), शिखा पांडे (नाबाद 23) और सिमरन शेख (22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं।

टी-20 विश्व कप: स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को मिला भारतीय वीजा

नई दिल्ली, जेएनएन। स्कॉटलैंड की टीम सोमवार को बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी-20 विश्व कप अभ्यास मैच मैच खेल पाएगी, क्योंकि उनके खिलाड़ियों के भारतीय वीजा तेजी से मंजूर कर दिए गए हैं। स्कॉटलैंड को आखिरी समय पर बांग्लादेश की जगह विश्व कप में शामिल किया गया था और उन्होंने 26 जनवरी को अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था। उनके दो खिलाड़ियों सफ्यान शरीफ (पाकिस्तानी मूल) और जैनुल्लाह एहसान (अफगानिस्तान में जन्म) के वीजा थोड़ी देर से आए, लेकिन अब वे भी भारत पहुंच चुके हैं। रविवार को दोनों ने बेंगलुरु में अपने टीम-साथियों के साथ अभ्यास भी किया। क्रिकेट स्कॉटलैंड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी एक वीडियो में यात्रा से पहले शरीफ ने कहा, यह हफ्ता काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव वाला रहा है। जैसे ही हमें पता चला कि हम विश्व कप में जा रहे हैं, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। मेरे लिए यह बहुत रोमांचक है और मैं बस मैदान पर उतरकर स्कॉटलैंड के लिए प्रदर्शन करने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। स्कॉटलैंड टीम और उन सभी लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की। स्कॉटलैंड ने ग्रुप-सी में बांग्लादेश की जगह ली है और वे, वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ मैच खेलेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की टी-20 इतिहास में सबसे बड़ी हार पाक ने 111 रन से रौंदकर 3-0 से जीती सीरीज

लाहौर (पाकिस्तान), जेएनएन। पाकिस्तान ने टी-20 विश्व कप की शुरुआत से पांच दिन पहले रविवार को ऑस्ट्रेलिया को इस प्रारूप में 111 रन की उसकी सबसे बड़ी शिकस्त देते हुए तीन मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी हार 2005 में मिली थी, जब साउथैम्पटन में इंग्लैंड ने उसे 100 रन से हराया था। भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में होने वाले टी-20 विश्व में खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल ऑस्ट्रेलिया की टीम 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज (18 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के सामने 16.5 ओवर में 96 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने छह विकेट पर 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने 37 गेंद में 56 रन बनाए, जबकि बाबर आजम ने 36 गेंद में नाबाद 50 रन की पारी खेली। शादाब खान पांच छक्कों की मदद से 19 गेंद में 46 रन बनाकर पाकिस्तान का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने पहला मैच 19 रन से जीतने के बाद दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से शिकस्त दी थी।

- बाबर आजम ने नाबाद अर्धशतक जड़ा। यह उनका टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 39वां अर्धशतक था। इससे उन्होंने विराट कोहली (38 अर्धशतक) को पीछे छोड़कर टी-20आई में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
- पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 में यह सबसे बड़ा स्कोर भी है।

बेखौफ बदमाशों ने दो जगह वारदात कर फैलाई दहशत

ग्वालियर में रिटा. फौजी को पीटकर बोनट पर लटकाया

रीवा में 3 मिनट में 100 लट्ठ बरसाकर जानलेवा हमला

जागरण, ग्वालियर/रीवा। बदमाशों पर प्रदेश पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। छोटे-छोटे विवाद में बदमाश एकजुट होकर राह चलते लोगों को भी नृशंस तरीके से प्रताड़ित करने से नहीं चूक रहे। ग्वालियर में कार से टक्कर होने पर बदमाश युवकों ने एक रिटायर्ड फौजी के साथ पहले जमकर मारपीट की, फिर उसे गाड़ी के बोनट पर लटकाकर सड़कों पर अपनी रंगदारी जमाते रहे। रिटायर्ड फौजी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं रीवा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक युवक पर दनादन लाठियां बरसा दीं। महज तीन मिनट में 100 लाठियां मारकर बदमाशों ने युवक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। खासबात यह है कि लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन बचाने कोई नहीं आया। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी से मारपीट का मामला डीडी नगर चौराहे का है। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड फौजी कल्याण किशोर कांत शर्मा आदित्यपुरम की गणेश कॉलोनी में रहते हैं। रात करीब 11 बजे अपने बहनोई अवधेश शर्मा के साथ प्रेस्टीज कॉलेज की ओर से घर लौट रहे थे। आदित्याज होटल के पास उनकी कार एक अन्य कार से टकरा गई। टक्कर के बाद कार सवार दो युवक बाहर निकले और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने रिटायर्ड फौजी और उनके बहनोई के साथ मारपीट कर दी। मौके पर भीड़ जमा होने लगी तो आरोपी कार लेकर भागने लगे। इस दौरान उन्हें रोकने के प्रयास में रिटायर्ड फौजी कार के सामने खड़े हो गए। आरोपियों ने कार रोकने के बजाय उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे उछलकर कार के बोनट पर गिर पड़े। आरोपी उन्हें बोनट पर लटकाकर करीब 500 मीटर तक ले गए। फिर झटके से ब्रेक लगाकर किशोर कांत को बोनट से गिराकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने वीडियो के आधार पर बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

रीवा में युवक की बेदम पिटाई, खतरे में जान

जिले के पनवार थाना अंतर्गत शिवपुर क्षेत्र में कबाड़ व्यापारी और उनके भाई 5 बदमाशों ने छोटी सी बात पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पांच बदमाश एक युवक को जमीन पर पटककर लाठी से पीटते दिख रहे हैं। इन युवकों ने महज 3 मिनट में युवक पर 100 से ज्यादा वार किए। बेसुध होने तक बदमाश उस युवक को पीटते रहे। फिर पिस्टल लहराते हुए घायल घायल व्यापारी अतीक और शफीक को छोड़कर भाग गए। दोनों की हालत बेहद नाजुक है। प्रयागराज में हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। झगड़े की इस बार शुरूआत निकलने के लिए जगह को लेकर हुई, लेकिन दोनों के बीच पुरानी रंजिश भी है। दबंगों ने कबाड़ व्यापारियों पर दोबारा हमला किया है। इस मारपीट से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पीड़ित पक्ष ने ग्राम चंपागढ़ थाना पनवार निवासी शिवम सिंह ठाकुर, अजीत सिंह ठाकुर, सौरभ सिंह, सत्यम सिंह और शक्ति सिंह ठाकुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

बेरोजगारी की हद: इंटरव्यू देने किसी ने दीवार फांदी तो कोई छत से कूदकर अंदर घुसा

सतना की सीमेंट फैक्टरी में निकले पद, नौकरी पाने उमड़ी युवाओं की भीड़

जागरण, सतना। इंजीनियरिंग और डिप्लोमा पास युवा एक अदद नौकरी के लिए हद दर्जे तक परेशान हैं। नौकरी के लिए रात-दिन हाथ-पैर पटक रहे युवाओं को नौकरी चाहिए, फिर कैसे भी मिले। ऐसा ही नजारा रविवार को सतना में बना, जब इंटरव्यू देने युवाओं का हुजूम ऐसा उमड़ा की कंपनी का कैंपस ही छोटा पड़ गया। हद तो तब हो गई कि जब अपना बायोडाटा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आए युवा जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकिचाए। इंटरव्यू देने के लिए कोई दीवार फांदकर फैक्टरी के आफिस में घुसा तो कोई छत चढ़कर खिड़कियों से अंदर पहुंच गया। बेरोजगारों की हालत को दिखाने वाला यह नजारा सतना के भरहुत नगर स्थित सीमेंट ग्रुप के कार्यालय में बना। फैक्टरी ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर्स और अन्य पदों पर भर्ती निकाली थी। रविवार को इंटरव्यू रखा गया था। जानकारी मिलते ही कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा जमा हो गए।

बिजनेस प्लस

हरीश दुहन ने संभाली डब्ल्यूसीएल की बागडोर

नागपुर। कोयला खनन में विशेष योग्यता के लिए जाने जाने वाले हरीश दुहन ने रविवार 1 फरवरी को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। वे वर्तमान में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं तथा उन्हें डब्ल्यूसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह अतिरिक्त प्रभार 01 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर प्रारंभिक अवधि तीन माह के लिए अथवा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। श्री दुहन वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नागपुर स्थित मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय में डब्ल्यूसीएल के निदेशक मंडल, सीवीओ तथा मुख्यालय के सभी महाप्रबंधकों एवं विभागाध्यक्षों ने उनका स्वागत किया। इसके उपरान्त उन्होंने मुख्यालय में कोयला उत्पादन, उत्पादकता एवं संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक ली। बैठक में निदेशक (वित्त) बिक्रम घोष, निदेशक तकनीकी (संचालन) आनंदजी प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. हेमंत शरद पांडे, निदेशक तकनीकी (परियोजना एवं योजना) संदीप परांजपे, सीवीओ अजय मधुकर म्हेत्रे, मुख्यालय के महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष गण उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के उपरान्त श्री दुहन ने उमरेड तथा नागपुर क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया एवं भविष्य की योजनाओं के विषय में क्षेत्रीय प्रबंधन से चर्चा की।

टाटा मोटर्स ने 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की

मुंबई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने जनवरी 2026 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल 71,066 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में हुई 48,316 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में 47.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाती है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल (पीवी) सेगमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, जिसमें कंपनी ने 70,222 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 48,076 यूनिट्स था, जिससे 46.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार (पीवी आईबी) में बिक्री 844 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की 240 यूनिट्स की तुलना में 251.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सेगमेंट में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। जनवरी 2026 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल 9,052 ईवी यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 5,240 यूनिट्स थी, जो 72.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इस आंकड़े में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बिक्री भी शामिल है, जो कंपनी की इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों सेगमेंट में बढ़ती मजबूती को दर्शाता है।

पुलिस ने पार्टी और सरकार को डिब्बे में डाल रखा: भाजपा जिलाध्यक्ष

जागरण, शिवपुरी। वाहन चैकिंग के दौरान गर्भवती महिला व परिजनों तथा आरक्षक के बीच मारपीट के बाद हुए विवाद ने जिले की पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। थाने के बाहर चल रहे धरने में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव ने पुलिस अफसरों को आड़े हाथों ले लिया। एसडीओपी और थाना प्रभारी से जाटव ने तल्खी दिखाते हुए कहाकि पुलिस ने भाजपा और उसकी सरकार को डिब्बे में डाल रखा है। आठ दिन से चल रही चालानी कार्रवाई ने यह हाल कर दिया है कि मुझे मुंह छुपाकर निकलना पड़ रहा है। उन्होंने गर्भवती महिला से मारपीट करने वाले आरक्षक और टीआई को तत्काल निलंबित करने की मांग की। असल में शनिवार शाम वाहन चैकिंग के दौरान एक आरक्षक का कुछ लोगों से विवाद हो गया था।

अवैध शराब से भरी पिकअप पकड़ी, दो गिरफ्तार

जागरण, धार। धामनोद क्षेत्र की पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक पिकअप वाहन पर देर रात 1 बजे बड़ी कार्रवाई की। पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-09-डीजे-1332 इंदौर से जुलवानिया की ओर अवैध शराब लेकर जा रहा था। धामनोद थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे पर दबिश देकर वाहन को रोका और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

मध्य प्रदेश राज्य सरकार की 07, 17 और 22 वर्षीय प्रतिभूतियों की नीलामी

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल **₹5,200 करोड़ (अंकित मूल्य)** राशि की प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है।

एकाधिक मूल्य प्रारुप के अंतर्गत प्रतिफल आधारित नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन **(ई-कुबेर)** पर **3 फरवरी 2026 (मंगलवार)** को आयोजित की जाएगी। व्यक्तिगत निवेशक भी **रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in)** के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसर बोली लगा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट **(www.rbi.org.in)** पर **30 जनवरी 2026 (शुक्रवार)** की प्रेस प्रकाशनी देखें।

''पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/कॉल द्वारा धोखा न खाएं''

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.)

Phone:07562-292337 Email: prinwpoly.seh@mp.gov.in

क्रमांक / शामपोमसी/भण्डार/2026/56-57 सीहोर, दिनांक 23/01/2026

// ई-निविदा सूचना //

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर में निम्नलिखित सामग्री हेतु पंजीकृत निविदाकर्ता/एजेन्सियों से ई-निविदा निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है।

Name of Work	EMD	Cost fo Tender form	Start Date of Bid Submmision	Last Date of Bid Submmision	System Tender No.
Supply of Stationery Items	20000/-	2000/-	24.01.2026	17.02.2026	2026_DTE_477839_1
Supply of Books	12000/-	1000/-	24.01.2026	17.02.2026	2026_DTE_477872_1

ऑनलाईन ई-निविदा निर्धारित तिथियों में भरी जा सकती है। उपरोक्त ई-निविदा से संबंधित सम्पूर्ण विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है।

जी- 25141/25

शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं सचिव जिला रोगी कल्याण समिति जयप्रकाश जिला-चिकित्सालय भोपाल, (मध्यप्रदेश)

(1250, तुलसी नगर भोपाल, परिसर, भोपाल)

क्र/ज.प्र.जि.चि./रो.क.स./2026/41 भोपाल दिनांक- 29/01/2026

// चतुर्थ निविदा सूचना //

जयप्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल मे पार्किंग व्यवस्था 2025-26 हेतु एम पी टेण्डर पोर्टल के माध्यम से चतुर्थ ई-निविदा में इच्छुक निविदाकार ऑनलाईन निविदा जमा कर सकते है। निविदा से संबंधित शर्ते, नियम, संशोधित पत्र आदि का ब्यौरा समय समय पर. MP Tender Portal Web Site https://mptenders.gov.in/ पर ऑनलाईन देखा जा सकता हैं। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
01	प्रकाशन तिथि	05-02-2026, 11:30 AM
02	दस्तावेज डाउनलोड/विक्रय प्रारंभ तिथि	06-02-2026, 11:00 AM
03	दस्तावेज डाउनलोड/विक्रय समाप्ति तिथि	25-02-2026, 05:00 PM
04	निविदा (बिड) जमा करने की प्रारंभ तिथि	06-02-2026, 11:00 AM
05	निविदा (बिड) जमा करने की अंतिम तिथि	26-02-2026, 05:00 PM
06	प्री-बिड बैठक की तिथि	12-02-2026, 04:00 PM
07	तकनीकी निविदा (बिड) खोलने की तिथि	27-02-2026, 12:30 PM
08	वित्तीय निविदा (बिड) खोलने की तिथि	समिति द्वारा निर्धारित

जी- 25198/25

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं सचिव जिला रोगी रोगी हलमाण समिति, जयप्रकाश जिला- चिकित्सालय भोपाल (म.प्र.)

न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, नर्मदापुरम् म.प्र.

क्रमांक/री.उ.पं./2026/33 नर्मदापुरम दिनांक 23/01/2026

:: सूचना-पत्र :: अंतर्गत धारा 84

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 84 के अन्तर्गत)

यह कि धारा 84 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरणों में सुनवाई हेतु पूर्व में सूचना पत्र जारी किये गये थे किन्तु बैंक से तामीली अप्राप्त रहने से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निम्न प्रकरणों में सूचना का प्रकाशन कराया जा रहा है-

प्रकरण कमांक	वादी	प्रतिवादी
DR/HBD/84/2023-24/0871	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	रामदयाल
DR/HBD/84/2023-24/0872	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	विष्णु
DR/HBD/84/2023-24/0873	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	पंकज
DR/HBD/84/2023-24/0874	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	जुगराज
DR/HBD/84/2023-24/0875	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	लक्ष्मण सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0876	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	शालकराम सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0877	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	रमेश
DR/HBD/84/2023-24/0878	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	कैलाश
DR/HBD/84/2023-24/0879	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	राम जी
DR/HBD/84/2023-24/0880	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	प्रदीप
DR/HBD/84/2023-24/0881	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	दिनेश कुमार
DR/HBD/84/2023-24/0882	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	जगदीश
DR/HBD/84/2023-24/0883	सेवा सहकारी समिति अन्हाई	गोधन सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0884	सेवा सहकारी समिति पुरेनाकला	जगदीश
DR/HBD/84/2023-24/0885	सेवा सहकारी समिति मर्या पुरेनाकला	चूंणामणि
DR/HBD/84/2023-24/0886	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	जंगजीत
DR/HBD/84/2023-24/0887	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	चूणांमणी
DR/HBD/84/2023-24/0888	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	लखन लाल
DR/HBD/84/2023-24/0889	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	जितेन्द्र
DR/HBD/84/2023-24/0890	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	मेघराज
DR/HBD/84/2023-24/0891	सेवा सहकारी समिति मर्यादित मलकजरा	प्यारेलाल पटैल
DR/HBD/84/2023-24/0892	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	हरिप्रसाद
DR/HBD/84/2023-24/0893	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	कृष्णगोपाल
DR/HBD/84/2023-24/0894	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	देवी सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0895	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	करन सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0896	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	विजय
DR/HBD/84/2023-24/0897	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	मंगल सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0898	सेवा सहकारी समिति मलकजरा	अर्जुन सिंह
DR/HBD/84/2023-24/0899	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या उमरधा	समीन बी
DR/HBD/84/2023-24/0900	कृषक सेवा सहकारी समिति उमरधा	रामप्रसाद

अतः आपको इस सूचना-पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि **दिनांक 16.02.2026 को दोप. 02:00 बजे** 'न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें नर्मदापुरम' में उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करे। आपके नियत दिनांक व स्थान पर अनुपस्थिति में प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही की जावेगी ।

जी-25089/25

उप पंजीयक
सहकारी संस्थायें नर्मदापुरम म.प्र.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग शाजापुर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 25 / 2025-26 शाजापुर, दिनांक 28.01.2026

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र	ठेके की अनु. राशि (रू. लाख में)	रिमार्क
1.	478737	शाजापुर	भवन कार्य	महाविद्यालय मक्सी जिला शाजापुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण, गेट एवं विभिन्न कार्य	प्रथम	185.79	दस्तावेज ऑनलाईन ही मान्य किये जाएंगे
				कुल योग		185.79	

उपरोक्त वेबसाइट आनॅलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 14.02.2026, 17.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

जी- 25102/25

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग भ./स. संभाग
शाजापुर (म.प्र.)

केमिकल से घर में बना रहे थे घी, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण, मंदसौर। नकली घी बनाने के मामले में देर रात मंदसौर पुलिस ने एक घर में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस ने सीतामऊ फाटक स्थित घर में दबिश देकर नकली घी बनाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घर से करीब 150 लीटर नकली घी भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने सोयाबीन तेल बर्तन और एक केमिकल भी जब्त किया है। केमिकल का उपयोग घी में खुशबू लाने के लिए किया जाता था। दोनों आरोपी लंबे समय से मंदसौर में रहकर नकली घी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा करते थे।

घी के सैंपल जांच के लिए भेजे

दोनों आरोपी अहमदाबाद के निवासी हैं और नकली घी बनाना वहीं से सीखकर आए थे। रेवेन्यू पुलिस ओर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फूड सेफ्टी विभाग द्वारा निकली घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वही दोनों आरोपी गोपाल ओर संजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23, 59 अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)

☎:-0755-2761257 E-mail:- eenvda23@gmail.com

पत्र क्रमांक 267/व.ले.लि.-23/2025-26, भोपाल, दिनांक : 29.01.2026

:: निविदा सूचना क्रमांक 12/वाहन/2025-26 ::

प्रथम आमंत्रण

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के अधिकारियों को आऊट सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने का कार्य हेतु ख्याति प्राप्त ट्रेवल एजेंसियों से ऑनलाईन निविदा मध्यप्रदेश शासन ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल की बेवसाईट https//www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन अलग से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु उपरोक्त बेवसाईट का कृपया अवलोकन करें।

स. क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	संख्या	अनुबंध की समयावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1	2	3	4	5
1.	किराये के सेडान टैक्सी वाहन प्रदाय का कार्य।	08	एक वर्ष	रू. 10,000.00 (रू. दस हजार) मात्र
2.	किराये के हैचबैक टैक्सी वाहन प्रदाय का कार्य।	14		

निविदा सूचना में दर्शायी गई वाहनों की संख्या अनुमानित है, आवश्यकता होने पर यह संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकेगी।

1. ठेके की अनुमानित लागत : रू. 96,05,000.00 (रुपए छियान्वें लाख पांच हजार) मात्र
2. धरोहर की राशि : रू. 96,050.00 (रुपए छियान्वे हजार पचास) मात्र
3. निविदा कार्य के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : दिनांक 13.02.20.26 सायं 05.30 तक।
4. धरोहर की राशि अहर्ता संबंधी दस्तावेज खोलने की तिथि : दिनांक 16.02.2026

निविदा प्रपत्र को उपरोक्त बेवसाईट पर केवल ऑनलाईन क्रय किया जा सकता है। ऑनलाईन पर रुपये 10.000.00 (रुपए दस हजार) मात्र भुगतान डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए उपरोक्त बेवसाईट का अवलोकन करें।

जी-25173/25

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23,
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, (वि./यॉ.)
लोक निर्माण विभाग, वि. / यॉ. संभाग क्र. -2, बारह दफ्तर परिसर, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

सूचना प्रकाशन क्रमांक. 33/व.ले.लि./2025-26 भोपाल, दिनांक : 30/01/2026

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	एन.आई.टी. क्र.	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि	धरोहर राशि	निविदा राशि
1	2026_PWDRB_478956_1	61/SAC/2025-26	प्रोवाईडिंग पोल शिफ्टिंग एवं हाईट रेसिंग 11 केव्ही 33 केव्ही एल टी लाईन एण्ड ट्रांसफार्मर ड्यू टू कन्स्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन रोड फनम जावर से कजलास से बिसूखेडी जिला सीहोर	प्रथम आमंत्रण	12705327.00	127053..00	12500.00
योगः-					12705327.00		

नोटः- निविदा विक्रय दिनांक 30/01/2026 प्रात: 10:30 बजे से निविदा विक्रय अंतिम दिनांक 17/02/2026 सायं 5:30 बजे तक एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करना है। निविदा की निर्धारित तिथियों में या अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे उपरोक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।

(इंजी. हिमांशु उपाध्याय)
कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. (वि./यां.) संभाग क्र. 02 भोपाल

जी-25157/25

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, प्लाट नं.-27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.- 02/2026/निविदा/सा/मु.अ.भ./ भोपाल दिनांक 20.01.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है

स.क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रू. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रू.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWPIU_478542_1	जय प्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल को मॉडल अस्पताल में अपग्रेड करने के लिये नवीन ब्लॉक एवं वतमान अस्पताल में कनेक्टिंग कॉरिडोर (जी+2), फायर एग्जिट हेतु सीढ़ी का निर्माण, नाला कवर, टॉप स्लैब, पैनल रूम शिफ्टिंग इत्यादि का निर्माण कार्य।	भोपाल	547.22	547220	20000	18 माह वर्षाकाल सहित
2	2026_PWPIU_477913_1	शासकीय पॅलिटेक्निक महाविद्यालय राजगढ़ में 100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य	राजगढ़	632.31	632310	20000	18 माह वर्षाकाल सहित
3	2026_PWPIU_477938_1	शासकीय पॅलिटेक्निक महाविद्यालय राजगढ़ में 50 सीटर बालिका छात्रावास भवन निर्माण कार्य	राजगढ़	399.13	399130	15000	15 माह वर्षाकाल सहित

1 निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट बेवसाईट http://mptenders.gov.in पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2 निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑन लाईन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑन-लाईन दिनांक 20.01.2026 समय 10.30 से दिनांक 05.02.2026 समय 05.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य 3 जानकारी बेबसाईट पर देखी जा सकती है।
4 निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त बेवसाईट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

जी- 25126/25

मुख्य अभियंता (भवन) लोक
निर्माण विभाग भोपाल

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 23//2026/का.यं. भोपाल, दिनांक 20/01/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रं.	कार्य की अनु. राशि (रू.लाख में)	ई.एम.डी राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWDRB_477628_1	पन्ना	पुल कार्य	पन्ना जिले के गुछछार कल्याणपुर मार्ग के कि.मी. 2 में रूंज नदी के गुछछारघाट पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित	प्रथम	1887.85	केवल ऑन-लाईन
2	2026_PWDRB_477629_1	खण्डवा	पुल कार्य	खण्डवा जिले में मूंदी पुनासा सुलगांव मार्ग के कि.मी. 41/6 में कावेरी नदी पर पहुँच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	प्रथम	1566.47	केवल ऑन-लाईन
3	2026_PWDRB_477630_1	टीकमगढ़	पुल कार्य	टीकमगढ़ जिले में पहाडी बुजुर्ग-खुरमपुर चंदेरा मार्ग में सपरार नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित।	प्रथम	676.89	केवल ऑन-लाईन
4	2026_PWDRB_477632_1	भोपाल	पुल कार्य	भोपाल जिले में भोपाल कोलार डेम के कि.मी. 11/4 में केरवा नदी पर पहुँचमार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य ।	चतुर्थ	501.56	केवल ऑन-लाईन
				कुल योग		4632.77	

उपरोक्त निविदा प्रपत्र ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा । निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 12/02/2026, (17.30) बजे निर्धारित है । विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा

जी-25111/25

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल

7 रेल-कॉरिडोर बड़े व्यापारिक शहरों को जोड़ेंगे

ट्रेनों को तूफानी रफ्तार देने का ऐलान

रविवार को पेश किए गए यूनियन बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए कई अहम और दूरगामी घोषणाएं की। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और आधुनिक यात्री परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। बजट में हाई-स्पीड रेल, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आम यात्रियों के लिए अमृत भारत ट्रेन और रेलवे सुरक्षा प्रणाली 'कवच' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता दी गई। केंद्रीय बजट 2026 में सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का बनाने का एलान किया गया है। इनमें दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरू हाईस्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। ये सात प्राइम रेल कोरिडोर्स होंगी जो सात रेल रूट्स को कनेक्ट करेंगी। इसके सबसे बड़ी बात ये होगी, कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होंगे। जिन पर सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी। जिनकी रफ्तार भी बेहद तेज़ होगी। इससे इन शहरों के बीच रेल सफर की आम समय सीमा घट जाएगी और तेज़ी से सफर कर पाना मुमकिन हो पाएगा। ये रेल मार्ग बेहद व्यस्त मार्ग भी हैं, ऐसे में इन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण से कुछ विशेष ट्रेनों को बिना किसी अवरोध के स्पेशल ट्रैक-रूट पर दौड़ने का मौका मिलेगा। इन कॉरिडोर्स का लक्ष्य न केवल बड़े महानगरों के बीच की दूरी को कम करना है बल्कि इससे देश की विकास को एक नया रफ्तार देना है। 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से भविष्य में देश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।7 नए कॉरिडोर्स का एलान यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर के बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ चुका है। ये 7 नए हाई-स्पीडर रेल कॉरिडोर विकसित भारत के नए भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन कॉरिडोरों के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हालांकि लोगों की उम्मीद थी कि रेल मंत्री बजट में सीनियर सिटीजन को टिकट किराए में मिलनी वाली छूट को दोबारा से लागू करेंगी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया।

कनेक्टिविटी का 'सुपरफास्ट' अवतार

निर्मला सीतारमण के मुताबिक, इन नए रूट्स का मकसद बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करना और इकोनॉमी को बूस्ट देना है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि यूनियन बजट 2026-27 के तहत ये कॉरिडोर रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो, अब घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ ट्रेवल आसान होगा, बल्कि बिजनेस और जॉब्स के नए मौके भी खुलेंगे।

शहर जिनकी चमकेगी किस्मत

बजट में जिन रूट्स का जिक्र किया गया है, उनकी लिस्ट काफी लंबी और इम्प्रेसिव है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु,बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी।

कई शहर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे

चेन्नई-बेंगलुरु कॉरिडोर की मदद से कनेक्शन से लेकर 4000 किलोमीटर का आसान होगा। वाराणसी से सिलीगुड़ी और दिल्ली से वाराणसी के बीच सफर को आसान बनाने के लिए ये दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं हाई स्लीड कॉरिडोर की मदद से उत्तर भारत के कई शहर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। इस रेल कॉरिडोर की मदद से दिल्ली से वाराणसी के बीच का सफर मात्र 3 घंटे 50 मिनट पूरा होगा। जबकि वाराणसी से सिलीगुड़ी की दूरी 2 घंटे 55 मिनट में पूरी होगी।

वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिली राहत

हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी को वित्त मंत्री के कई उम्मीदें थीं। बुजुर्गों को वित्त मंत्री से रेल किराये में मिलने वाली छूट का इंतजार था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी। इसके अलावा कई राज्यों को वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की सौगात का भी इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

केंद्रीय बजट 2026 में भारतीय रेलवे को 2.93 लाख करोड़ कैपेक्स आवंटित किए

केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,93,030 करोड़ आवंटित करने की घोषणा की, जो पिछले वर्ष के 2,78,030 करोड़ की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 2,93,030 करोड़ की मुख्य राशि पूंजी और रेवेन्यू आइटम को कवर करती है। नई लाइन परियोजनाओं को 36,721.55 करोड़ प्राप्त होते हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों में 30,631.50 करोड़ से अधिक है।

रेलवे ट्रेक के लिए फंड 37,750 करोड़ तक बढ़ाया गया है, जबकि पहले यह 29,026 करोड़ था। गेज रूपांतरण 4,600 करोड़ पर सेट है, जो 4,284 करोड़ से थोड़ा अधिक है।

ट्रैक नवीनीकरण आवंटन

22,853 करोड़ पर है, जो 25,166.45 करोड़ से थोड़ा कम है। सिग्नलिंग और टेलीकॉम को 7,500 करोड़ प्राप्त होते हैं, जो 6,500 करोड़ से अधिक है, जबकि विद्युतीकरण परियोजनाओं को 5,000 करोड़ का फंड मिलता है, जो 4,500 करोड़ से अधिक है।

पूंजीगत व्यय का विभाजन

रोलिंग स्टॉक व्यय 52,108.73 करोड़ पर प्रक्षेपित है, जो 50,007.77 करोड़ से अधिक है। पट्टे पर लिए गए संपत्तियों के लिए पूंजी भुगतान 39,650 करोड़ तक बढ़ जाता है, जो 28,157.13 करोड़ से अधिक है।

नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा

टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए उठाए कई कदम

नई दिल्ली, जेएनएन। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले साल किए गए बड़े टैक्स सुधारों के बाद इस बार इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी लोगों को जिस टैक्स सिस्टम के तहत अभी टैक्स देना पड़ रहा है, वही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स की बुनियादी संरचना पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने और टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए केवल मामूली शुल्क देना होगा। गौरतलब हो, रिटर्न फाइल करने की तारीखों को भी अलग-अलग किया गया है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले लोग पहले की तरह 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करेंगे।

इनकम टैक्स में बड़े बदलाव

- **आईटीआर भरने की नई आखिरी तारीख :** जिनकी कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से है और ऑडिट जरूरी नहीं, उनकी आईटीआर की डेडलाइन 31 अगस्त की है। वेतनभोगी लोगों के लिए 31 जुलाई ही रहेगी जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए 31 अक्टूबर यथावत ही रहेगा।
- **आईटीआर में गलती सुधरने का मौका:** रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक दे सकते हैं। इसके बाद फाइल करने पर लेट फीस लगेगी। 5 लाख की इनकम पर 1,000 रुपए। 5 लाख से ज्यादा पर 5,000 रुपए। धारा 148 नोटिस के बाद आईटीआर दे सकते हैं।
- **एमएसीटी मुआवजे के ब्याज पर टैक्स नहीं :** मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर अब टैक्स और टीडीएस दोनों से छूट।
- **एनआरआई से** घर खरीदते समय टीडीएस के लिए टीएएन नंबर जरूरी नहीं।
- **टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेट हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना :** 1 महीने तक देरी पर 75,000 रुपए जुर्माना। 1 महीने से ज्यादा की देरी होने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
- **फ्यूचर्स-ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी :** फ्यूचर्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स- 0.02 फीसदी से बढ़कर 0.05 फीसदी हुई।
- **ईपीएफ जमा लेट होने पर राहत :** अगर नियोक्ता कर्मचारी का पीएफ योगदान आईटीआर की डेडलाइन से पहले जमा कर दे, तो वह आय नहीं माना जाएगा।
- **अनएक्सप्लेंड इनकम पर टैक्स घटा :** पहले 60 फीसदी टैक्स लगता था, अब 30 फीसदी लगेगा।
- **छोटी विदेशी संपत्ति घोषित करने का मौका :** 1 करोड़ रुपए तक विदेशी संपत्ति छुपी हो तो 6 महीने में घोषित करें। इस पर 30 फीसदी टैक्स और 30 फीसदी अतिरिक्त देकर मुकदमे से राहत मिलेगी।
- **पहले टैक्स भर चुके, पर संपत्ति बताना भूल गए तो** 5 करोड़ रुपए तक विदेशी संपत्ति पर सिर्फ 1 लाख रुपए देकर खुलासा कर सकते हैं। इस पर कोई केस नहीं होगा।
- **विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों** के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दी गई है।

भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाकर आधी की अब 60 करोड़ देंगे, मालदीव-म्यांमार का भी फंड कटा

नई दिल्ली, जेएनएन। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद में बड़ी कटौती की है। इस साल बांग्लादेश के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछले साल 120 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव चल रहा है। इसकी वजह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और वहां की विदेश नीति में बदलाव है। बांग्लादेश के अलावा मालदीव को 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन यह पिछले साल से कम है। म्यांमार के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पहले से कम हैं। इस बजट में भारत ने भूटान के लिए 2,288.55 करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल से करीब 138 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। भारत ने बजट में अफ्रीकी देशों के लिए 225 करोड़ रुपए, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 120 करोड़ रुपए और यूरेशियन देशों के लिए 38 करोड़ रुपए रखे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन रीजन के किस देश को कितना पैसा दिया जाएगा। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय का कुल बजट करीब 22,118 करोड़ रुपए रखा है। यह रकम पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। विदेश मंत्रालय के तहत सचिवालय, विदेशों में बने दूतावास और मिशन, पासपोर्ट और इमीग्रेशन से जुड़े कामों पर भी पैसा खर्च होता है।

भारतीय कृषि को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी

नई दिल्ली, जेएनएन। बजट में खेती और गांवों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। उन्होंने बताया कि पशुपालन में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत दूध, पोल्ट्री और अन्य पशु व्यवसायों को मॉडर्न बनाया जाएगा। कोकोनट प्रोत्साहन योजना के जरिए करीब 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों की मदद के लिए एआई आधारित एग्री टूल लाया जाएगा, जिससे वे सही फैसले ले सकेंगे और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी।

ज्यादा कीमत वाली फसलों और डाइवर्सिफिकेशन पर जोर

खेती की पैदावार में डाइवर्सिफिकेशन लाने और इनकम बढ़ाने के लिए, सरकार तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको और काजू, नॉर्थ ईस्ट में अगरवुड, और अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसे नट्स जैसी ज़्यादा कीमत वाली फसलों को सपोर्ट करेगी। खास प्रोग्राम पुराने बागों को फिर से ज़िंदा करने, ज़्यादा डेंसिटी वाली खेती को बढ़ाने और गांव के युवाओं को जोड़कर वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने पर फोकस करेंगे।

कई फसलों को मिलेगा नया सहारा, एआई से मिलेगी मदद

मजबूत होगी तटीय क्षेत्रों की खेती

इस बजट में तटीय क्षेत्रों की खेती को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। नारियल, काजू, कोको और चंदन जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। भारत पहले से ही नारियल उत्पादन में दुनिया में आगे है और इससे करीब 3 करोड़ लोगों, जिनमें 1 करोड़ किसान शामिल हैं, की आजीविका जुड़ी हुई है। सरकार नारियल संवर्धन योजना शुरू करेगी, जिसके तहत पुराने और कम फल देने वाले पेड़ों की जगह नए, बेहतर किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। इससे पैदावार और किसानों की आमदनी दोनों बढ़ेंगी।

काजू और कोको पर रहेगा खास फोकस

काजू और कोको के लिए अलग से विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को कच्चे काजू और कोको के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही इनके प्रोसेसिंग, निर्यात और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि 2030 तक भारतीय काजू और कोको को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम ब्रांड के रूप में पहचान मिल सके।

चंदन से लेकर अखरोट तक खेती को मजबूती

चंदन की खेती को दोबारा बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। इसमें खेती के साथ-साथ कटाई के बाद प्रोसेसिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में अखरोट, बादाम और पाइन नट्स जैसी महंगी और पोषक फसलों को प्रोत्साहन मिलेगा। पुराने बागानों को फिर से विकसित करने और हाई-डेंसिटी खेती को फैलाने के लिए अलग योजनाएं होंगी। युवाओं को इससे जोड़कर वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाएगा, जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा हो सके। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

सिंचाई व्यवस्था होगी और मजबूत

सरकार ने माना है कि बेहतर सिंचाई के बिना महंगी और उन्नत फसलों की खेती संभव नहीं है। इसलिए पहले से चल रही पीएम कृषि सिंचाई योजना के साथ-साथ इस बजट में सिंचाई से जुड़े इंफ्राट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। इससे पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, फसलों की गुणवत्ता सुधरेगी और सूखा या बाढ़ जैसी समस्याओं का असर कम होगा।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं

देश में खुलेंगे 3 नए आयुर्वेद एम्स

इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, जिला स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं छूने की कोशिश

नई दिल्ली, जेएनएन। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बजट 2026-27 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। पहली बार देश का हेल्थकेयर बजट 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यूनियन बजट 2026-27 में हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 1,04,599 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बड़ा है, बल्कि सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें स्वास्थ्य को विकास की बुनियाद माना जा रहा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि देश में मजबूत, समावेशी और आधुनिक हेल्थकेयर सिस्टम तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में इलाज, रिसर्च, मेडिकल टूरिज्म, आयुष और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं हर पहलू को छूने की कोशिश की गई है।

191 प्रतिशत बढ़ा हेल्थ बजट

वित्त वर्ष 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए गए 1,04,599 करोड़ रुपये पिछले साल के मुकाबले बड़ा इजाफा है। 2025-26 में हेल्थ मिनिस्ट्री को 98,311 करोड़ मिले थे। अगर पिछले दस वर्षों पर नजर डालें, तो 2015 में हेल्थ बजट सिर्फ 34,286 करोड़ रुपये था, जो अब लगभग 191 प्रतिशत बढ़ चुका है। यह दिखाता है कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर को धीरे-धीरे मजबूत करने की ठोस रणनीति अपनाई है।

मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

बजट 2026 की एक बड़ी घोषणा है, 5 मेडिकल टूरिज्म हब की स्थापना। ये हब निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाए जाएंगे। जिन प्रमुख संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है, वे हैं अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस। इस पहल से भारत न केवल देशी मरीजों के लिए बल्कि विदेशी मरीजों के लिए भी एक भरोसेमंद मेडिकल डेस्टिनेशन बनेगा।

वरिष्ठ नागरिकों को सभी इलाज एक ही छत के नीचे

आम बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए भी कई घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ आने वाली बीमारियो को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में जेरियाट्रिक केयर सेंटरों को और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी की बुजुर्ग मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी तरह का इलाज मिल सके। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अगले 10 से 15 वर्षों में देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी में तेजी से इजाफा होने वाला है।

आयुर्वेदिक शिक्षा और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने आयुष सेक्टर को भी मजबूती देने का ऐलान किया है। इसके तहत तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा।

आयुर्वेदिक संस्थान की जरूरत : सरकार के इस कदम से आयुर्वेदिक शिक्षा और रिसर्च को और बढ़ावा मिलेगा। नए आयुर्वेद संस्थानों में आयुर्वेद से इलाज के साथ- साथ आधुनिक रिसर्च पर भी फोकस किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली के सरिता विहार में पहले से ही एक (एआईआईए) है, जो देश में आयुर्वेद से इलाज के मामले में सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश में बढ़ती आबादी और इलाज की बढ़ती मांग को देखते हुए नए आयुर्वेद संस्थान की जरूरत है। इनके बनने से आयुर्वेद को देश और विश्व स्तर पर और बेहतर पहचान मिलेगी।

जिला अस्पतालों में 50 प्रतिशत क्षमता बढ़ेगी

बजट में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर बनाकर उनकी क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी।

कैंसर दवाए होंगी सस्ती

कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। अभी 5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।

पिछले सालों में हेल्थ बजट का सफर

बजट 2026-27 साफ संकेत देता है कि भारत अब हेल्थकेयर को खर्च नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देख रहा है. 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हेल्थ बजट, मेडिकल टूरिज्म हब, आयुष को बढ़ावा और जिला अस्पतालों की मजबूती, ये सभी कदम मिलकर भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर हेल्थकेयर सिस्टम की ओर ले जाते हैं।

साल	बजट करोड़ रुपये में
2018-19	52,800 करोड़
2019-20	62,659 करोड़
2020-21	65,012 करोड़
2021-22	73,932 करोड़
2022-23	86,200 करोड़
2023-24	79,221 करोड़
2024-25	90,959 करोड़
2025-26	98,311 करोड़

महिला उद्यमियों और छात्राओं के लिए बजट में ऐलान

महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 'शी मार्ट्स' और हर जिले में होंगे गर्ल्स हॉस्टल

नई दिल्ली, जेएनएन। इस बजट में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। उच्च शिक्षा और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है, खासकर एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी महिलाओं के लिए 'शी मार्ट्स' की शुरुआत की जाएगी। ये समुदाय-स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स होंगे, जो महिला स्व-सहायता समूहों और उद्यमियों को बेहतर बाजार, ब्रांडिंग और स्थायी आय उपलब्ध कराएंगे।

इन मार्ट्स के ज़रिए ग्रामीण महिलाएं कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और छोटे घरेलू व्यवसायों से जुड़े अपने उत्पाद सीधे बाज़ार में बेच सकेंगी। यह पहल 'लखपति दीदी' कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ़ आजीविका तक सीमित न रखकर उद्यमिता और बाज़ार से सीधे जोड़ना है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इसके अलावा करीब 800 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल बनाने का टारगेट है।

एग्री-क्लस्टर्स में स्थापना

'शी मार्ट्स' को कृषि क्लस्टर्स में विकसित किया जाएगा, जहां ये नियमित बाज़ार की तरह संचालित होंगी। महिलाओं को कार्यशील पूंजी, आसान क्रेडिट और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगभग 50 बायर-सेलर मीट्स आयोजित होंगी, जिससे ग्रामीण महिलाएं बड़े खरीदारों और संस्थागत बाज़ारों से जुड़ सकें। योजना के तहत जोखिम कम करने, नकदी प्रवाह बनाए रखने और क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

सरकारी सहयोग और डिजिटल सुविधा

'शी मार्ट्स' योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से लागू किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन लोन सिस्टम की व्यवस्था होगी, जिससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बिना जटिल प्रक्रिया के ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर भी लगाम लगेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर

इस योजना के ज़रिए महिलाओं को उच्च मूल्य वाली फसलें, पशुपालन और कौशल आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। सरकार का अनुमान है कि 'शी मार्ट्स' से लाखों ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनेंगी और ग्रामीण भारत में महिला-नेतृत्व वाली उद्यमिता को नई मजबूती मिलेगी।

नई पीढ़ी के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को मिलेंगे नए मौके

'ऑरेंज इकॉनमी' को बढ़ावा देने से पैदा होंगी रचनात्मक नौकरियां

कौशल विकास

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में रचनात्मक उद्योगों को नई पहचान देते हुए 'ऑरेंज इकॉनमी' को बढ़ावा देने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार रचनात्मक नौकरियां पैदा करना और भारत की सांस्कृतिक-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस बजट में शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं की क्षमता बढ़ाने और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर पर जोर देते हुए बताया कि 2030 तक इस क्षेत्र में करीब 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के सहयोग से देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इससे नई पीढ़ी के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, संस्कृति, मीडिया, मनोरंजन और बौद्धिक संपदा जैसे रचनात्मक क्षेत्र रोजगार, शहरी सेवाओं और पर्यटन के बड़े इंजन बन सकते हैं। हालांकि, इसके विस्तार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और नियामकीय बाधाएं अभी चुनौती बनी हुई हैं।

15,000 सेकेंडरी स्कूलों, 500 कॉलेजों में बनेंगी कंटेंट क्रिएटर लैब्स

1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण

डिजाइन शिक्षा को मजबूती

डिजाइन सेक्टर में कौशल की कमी को देखते हुए पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजाइन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशिक्षित डिजाइनरों की कमी दूर करना जरूरी है।

रोजगार क्षेत्र में बड़े एलान

पांच साल में सरकार जोड़गी एक लाख एएचपी 1.5 लाख केयर गिवर्स को मिलेगा प्रशिक्षण

केंद्रीय बजट 2026 में रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अगले पांच वर्षों में एक लाख एएचपी और 1.5 लाख केयरगिवर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि युवाओं की कौशल क्षमता बढ़े और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

दक्षता आधारित रोजगार पर जोर

सरकार शिक्षा को रोजगार और उद्यम के साथ जोड़ने पर जोर देगी। विकसित भारत का मुख्य चालक सेवा क्षेत्र रहेगा, और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो एआई और नई तकनीकों के प्रभाव का आकलन करेगी। दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा और स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण बढ़ाया जाएगा।

'सशक्त दिव्यांगजन' पर फोकस

बजट 2026 में दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा भी की गई है—- दिव्यांगजन स्किल स्कीम- उद्योग-संबंधित और विशेष प्रशिक्षण के जरिए दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन के अवसर।

दिव्यांग सहारा योजना- (आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) को सहयोग—सहायक उपकरणों के उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास और एआई तकनीकों के समावेश के लिए।

मेडिकल टूरिज्म और हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स का विस्तार

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता होगी। हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स में आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब केंद्र शामिल होंगे, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार बढ़ेगा।

कंटेंट क्रिएटर लैब्स, एनिमेशन जेन जी के लिए भी बहुत कुछ

युवा वर्ग

बजट को 'युवा शक्ति' की सोच और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की इनपुट्स के आधार पर बनाया गया है बजट ने रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और स्टॉर्टअप पर जोर देते हुए पारंपरिक सेक्टरों से हटकर डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, डिजाइन, टूरिज्म और हेल्थकेयर जैसी सेक्टर को नई दिशा दी है। ये सीधे युवा वर्कफोर्स को टारगेट करता है। सरकार का मानना है कि आईडिया बेस्ड इंडस्ट्रीज भविष्य में नौकरियों का बड़ा इंजन बनेंगी। इस बजट में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स में 1.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश, नए डिजाइन संस्थान, खेलो इंडिया मिशन और हेल्थकेयर स्किलिंग जैसे कदम युवा प्रतिभाओं को क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और सर्विस सेक्टर के भविष्य के लीडर्स बनाने का संदेश देते हैं। यह बजट जेन जी को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि देश की नई सोच और सृजन शक्ति का हिस्सा बनने वाला बनाता है।

विदेश में पढ़ाई का खर्च कम : विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है. सरकार ने टीसीएस के तहत खर्च पर इंटरेस्ट रेट को 5 फीसद से घटाकर 2फीसद कर दिया है. यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्याज देना होगा. हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा. साफ शब्दों में कहें, तो विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा.

टूरिज्म और स्पोर्ट्स से नई नौकरियां : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगा, कल्चरल और हेरिटेज साइट्स को मैप करने के लिए डिजिटल नॉलेज ग्रिड आएगा। स्पोर्ट्स में भी बड़ा निवेश है। खेलो इंडिया मिशन से लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टैलेंट डेवलपमेंट के रास्ते तैयार होंगे और कोचिंग सिस्टम मजबूत होगा। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स साइंस, एनालिटिक्स, ट्रेनिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे करियर्स के लिए भी है।

डेटा सेंटर बनाने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक मिलेगा टैक्स हॉलिडे

एआई और आईटी देश का ग्रोथ इंजन

2047 तक टैक्स हॉलिडे विदेशी डेटा सेंटर को

15.5 प्रतिशत का कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन

2,000 करोड़ रुपये सेफ हार्बर की सीमा

बजट 2026 में सरकार नेएआई और आईटी सेक्टर को देश का ग्रोथ का इंजन मानते हुए इन्हें बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर बनाकर दुनिया भर को क्लाउड सेवाएं देंगी, उन्हें साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। सरकार के इस कदम का मकसद भारत को सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया का बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ना माना जा रहा है।

एआई रिवोल्यूशन के लिए डेटा सेंटर जरूरी

मौजूदा दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसकी पैठ हर सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। बैंकिंग से लेकर हेल्थ और एजुकेशन तक, हर जगह एआई आधारित सिस्टम काम कर रहे हैं। लेकिन एआई को चलाने के लिए भारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए और यह काम डेटा सेंटर करते हैं। डेटा सेंटर ही वो जगह हैं जहां बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। यही वजह है कि सरकार ने डेटा सेंटर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हुए इसमें निवेश बढ़ाने पर फोकस किया है।

क्यों खास है भारत का डेटा सेंटर मार्केट

अभी भारत का डेटा सेंटर बाजार करीब 10 अरब डॉलर का माना जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 में इससे करीब 1.2 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। रियल एस्टेट और टेक सेक्टर की रिपोर्ट बताती हैं कि 2027 तक भारत में डेटा सेंटर की क्षमता 1.8 गीगावॉट तक पहुंच सकती है। सरकार और निजी कंपनियों की बड़ी घोषणाएं भी इसी दिशा में इशारा करती हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियां पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत में अरबों डॉलर निवेश करने का ऐलान कर चुकी हैं।

आईटी सेक्टर के लिए आसान बनाए नियम

बजट में आईटी सेक्टर के लिए भी नियम आसान किए गए हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस, आईटी इनेबल्ड सर्विस और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को एक ही कैटेगरी में लाया जाएगा। इनके लिए 15.5 प्रतिशत का कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन तय किया गया है। इसके साथ ही सेफ हार्बर की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी और बार-बार टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इन कदमों से बड़ा विदेशी निवेश आएगा। रियल एस्टेट, कूलिंग सिस्टम और फाइबर नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में भी काम बढ़ेगा। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत की डिजिटल ताकत और मजबूत होगी।

10,000 गाइड्स को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण

15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को वाइब्रेंट डेस्टिनेशन

02 प्रतिशत टीसीएस विदेश यात्रा के पैकेज पर

5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान तीर्थ स्थलों के विकास हेतु

पर्यटन को नया पेशेवर क्षेत्र बनाने की दिशा में कदम

पर्यटन और इको-टूरिज्म

बजट की सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से एक आईआईएमप्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड्स है। देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली बार, गाइड्स के प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को जोड़ा गया है। यह कदम पर्यटन को अनौपचारिक से पेशेवर क्षेत्र में बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय सेवा मिलेगी और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सरकार ने इको-टूरिज्म और नेचर-बेस्ड ट्रैवल पर भी जोर दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अराकू वैली और पश्चिमी घाट में माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुआ नेस्टिंग और बर्ड-वॉचिंग ट्रेल्स प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, 10,000 टूर गाइड्स का अपस्किलिंग और सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की गई है। बजट 2026-27 में पर्यटन केवल एक सेवाक्षेत्र नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को अब वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाएगा। बजट का संदेश यही है कि पर्यटन के जरिए रोजगार और विरासत के साथ विकास हो।

ऐतिहासिक स्थलों का डिजिटल डाटाबेस

बजट में देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे सारनाथ, हस्तिनापुर को वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। उत्तर-पूर्व में बौद्ध सर्किट और हिमाचल-कश्मीर में नई हाइकिंग ट्रेल्स का विकास न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा, अपितु इन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। भारत के सभी ऐतिहासिक स्थलों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को घर बैठे ही उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

पर्यटन के आधुनिक स्वरूप को प्राथमिकता

बजट में पर्यटन के आधुनिक स्वरूप को प्राथमिकता दी गई है। भारत में सीप्लेन के निर्माण और उनके संचालन के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, जिससे तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यटन सुलभ होगा। डार्क स्काई पार्क्स की स्थापना के माध्यम से खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए नए द्वार खुलेंगे। साथ ही, विदेश यात्रा के पैकेजों पर लगने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी के समान है। इससे न केवल विदेश जाना सस्ता होगा, बल्कि देश के भीतर ट्रैवल ऑपरेटर्स का कारोबार भी बढ़ेगा। 5 नए मेडिकल हब्स की स्थापना भारत को ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी, जिससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आने की उम्मीद है।

अधिक सुविधाजनक और किफायती पर्यटन

देसी पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित गाइड्स और डिजिटल जानकारी के कारण अब भारत घूमना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और किफायती होगा। साथ ही, विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा प्रक्रियाओं में सरलीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली सुविधाओं के कारण भारत उनके बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। बजट 2026-27 पर्यटन को केवल घूमने-फिरने तक सीमित नहीं रखता, अपितु इसे एक रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। बजट में भारत को वर्ष 2047 तक एक पर्यटन महाशक्ति बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं। यदि इन योजनाओं का धरातल पर सफल क्रियान्वयन होता है तो पर्यटन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऐतिहासिक योगदान देने के लिए तैयार है।

विदेशी टूर पैकेज से घटा टैक्स

बजट 2026 में अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी शिक्षा और चिकित्सा खर्च पर लगने वाले टैक्स ढांचे में बड़े बदलावों की घोषणा की है. सरकार ने विदेशी टूर पैकेज और विदेश पैसा भेजने पर लगने वाले टीसीएस की दरों को घटाकर यात्रियों और छात्रों के परिवारों को बड़ी राहत दी है. इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर लगने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना और टैक्स नियमों में स्पष्टता लाना है। अब अंतरराष्ट्रीय ट्रिप के लिए पैकेज बुक करने पर मात्र 2फीसद टीसीएस देना होगा, जबकि इससे पहले यह दर 5 फीसद और कुछ मामलों में 20 फीसद तक थी. इसके अलावा, अब टीसीएस लागू होने के लिए किसी न्यूनतम राशि की कोई शर्त नहीं रहेगी. इस फैसले से उन सभी नागरिकों को लाभ होगा जो विदेशी छुट्टियों या अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बुकिंग करते हैं ।

नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आध्यात्मिक पर्यटन की नई धुरी

नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा। ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटक, खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया से आने वाले यात्रियों को आकर्षित किया जा सकेगा। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, होमस्टे और गाइड आधारित रोज़गार को सीधा लाभ मिलेगा। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। धोलावीरा जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।

देशभक्त चायवाले ने लोगों को दिखाई बॉर्डर-2

जागरण, खरगोन। जिले के कसरावद में एक देशभक्त चाय वाले ने अपनी जेब से 50 टिकट बुक कर लोगों को बॉर्डर-2 फिल्म दिखाई। इसके पीछे उनका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था। कसरावद के नए बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाने वाले विजय वर्मा को देशभक्ति फिल्मों से विशेष लगाव है। विजय प्रतिदिन चाय बेचकर लगभग 600-700 रुपए कमाते हैं।

झाबुआ के 200 जैन घरों में प्रभु पार्श्वनाथ विराजित

जागरण, झाबुआ। रविवार को 200 से अधिक जैन परिवारों के मुख्य द्वारों पर प्रभु श्री पार्श्वनाथ जी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। यह आयोजन स्थानीय जैन तीर्थ श्री ऋषभदेव 52 जिनालय और जैन श्वेतांबर श्री संघ झाबुआ के तत्वावधान में पन्यास प्रवर श्री योगरुचि विजय जी महाराज साहेब की निश्रा और आचार्य भगवंत श्री जिनसुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब की प्रेरणा से संपन्न हुआ।

"ट्वीट ऑफ द डे"

आयुष डोसेजा
रणजी खिलाड़ी

मैं विराट कोहली को बचपन से फॉलो करता आ रहा हूं, जब वे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेलने आए थे तो मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने यही कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको दिल्ली से खेलने का मौका मिला है। मैदान में जब भी उतरो तो 200 प्रतिशत देना है, जब दिल्ली के लिए ऐसा करोगे तो एक दिन इंडिया के लिए भी मौका मिलेगा। मैंने उनसे फिटनेस पर भी टिप्स ली, उस पर काम कर रहा हूं।

वाहन मालिकों को 300 किलोमीटर दौड़ लगवा रहा फिटनेस सर्टिफिकेट

» संभाग स्तर पर एक ही सेंटर से बढ़ी परेशानी » नए नियमों के विरोध में बढ़े स्वर

स्वप्निल सकरगायें खरगोन, खण्डवा। केंद्र सरकार के रोड परिवहन मंत्रालय द्वारा कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट की व्यवस्था में किया गया बदलाव कमर्शियल वाहन चालकों को काफी भारी पड़ रहा है। नई व्यवस्था में फिटनेस सर्टिफिकेट केवल आरटीओ स्तर पर जारी किया जाने लगा है। इससे अधिकांश जिलों के वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट पाने 50 से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। आना-जाना मिलाकर हर वाहन मालिक को 300 से 400 किलोमीटर का फेरा लगाने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट मिल पा रहा है। कोई कमी रह जाने या आरटीओ में देरी का खामियाजा वाहन मालिकों को ही भुगतना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 दिसंबर को व्यवस्था में बदलाव करते हुए राज्य के परिवहन विभाग को पत्र जारी किया है। इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर नई व्यवस्था व जमावट की जानकारी दी गई है। नई व्यवस्था में इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और सिंगरौली आरटीओ को अपने संभाग और समीपस्थ जिलों के कमर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। आरटीओ कार्यालय के साथ ही फिटनेस के लिए प्राइवेट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के तौर पर एजेंसी भी तय की गई हैं। केंद्र का आदेश मिलने के बाद राज्य में भी व्यवस्था बदल दी गई हैं। नई व्यवस्था होने से फिटनेस लेना वाहन मालिकों के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। जहां उन्हें लंबी दूरी तय करना पड़ रही है, वहीं खर्चा भी बढ़ गया है। खंडवा जिले के वाहनों के लिए देवास आरटीओ कार्यालय तय किया गया है। खंडवा से देवास करीब 160 किलोमीटर दूर है। इससे फिटनेस सर्टिफिकेट लेने वाहन मालिकों को करीब 300 किमी की यात्रा करना पड़ रही है। ऐसे में कभी दूसरी बार जाने की नौबत आती है तो वाहन मालिकों की परेशानी दोगुनी हो जाती है। इसके चलते अब जिलों में विरोध शुरू हो गया है।

परिवहन सचिव को लिखा पत्र : खंडवा बस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुनील आर्य का कहना है कि गाड़ियों को दूसरे जिले में ले जाना न्याय संगत नहीं है। इससे वाहन मालिको पर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। छोटे ऑटो टेम्पो वाले इसे कैसे वहन करेंगे ,यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन देवास तक का फ्री परमिट उपलब्ध कराएगा । वाहन मालिकों की समस्याओं को देखते हुए हमने सचिव परिवहन विभाग को पत्र के माध्यम से विरोध जताया है। यदि व्यवस्था में बदलाव नहीं होता है तब वरिष्ठों के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। इस व्यवस्था का हर स्तर पर विराेध जताया जाएगा। खंडवा जिले के आरटीओ दीपक मांझी का कहना है कि प्रशासन के निर्देश पर जिले के समस्त कमर्शियल वाहन मालिको को सूचित कर दिया गया है। निर्देश अनुसार बताए गए सेंटर्स से फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। यह केंद्र शासन के आदेश पर बनी व्यवस्था है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है।

यह है विरोध की वजह

इस नई व्यवस्था का विरोध दिनों-दिन हर जिले में तेज हो गया है। क्योंकि जिलों में परिवहन कार्यालय होने के बाद भी वहां फिटनेस सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था नहीं है। वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की मांग है कि हर जिले के परिवहन कार्यालय को फिटनेस देने का अधिकार होना चाहिए। जरूरी व्यवस्था जिला स्तर पर ही जुटाई जाना चाहिए। पूर्वी निमाड़ के खंडवा को देवास और पश्चिमी निमाड़ के खरगौन को देवास और इंदौर आरटीओ जाकर फिटनेस लेना पड़ रही है। देवास आरटीओ में खंडवा और खरगौन के साथ हरदा ,शाजापुर को भी जोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार खंडवा जिले में ही मध्यम और बड़े कमर्शियल वाहन करीब 20 हजार से अधिक हैं। नई व्यवस्था में इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 160 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। करीब 320 किमी का चक्कर लगाने के बाद इन्हें सर्टिफिकेट मिल पाता है।

किसे कहां से मिल रही फिटनेस

- **इंदौर**- धार, खरगोन।
- **भोपाल**- सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, राजगढ़।
- **ग्वालियर** - मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी।
- **उज्जैन**- रतलाम, आगार, मालवा, शाजापुर, धार।
- **जबलपुर**- नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, उमरिया।
- **सतना**- रीवा,सीधी, उमरिया, कटनी, पन्ना, शहडोल।
- **देवास**- शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन।
- **सिंगरोली** - सीधी।

मंदसौर में गिरे ओले, प्रदेश के 15 स्थानों पर तेज बारिश

- आज 14 जिलों में बारिश की चेतावनी
- भोपाल में दिन का तापमान 29 डिग्री तक उछला

नगर संवाददाता, भोपाल। प्रदेश में रविवार को मौसम अचानक बदल गया। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। जबकि दोपहर के समय कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। मंदसौर के मल्हारगढ़ में ओले गिरे। ओले इतनी मात्रा में गिरे कि सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिन का तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। कई जिलों में बारिश, आंधी, घना कोहरा और ओलावृष्टि देखने को मिली। मंदसौर जिले के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ के ग्राम झारड़ा से ओलावृष्टि के दृश्य सामने आए। रविवार शाम करीब आधे घंटे तक तेज बारिश और ओले गिरे, जिससे सड़क किनारे बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई। कई जगह लोग घर के आंगन में फावड़े से ओले समेटते नजर आए। नीमच जिले के पालसोडा और भंवरासा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई, जहां नजारा मिनी कश्मीर जैसा दिखा। ओलों और बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

उत्तर से सटे जिलों में छाया रहा घना कोहरा

प्रदेश के दतिया और खजुराहो में घना कोहरा छाया रहा। यहां दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्वालियर, उज्जैन, धार और मुरैना में रात से सुबह तक बारिश होती रही, जबकि भोपाल में सुबह 9 बजे तक कोहरे का असर रहा। मौसम में बदलाव के बावजूद बड़े शहरों में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। केवल खजुराहो, राजगढ़ और नौगांव में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में गेहूं की फसल आड़ी हो गई, जिससे नुकसान की आशंका है।

14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार दतिया, खजुराहो, ग्वालियर, नौगांव, सतना, रीवा, उज्जैन, श्योपुर, राजगढ़, रतलाम, गुना, दमोह, मंडला, टीकमगढ़ और मलाजखंड में कोहरे का असर ज्यादा रहा। वहीं नीमच, मंदसौर सहित 14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और बादल बने रहने की संभावना है।

बरगी बांध की नहर टूटी, फसलें बर्बाद

जागरण, जबलपुर। जिले के बरगी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 12 बजे बरगी बांध की मुख्य दाईं तट नहर ग्राम सगड़ा-झपनी के पास टूट गई। नहर टूटते ही तेज बहाव के साथ पानी आसपास के खेतों में घुस गया, जिससे किसानों की खड़ी फसलें डूब गईं। देखते ही देखते खेत तालाब में तब्दील हो गए और ग्रामीणों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। ऐहतियात के तौर पर बरगी बांध की दाईं तट नहर से पानी की निकासी पूरी तरह बंद करा दी गई। साथ ही टूटे हिस्से के आगे के सभी नहर गेट खोल दिए ताकि खेतों में भरे पानी की तेजी से निकासी हो सके और नुकसान को और बढ़ने से रोका जा सके। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि नहर की हालत लंबे समय से खराब थी। समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई।

संक्षिप्त खबरें

खुलासा: पॉश इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट

जागरण, जबलपुर। प्रदेश के जबलपुर शहर में पॉश इलाके में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर इसका खुलासा किया है। सेक्स रैकेट में विदेशी महिला (उज्बेकिस्तान) शामिल थी। ग्रीन सिटी इलाके में शिव चौधरी नाम का शख्स पत्नी के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रहा था। पुलिस की छापेमारी की खबर मिलते ही सेक्स रैकेट का सरगना फरार हो गया। आरोपी की पत्नी सुषमा चौधरी और उज्बेकिस्तान की महिला को पुलिस ने आरोपी बनाया है। सेक्स रैकेट में एक दर्जन युवतियों और महिलाओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। महिला थाने में आरोपियों से पूछताछ जारी है। सेक्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है।

अडानी पावर प्लांट में महिला की मौत से हड़कंप

जागरण, सिंगरौली। अडानी पावर प्लांट में हादसे से एक मौत हो गई। ऐश डैम के पास हादसे में एक महिला की मौत से पूरे इलाके के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। दरअसल यह पूरा मामला सिंगरौली के बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट (खैराही) का है। जानकारी के मुताबिक, कंपनी की भारी मशीन की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस हादसे से ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतका की पहचान खैराही निवासी पावित्री पनिका के रूप में हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि गांव वाले ऐश डैम के पक्ष में नहीं थे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बीचों बीच बनाए गए ऐश डैम से पहले ही लोग नाराज थे और अब यह नाराजगी गुस्से में बदलती दिख रही है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है।

भोपाल में 11वीं की छात्रा से कार में दुष्कर्म युवक ने अश्लील वीडियो बनाया, केस दर्ज

ब्लैकमेल कर मांगे एक लाख, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया

जागरण, भोपाल। राजधानी के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में 11वीं की छात्रा के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का मामला सामने आया है। शाहपुरा इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसा कर आरोपी ने कार में रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। कोहेफिजा थाना टीआई कृष्ण गोपाल शुक्ला के अनुसार आरोपी ओसाफ अक्सर छात्रा की सहेली से मिलने स्कूल के आसपास आता था। इसी सहेली के माध्यम से उसकी पहचान पीड़िता से हुई। पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया। वहां कार के अंदर आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया। विरोध करने पर उसने शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया।

अलग-अलग नंबरों से किया परेशान

आरोपी ने पीड़िता से रेप के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। कुछ समय बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा से 1 लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से घबराई छात्रा ने किसी तरह 40 हजार रुपये का इंतजाम कर आरोपी को दिए। पैसे लेने के बाद भी आरोपी की मांग जारी रही और वह बार-बार रेप करने का दबाव बनाता रहा। तंग आकर जब छात्रा ने उसे सोशल मीडिया और फोन पर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी ने अलग-अलग नंबरों से कॉल कर परेशान किया। जब छात्रा नहीं मानी, तो आरोपी ने वह निजी वीडियो छात्रा के दोस्तों को दिखा दिया। इसके बाद छात्रा ने अपने मौसेरे भाई और हिंदू संगठन के लोगों की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

धर्म परिवर्तन और नमाज का दबाव

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शादी के बाद उस पर धर्म बदलने का दबाव डालता था। इतना ही नहीं, दबाव बनाकर उससे कई बार जबरन धार्मिक दुआएं भी पढ़वाई गईं। पुलिस ने आरोपी ओसाफ अली खान को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी।

अनदेखी इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल को केंद्र से मिला था लिफ्ट की मरम्मत का बजट

अस्पताल की लिफ्ट बंद, गर्भवती सीढ़ियां चढ़ने मजबूर

नगर संवाददाता, भोपाल। गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। कमला नेहरू अस्पताल में जहां चिकित्सकों की कमी है, वहीं इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल में लिफ्ट खराब होने के कारण यह कई दिन से बंद है। यहां सिर्फ लिफ्ट बंद नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन पाइप लाइन और मॉडयूलर आपरेशन थियेटर भी बंद हैं। लिफ्ट बंद होने का सबसे ज्यादा असर यहां आने वाली गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं ओपीडी व आईपीडी के लिए इस अस्पताल में आती हैं और इन्हें यहां सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर होना पड़ता है। जबकि प्रसूति रोग विशेषज्ञों का तर्क है कि गर्भवती महिलाओं को सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके गैस राहत अस्पताल में लिफ्ट बंद है।

मेंटेनेंस के बारे में किसी को जानकारी नहीं: इंदिरा गांधी बाल एवं महिला चिकित्सालय में कुछ समय पहले केंद्र से एक निश्चित बजट दिया गया था। इस बजट का इस्तेमाल अस्पताल की लिफ्ट को सुधारने व इसके संचालन पर होना था। इसके अलावा कुछ राशि अन्य कामों के लिए दी गई थी। अब बताया जा रहा है कि राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन लिफ्ट फिर भी खराब है। जब इस बारे में अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया गया तो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के पास कोई जवाब नहीं था।

150 बेड का अस्पताल, मरीज न के बराबर

इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल विशेष तौर पर महिला एवं बच्चों के लिए बनाया गया है। इस अस्पताल की क्षमता 150 बेड की है। कुछ साल पहले करीब एक करोड़ रुपए की लागत से यहां 113 बिस्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था। बताया जाता है कि यह ऑक्सीजन प्लांट भी काम नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार से मिली राशि का यहां दुरुपयोग किया जा रहा है।

सोनोग्राफी मशीन, लेकिन डॉक्टर नहीं: इंदिरा गांधी अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या यहां सोनोलॉजिस्ट का न होना है। अस्पताल में गर्भवती महिलाएं आती हैं, प्रोटोकॉल के तहत हर गर्भवती की पूरे 9 महीने में कम से कम तीन बार सोनोग्राफी जांच कराना अनिवार्य है। लेकिन इस अस्पताल में आने वाली महिलाओं को निजी सेंटर पर सोनोग्राफी कराना पड़ती है। इससे इन महिलाओं पर आर्थिक बोझ पड़ता है।

ऑक्सीजन लाइन भी बंद: अस्पताल में आईसीयू व एचडीयू वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए उनके बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के चलते अस्पताल की मैन ऑक्सीजन लाइन कई दिन से बंद है।

एक करोड़ से बना ओटी बंद: इंदिरा गांधी अस्पताल में करीब एक करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2020-21 में मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर का काम शुरू हुआ था। जो कि वर्ष 2023 में पूरा हुआ। पीडब्ल्यूडी द्वारा जब इस मॉड्यूलर ओटी को अस्पताल अधीक्षक के पास हैंड ओवर किया जा रहा था तो उस समय ओटी की सीलिंग गिर गई थी और सीपेज का पानी भी आपरेशन थियेटर में जमा हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक ने ओटी का हैंड ओवर लेने से मना कर दिया। इस बात को दो साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर शुरू नहीं हो सका।

> इंदिरा गांधी अस्पताल में ढेर कमियां हैं। ताजा मामला लिफ्ट का सामने आया है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
> ■ **रचना ढींगरा,** सामाजिक कार्यकर्ता

मुद्रक एवं प्रकाशक **राजीव मोहन गुप्त** द्वारा जागरण पब्लिकेशन्स प्रा. लि. हेतु 'दैनिक जागरण प्रेस' 33, जागरण भवन, प्रेस काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश -462011 (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। आर.एन.आई. नं. 1573/57, पंजीयन संख्या 7 म.प्र., **संस्थापक : स्व. गुरुदेव गुप्त,** संपादक : **राजीव मोहन गुप्त,** स्थानीय संपादक : **हरिमोहन गुप्त** फोन : **कार्या. :** 0755-6723200 **E-mail :** modemdj@gmail.com।